चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित | 11 अप्रैल–17 अप्रैल 2016 | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

संघ से जुड़े उद्योगपतियों पर पड़ी कोयला घोटाले की पहली क़ानूनी मार

विहिप के झंडाबरदार हैं रूंगटा

विश्व हिंदू परिषद की झारखंड इकाई के अध्यक्ष रहे हैं आरएस रूंगटा

रूंगटा बंधुओं के बड़े भाई नंद किशोर रूंगटा भी थे विहिप के कोषाध्यक्ष

1997 में वाराणसी से अगवा कर नंद किशोर रूंगटा की हत्या कर दी गई थी

प्रभात रंजन दीन

कोयला खान आवंटन घोटाला संप्रग सरकार के कार्यकाल में उजागर हुआ लेकिन उस घोटाले की सबसे पहली सजा भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े उद्योगपतियों को मिली. कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने जिन रूंगटा ब्रदर्स को दोषी करार दिया है, उनके संघ और भाजपा से गहरे रिश्ते हैं. कोयला घोटाले में दोषी करार दिए गए झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (जेआईपीएल) के दो निदेशकों में से एक राम स्वरूप रूंगटा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की आनुषांगिक संस्था विश्व हिंदू परिषद की झारखंड इकाई के अध्यक्ष रहे हैं. उनके एक भाई नंद किशोर रूंगटा भी विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे. 1997 में नंद किशोर रूंगटा का वाराणसी से सनसनीखेज अपहरण हुआ था. उस बहुचर्चित अपहरणकांड में पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी का नाम आया था. मुख्तार की गिरफ्तारी भी हुई थी. सीबीआई ने मामले की छानबीन भी की थी. लेकिन नंद किशोर रूंगटा के अपहरण की गुत्थियां रहस्य ही रह गईं और उनकी हत्या भी कर दी गई. करोड़ों रुपये की फिरौती वसूलने के बावजूद नंद किशोर रूंगटा की हत्या कर दी गई थी. रूंगटा परिवार से विहिप नेता अशोक सिंघल के भी अंतरंग रिश्ते थे. नंद किशोर रूंगटा के मारे जाने के बाद उनके भाई राम स्वरूप रूंगटा विहिप के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष बने. रूंगटा प्रतिष्ठान के भाजपा से रिश्ते यथावत बने रहे और उस औद्योगिक घराने से भाजपा को अच्छी खासी फंडिंग भी होती रही. रूंगटा परिवार से फंडिंग की बात को भाजपा आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन यही तथ्य सत्य है. ओड़ीशा के कंधमाल में 23 अगस्त 2008 को स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती और उनके चार सहयोगियों की हुई हत्या के मामले में चर्च की भूमिका को राम स्वरूप रूंगटा ने ही दस्तावेजों से उजागर किया था. आप जानते ही हैं कि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने झारखंड इस्पात प्राइवेड लिमिटेड (जेआईपीएल) के दो निदेशकों राम स्वरूप रूंगटा और राम चंद्र रूंगटा को कोयला खान आवंटन में हुई अनियमितता के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 120–बी (आपराधिक षडयंत्र) और 420 (धोखाधड़ी) का दोषी करार दिया है. विशेष अदालत का गठन कोयला घोटाले के मामलों की सुनवाई के लिए ही किया गया है. दोषी करार देने के बाद अदालत के आदेश पर रूंगटा भाइयों को हिरासत में ले लिया गया. संप्रग (यूपीए) के दूसरे कार्यकाल में सुर्खियां बने कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले के पहले मामले में 28 मार्च 2016 को अदालत का फैसला आया. दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआई अदालत जिस समय अपना फैसला सुना रही थी उस समय जेआईपीएल के दोनों निदेशक बंधु अदालत में ही मौजूद थे. दोषी करार दिए जाने के तुरंत बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया. इससे पहले वे जमानत पर बाहर थे.

कोयला घोटाले को लेकर चौथी दुनिया ने कई नायाब रहस्योद्घाटन किए हैं. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट से कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला उजागर हुआ था. कैग ने कहा था कि कोल ब्लॉक के आवंटन में एक लाख 86 हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ. औद्योगिक घरानों को कोयले की खानें बिना कोई बोली लगाए दे दी गई थीं. उन कोयला खानों की वाकायदा नीलामी की गई होती तो सरकार को अरबों का घाटा नहीं उठाना पड़ता. एस्सार पावर, हिंडाल्को, टाटा स्टील, टाटा पावर, जिंदल स्टील एंड पावर, जेआईपीएल सहित 25 कंपनियों को विभिन्न राज्यों में कोयले की बड़ी खानें दी गई थीं. कोल ब्लॉक आवंटन की रेबड़ियां बटोरने में छोटी–बड़ी मिला कर करीब सौ कंपनियां शामिल रही हैं. कोयला घोटाले में कुल 20 मुकदमे दर्ज हैं. विशेष सीबीआई जज भरत पाराशर को केवल कोयला घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए ही नियुक्त किया गया है. न्यायाधीश ने जेआईपीएल को भी दोष के दायरे में लिया है. जेआईपीएल के निदेशक राम स्वरूप रूंगटा और रामचंद्र रूंगटा को आइपीसी की धारा 120–बी और 420 के तहत मुजरिम करार दिया गया लेकिन उन पर आइपीसी की धारा 467, 468 और 471 के तहत लगाए गए आरोपों से मुक्त कर दिया गया. इन धाराओं के महेनजर सबूतों का अभाव पाया गया. 132 पेज के अदालती फैसले में कहा गया है कि कंपनी ने कोयला मंत्रालय के समक्ष जमीन व कोयला ब्लॉक की क्षमता के संबंध में जानबूझकर गलत दस्तावेज पेश किए थे. इस आधार पर कोयला मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी ने उसे झारखंड के उत्तरी धांदू में कोयला ब्लॉक आवंटित कर दिया था. गलत तथ्यों के आधार पर ही तत्कालीन कोयला मंत्री ने भी स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों पर अपनी मुहर लगा दी थी. न्यायाधीश ने कहा कि कोयला ब्लॉक पाने के लिए की गई साजिश पूरी तरह

(शेष पृष्ठ 2 पर)

फिर दूसरे फार्मूले से लूटने की तैयारी

यूपीए सरकार के कार्यकाल में कोयला खदानें बिना नीलामी के दे दी गईं. इस तरह रेवड़ी बांट देने से सरकारी खजाने को लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ. अब एनडीए की सरकार कोयला खदानों की बाकायदा नीलामी तो कर रही है, लेकिन पूंजीपति और औद्योगिक घरानों से साठगांठ कर उन्हें उनकी पसंदीदा खदानें दी जा रही हैं. इससे केंद्र सरकार और संबद्ध राज्य सरकारों के खजाने में भी धन जाएगा और नेताओं, नौकरशाहों और दलालों की जेब भी भरेगी. एक तरह से देखें तो कोयले से कमाई का भौंडा (कांडेसी) तरीका अपनाने के बजाय चालू (भाजपाई) जुगाड़ निकाला गया है. लेकिन लूटेरे पूंजीपतियों का घेरा बदला नहीं है. यूपीए के शासनकाल में उन्होंने जिस तरह कोयले से खरबों रुपये कमाए, अब उसी तरह एनडीए सरकार को भी घेरे में लेकर अरबों रुपये कमाने की पेशबंदियां हो रही हैं. आपको मालूम ही है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सारे आवंटन रद्द कर दिए जाने के बाद अब दोबारा उन कोयला खदानों की नीलामी शुरू हो गई है. कोयला खदानों के आवंटन से लाखों करोड़ रुपये मिलने की बात सही है. कई खदानों की नीलामी सफलतापूर्वक हो भी चुकी है. सरकारी खजानों को खासा धन मिल भी रहा है. लेकिन कमाई के जुगाड़ भी काम कर रहे हैं. कई खदानों की नीलामी में ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिसमें कंपनियों और अधिकारियों की मिलीभगत से कोयला खदानों का आवंटन किया गया है. 90 हजार करोड़ के कर्ज में डूबे जेपी समूह और इन्वेस्टर्स समिट में 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश करने की घोषणा के बावजूद निवेश नहीं करने वाले रिलायंस समूह का नायाब उदाहरण सामने है जो मध्यप्रदेश की धरती पर अब आधिकारिक रूप से कोयला खोदेंगे. इन दोनों पूंजीपति घरानों और कुछ अन्य विवादी कारोबारियों को मध्य प्रदेश के कोल ब्लॉक मिल गए हैं. रिलायंस ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेएल) और ओसीएल आयरन एंड स्टील को पटखनी देकर कोल ब्लॉक हासिल किया है. रिलायंस को जो कोल ब्लॉक मिला है उसमें 2.93 करोड़ टन का भंडार है. जेपी सीमेंट कॉरपोरेशन को भी मध्य प्रदेश में अमलिया नॉर्थ और मंडला साउथ की कोयला खदानें मिली हैं. इसी तरह देशभर की 214 कोयला खदानों की 30 वर्ष के लिए ई–नीलामी हो रही है. अभी ही जिस तरह की अनियमितताएं और विसंगतियां सामने आ रही हैं उससे लगता है कि कोल ब्लॉक आवंटन पर फिर से कानूनी आफत गिरेगी. मौजूदा सत्ता गलियारे के अधिकारी बताते हैं कि कोयला मंत्रालय के अधिकारियों से साठगांठ कर कारोबारी घरानों ने अपनी पसंद के कोल ब्लॉक आपस में बांट लिए हैं. नीलामी प्रक्रिया में भी जुगाड़ सेट कर लिए गए हैं. सामंजस्य और सुविधा से कोल ब्लॉक की नीलामी की बोलियां लग रही हैं.

केंद्र सरकार का कहना है कि नीलामी से आने वाले राजस्व का फायदा या तो राज्यों को मिलेगा या फिर सस्ती बिजली की दर के रूप में भारत की जनता को मिलेगा. 31 मई 2016 तक देश के 83 कोल ब्लॉकों के आवंटन का कोयला मंत्रालय का लक्ष्य है. इनमें से 40 ब्लॉकों की नीलामी होगी और 43 ब्लॉकों का आवंटन होगा. 83 ब्लॉकों में से 56 ब्लॉक ऊर्जा सेक्टर के लिए रखे गए हैं, जबकि शेष ब्लॉक लोहा–इस्पात और सीमेंट जैसे उद्योगों के लिए मिलेंगे. कोयला खदानों के लिए जेपी, रिलायंस के अलावा भाजपा से जुड़ा अडानी समूह, एस्सार, जीएमआर, वेदांत, जिंदल, आदित्य बिड़ला ग्रुप समेत कई ऐसी कंपनियां लगी हुई हैं जो कांग्रेस के शासनकाल में भी कोयला लूट चुकी हैं. सूत्र बताते हैं कि भाजपा के शासनकाल में नीलामी के जरिए कोल ब्लॉक आवंटित तो हो रहे हैं, लेकिन उसमें नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) की आपत्तियों को नजरअंदाज किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ में जिन कोल ब्लॉकों पर एनजीटी ने आपत्ति दर्ज कर रखी है, उनकी नीलामी के लिए 10 फीसदी रकम जमा कराई जा चुकी है. कोल ब्लॉकों के आवंटन में अब राज्य सरकारों की कोई भूमिका नहीं रह गई है. पहले कोल ब्लॉक देने की सिफारिश राज्य सरकारों की तरफ से आती थी. अब हर राज्य को उसकी जरूरत के मुताबिक ही कोयला मिलेगा. कोल रॉयल्टी मिलने से कोयला उत्पादक राज्यों को फायदा मिलने का रास्ता मोदी सरकार साफ कर चुकी है. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रद्द किए गए कोल ब्लॉकों की खुली ई–नीलामी करने के फैसले के बारे में सरकार पहले ही कह चुकी है कि जो भी राशि प्राप्त होगी, वह पूरी तरह से राज्यों को जाएगी. ■

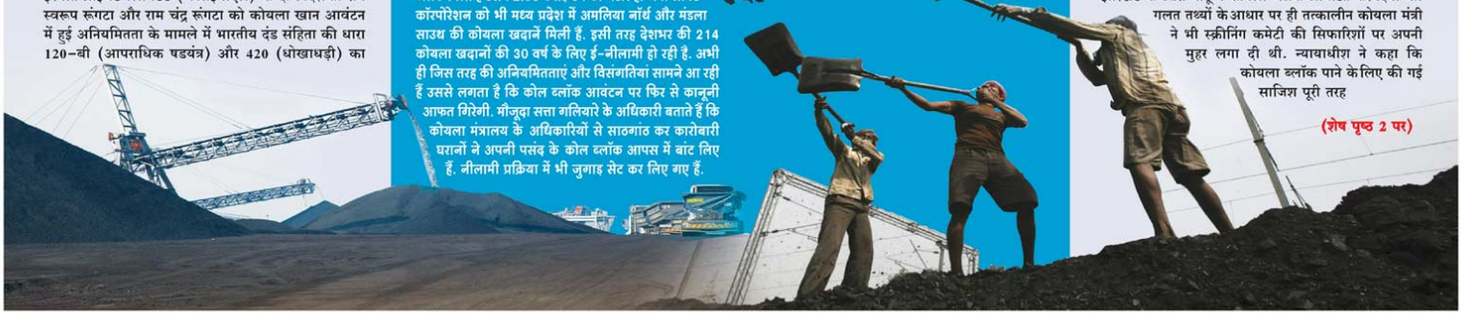

विहिप के झंडाबरदार हैं रूंगटा

पृष्ठ 1 का शेष

से स्पष्ट है, लिहाजा दोषियों की भूमिका को लेकर उनके मन में कोई दो राय नहीं है. कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में जेआईपीएल अचानक तब सुर्खियों में आ गई थी जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी आरोपी बनाने के लिए कंपनी की ओर से अदालत में याचिका दाखिल की गई. हालांकि वह याचिका अदालत से खारिज हो गई, लेकिन उसने कोयला घोटाले के कई और आयाम उजागर किए. जेआईपीएल को जिस समय कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ था उस समय मनमोहन सिंह के पास ही कोयला मंत्रालय था. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा तत्कालीन कोयला राज्यमंत्री दासारी नारायण राव को भी अदालत में हाजिर कराने और उनका बयान लेने का अदालत से आग्रह किया गया था. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आरोपी बनाने की मांग की थी. उस समय के कोयला राज्यमंत्री दासारी नारायण राव यह कह चुके थे कि मनमोहन सिंह को आरोपी बनाने की मांग उचित है. राव का कहना था कि कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर सभी निर्णय मनमोहन सिंह की अंतिम स्वीकृति के बाद ही लिए गए, लिहाजा उन्हें मामले में आरोपी बनाया जाना चाहिए. केंद्र सरकार के पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता ने भी अदालत के समक्ष यह बयान दिया था कि मनमोहन सिंह द्वारा अंतिम निर्णय लेने के बाद ही कोल ब्लॉक आवंटित किया जाता था. नियम–कानून को ताक पर रखकर झारखंड में कोलकाता की विनी आयरन व स्टील उद्योग लिमिटेड को राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक आवंटित करने के मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता भी

वो कौन थे जिनकी फाइलें गायब हो गईं!

कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ी 147 फाइलों के गायब होने का मसला सीबीआई की छानबीन में भी सुलझ नहीं पाया है. सवाल है कि वो कौन प्रभावशाली लोग हैं जिनसे जुड़ी फाइलें गायब कर दी गईं! लोग यह कयास ही लगाते रह गए कि उन फाइलों से कांग्रेस के प्रभावशाली नेता या कांग्रेस से जुड़े प्रभावशाली उद्योगपति घराने का ताल्लुक होगा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया. गायब फाइलों में से 45 फाइलें उन कंपनियों की हैं जिन्होंने कोयला खदान पाने के लिए 1993 से 2005 के बीच आवेदन किया था. इनमें कांग्रेस सांसद विजय दरडा की कंपनी की कुछ फाइलें भी शामिल हैं. ■

कांग्रेस और राजद के नेताओं ने भी खूब लूटा

जे आर पावर जेन प्राइवेट लिमिटेड ने ओड़ीशा में कोल ब्लॉक का आवंटन हासिल किया था. यह कंपनी यूपीए सरकार में सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री रहे एस जगतरक्षकन की है. इस कंपनी ने पुडुचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट (पीआईपीडीआईसी) के साथ साझेदारी का करार किया और पांच ही दिन बाद पीआईपीडीआईसी को भी कोल ब्लॉक आवंटित हो गया. कोल ब्लॉक उसी कंपनी को मिलना चाहिए था जिसे तापीय विद्युत (थर्मल पावर), लोहा एवं इस्पात या सीमेंट उद्योग में विशेषज्ञता हो, लेकिन केंद्रीय मंत्री की इस कंपनी को ऐसा कुछ भी हासिल नहीं था. मंत्री की इस कंपनी ने वर्ष 2010 में केएसके इनर्जी वेंचर्स को अपने 51 प्रतिशत शेयर बेच डाले. इस तरह धूर्तता करके जेआर पावर को मिला कोल ब्लॉक केएसके पावर को मिल गया. इसी तरह यूपीए सरकार में मंत्री रहे सुबोधकांत सहाय ने अपनी कंपनी एसकेएस इस्पात एंड पावर को कोल ब्लॉक देने के लिए पांच फरवरी 2008 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखा था. अगले ही दिन पीएमओ से एक पत्र कोयला सचिव को चला गया जिसमें सूचित किया गया कि एसकेएस इस्पात को कोल ब्लॉक आवंटित कर दिया गया है. सुबोधकांत सहाय के भाई सुधीर सहाय कंपनी के कार्यकारी निदेशक हैं. वर्ष 2012 में अंतर–मंत्रिपरिषदीय समूह (आईएमजी) की अध्यक्ष जोहरा चटर्जी ने एसकेएस इस्पात को दिए गए कोल ब्लॉक को रद्द करने की सिफारिश की थी. इसी तरह कांग्रेस सांसद विजय दरडा और महाराष्ट्र सरकार में शिक्षा मंत्री रहे उनके भाई राजेंद्र दरडा ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपनी तीन कंपनियों जेएलडी यवतमाल इनर्जी, जेएएस इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड पावर लिमिटेड और एएमआर आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड के लिए अवैध तरीके से कोल ब्लॉक का आवंटन करा लिया था. राज्यसभा सांसद विजय दरडा और उनके भाई व महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा मंत्री राजेंद्र दरडा पर 25,000 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है. दरडा परिवार को कई कंपनियों के जरिए कोयले की कुल नौ खदानें आवंटित की गई थीं. ये वो कंपनियां हैं, जिनमें दरडा परिवार और जायसवाल समूह की भागीदारी थी. जायसवाल समूह के मालिक पूर्व केंद्रीय कोयला मंत्री

सुबोधकांत सहाय

प्रेमचंद गुप्ता

एस जगतरक्षकन

विजय दरडा

नवीन जिंदल

श्रीप्रकाश जायसवाल के रिश्तेदार हैं. आवंटन की प्रक्रिया में जालसाजी की गई और फर्जी कंपनियों का सहारा लिया गया. दरडा और जायसवाल जेएलडी यवतमाल एनर्जी, जेएएस इंफ्रास्ट्रक्चर, अभिजीत इंफ्रास्ट्रक्चर, जायसवाल नेको लिमिटेड जैसी कई कंपनियों में भागीदार हैं. विजय दरडा उनके भाई राजेंद्र दरडा और बेटे देवेंद्र विजय दरडा जायसवाल–अभिजीत–दादरा समूह की कई कंपनियों के निदेशक और शेयरधारक भी हैं, लेकिन कोयला घोटाले के सामने आते ही दरडा ने इन कंपनियों से अपनी भागीदारी खत्म कर ली. जेएलडी कंपनी में ही अकेले दरडा और जायसवाल के पास कुल 60 फीसदी शेयर थे. कंपनी को छत्तीसगढ़ और फतेहपुर (पूर्व) की कोयला खदानें आवंटित की गई थीं, जिसमें करीब 10,000 करोड़ कीमत का कोयला भंडार था. राष्ट्रीय जनता दल के नेता और यूपीए सरकार में मंत्री रहे प्रेमचंद गुप्ता के बेटों मयूर गुप्ता और गौरव गुप्ता की कंपनी आईएसटी स्टील एंड पावर और सीमेंट कंपनी गुजरात अम्बुजा को महाराष्ट्र के दहीगांव और मकरधोकरा में कोल ब्लॉक दे दिए गए थे. गुजरात अम्बुजा और लाफार्ज कंपनियों ने आवंटित क्षेत्र से कहीं अधिक विस्तृत क्षेत्र पर कब्जा जमा रखा है और कोयले का अंधाधुंध अवैध खनन हो रहा है. कांग्रेस के पूर्व सांसद नवीन जिंदल की कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की सत्ता शक्ति इतनी थी कि उसने 15 सौ मिलियन मीट्रिक टन कोयला के खनन का अधिकार हासिल किया, जबकि वह अधिकार सरकारी उपक्रम कोल इंडिया लिमिटेड को नहीं मिल पाया. जिंदल की कंपनी को तालचेर कोल फील्ड के अंगुल क्षेत्र में कोयला खनन का अधिकार मिला था. इसके अलावा झारखंड के अमरकोंडा मुर्गदंगल में जिंदल स्टील को अवैध तरीके से मिले कोल ब्लॉक की छानबीन निर्णायक दौर में है. ■

आरोपी हैं. अदालत के समक्ष यह तथ्य भी रखा गया था कि कोयला सचिव एचसी गुप्ता स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे और सिर्फ उन्हीं आवंटनों को स्वीकृत करते थे जिन्हें कोयला मंत्री द्वारा बाकायदा स्वीकृत किया जाता था. गुप्ता सिर्फ आवेदकों की फाइलें कोयला मंत्री तक पहुंचाते थे. कोयला मंत्री ही अंतिम निर्णय लेते थे कि कौल ब्लॉक किन कंपनियों को आवंटित किया जाएगा. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आरोपी बनाने के मसले पर जिंदल स्टील के मालिक कांग्रेस नेता नवीन जिंदल ने अदालत के समक्ष कहा था कि मनमोहन सिंह को आरोपी बनाने के मसले पर न वह पक्ष में हैं और न विरोध में. जिंदल स्टील और नवीन जिंदल भी कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में आरोपी हैं. झारखंड के अमरकोंडा मुर्गदंगल में नवीन जिंदल की कंपनी जिंदल स्टील को अवैध तरीके से कोल ब्लॉक देने का मामला चल रहा है.

कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला 2012 में संप्रग के दूसरे कार्यकाल में उजागर जरूर हुआ, लेकिन यह घोटाला संप्रग के पूरे 10 वर्ष के शासनकाल और उसके पहले के पांच वर्ष के भाजपा शासनकाल में किया गया. कोयला घोटाले पर भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर रही, लेकिन असलियत यही है कि इस घोटाला प्रतियोगिता में कांग्रेस ने 10 साल का फायदा उठाया तो भाजपा ने तकरीबन पांच साल का. कोयला घोटाले का कार्यकाल व्यापक तौर पर वर्ष 1999 से लेकर वर्ष 2014 के बीच का माना जा सकता है. इस दरम्यान नवीन पटनायक (1998 से 2000), सुंदर लाल पटवा (2000 से 2001), सैयद शाहनवाज हुसैन (फरवरी 2001 से सितम्बर 2001), राम विलास पासवान (2001 से 2002), ममता बनर्जी (जनवरी 2004 से मई 2004), शीबू सोरेन (2004 से 2007), मनमोहन सिंह (2004 में चार महीने और 2007 से 2012), श्रीप्रकाश जायसवाल (2012 से 2014) देश के खान एवं कोयला मंत्री रहे. 2003 में खनन मंत्रालय और कोयला मंत्रालय को अलग–अलग कर दिया गया था. कोयला घोटाले में आधिकारिक तौर पर जिन भाजपाइयों ने फायदा उठाया उसमें एसएमएस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अजय संचेती का नाम भी अव्वल है. भाजपा के कद्दावर नेता और मौजूदा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के करीबी अजय संचेती भाजपा के राज्यसभा सदस्य हैं और उन्होंने अपने प्रभाव से छत्तीसगढ़ के कोल ब्लॉक हथियाए थे. एसएमएस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अकेले ही देश को हजार करोड़ का नुकसान पहुंचाया. रूंगटा भाइयों की झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड का स्थान उसके बाद ही आता है. हालांकि रूंगटा ब्रदर्स को कोल ब्लॉक का आवंटन वर्ष 2005 में हुआ था, तब मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार केंद्र में आ गई थी.

रूंगटा बंधुओं के आर्थिक विकास की कहानी उनके राजनीतिक विकास से जुड़ी हुई है. विहिप के कोषाध्यक्ष रहे नंद किशोर रूंगटा की हत्या की जांच करने वाली टीम के सदस्य रहे एक सीबीआई अधिकारी ने बताया कि नंद किशोर रूंगटा के अपहरण में आर्थिक और राजनीतिक दोनों वजहें शामिल थीं. अयोध्या आंदोलन में सक्रिय भूमिका अदा करने वाले अशोक सिंघल के अंतरंग नंद किशोर रूंगटा कई लोगों की आंखों में खटक रहे थे और कुछ माफिया तत्व उन्हें रास्ते से हटा कर बदला भी लेना चाहते थे. यही वजह है कि नंद किशोर रूंगटा के अपहरण में करोड़ों रुपये की फिरौती भी वसूली गई और उनकी हत्या भी कर दी गई. नंद किशोर रूंगटा अपहरण मामले में माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के शूटर अताउर रहमान उर्फ बाबू की आजतक गिरफ्तारी नहीं हो पाई. जबकि सीबीआई ने उसकी गिरफ्तारी में दुनियाभर में कथित तौर पर जाल बिछाया और रेड कॉर्नर नोटिस तक जारी की. विडंबना यह है कि फरारी के दरम्यान ही उसने भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की भी हत्या कर दी.

बहरहाल, तत्कालीन बिहार के रामगढ़ (अब झारखंड में) के कोयलांचल में रूंगटा बंधुओं की आर्थिक विकास यात्रा 80 के दशक में शुरू हुई थी. उसके पहले उनका कोयले का छोटा व्यापार था और वे एक–दो ट्रक कोयला ही बनारस भेजा करते थे. (शेष पृष्ठ 3 पर)

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 08 अंक 06
11 अप्रैल–17 अप्रैल 2016

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060, +91–8451050786, +91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

विहिप के झंडाबरदार हैं रूंगटा

पृष्ठ 2 का शेष

फर्जी दस्तावेजों पर पूर्व सैनिकों के नाम पर कोयला उठान का धंधा करके रूंगटा बंधुओं ने भारी कमाई की. एक समय ऐसा भी आया कि उत्तर प्रदेश आने वाले कोयले का 90 प्रतिशत डीओ रूंगटा बंधुओं के नाम हुआ करता था. बाद में इनकी कई स्पंज आयरन फैक्ट्रियां लगीं. इनकी प्रमुख कंपनियों में झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, आलोक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, मां छिनमस्तिका सीमेंट एंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, श्रीदुर्गा सीमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, वीएफपीएलजेबी कंपनी ओड़ीशा, एमआर रेलकॉन प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव, खेलारी सीमेंट, रूंगटा सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, अनन्दिता सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, अजंता ट्रांसपोर्ट जैसी कई कंपनियां शामिल हैं, जो प्रमुख रूप से झारखंड, ओड़ीशा, छत्तीसगढ़, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हैं. रूंगटा बंधुओं को झारखंड के उत्तरी धांदू में 32 एकड़ क्षेत्र में ही कोयला खनन की अनुमति मिली थी, लेकिन वे 79 एकड़ के बड़े क्षेत्र में कोयला खोद रहे थे. इसके लिए दस्तावेजों में भी फर्जीवाड़ा किया गया था. कोलेश्वर महतो और ललित कुमार दास के नाम से बने दो सेल-डीड भी फर्जी पाए गए थे.

वाराणसी के मुगलसराय स्थित चंदासी अवैध कोयला बाजार का गढ़ है. रूंगटा बंधुओं के कोयला व्यापार का चंदासी बड़ा केंद्र रहा है. इस बाजार में कोयले की कीमत मनमर्जी से तय होती है. कोयले के धंधे से जुड़े लोग कहते हैं कि झरिया या अन्य प्रमुख खदानों से रोजाना करीब डेढ़ हजार ट्रक कोयला चंदासी की कोयला मंडी में पहुंचता है. चंदासी कोयला मंडी का अपना अलग अर्थशास्त्र है जो रूंगटा बंधु जैसे व्यापारी या माफिया तय करते हैं. कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी द्वारा नंद किशोर रूंगटा का अपहरण किए जाने के पीछे यह अर्थशास्त्र ही मुख्य वजह थी. अब तो हालात यह हैं कि देश के विभिन्न बाजार और कल-कारखानों में चंदासी जैसी अवैध कोयला मंडियों के जरिए ही कोयला पहुंचता है. देशभर के व्यापारी अपने मुंशियों और बिचौलियों के माध्यम से चंदासी मंडी से कोयला खरीदना तय करते हैं. सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि कोल ब्लॉक के अवैध आवंटन से ही सरकारी खजाने को एक लाख 86 हजार करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा लेकिन कोयला बाजार के विशेषज्ञ बताते हैं कि कोयले के अवैध खनन और अवैध विक्रय से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान रोजाना पहुंचाया जा रहा है. इसमें रूंगटा बंधुओं जैसे लोगों की भरमार है. इसमें उद्योगपति, नेता, नौकरशाह, दलाल और माफिया सब शामिल हैं. कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में फायदा उठाने वालों में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, कांग्रेस नेता विजय दरडा और राजेंद्र दरडा, कॉरपोरेट मामलों के पूर्व मंत्री और राजद नेता प्रेमचंद गुप्ता, पूर्व कांग्रेस सांसद और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के चेयरमैन नवीन जिंदल जैसे तमाम लोग शामिल हैं. घोटाले का फायदा उठाने वाले औद्योगिक घरानों में टाटा समूह, इलेक्ट्रो स्टील, अनिल अग्रवाल समूह, भूषण पावर एंड स्टील, जायसवाल नेको, अभिजीत समूह, आदित्य बिड़ला समूह, एस्सार समूह, अदानी समूह, आर्सेलर मित्तल, लैंको समूह वगैरह शामिल हैं. इन औद्योगिक घरानों के राजनीतिक जुड़ाव कांग्रेस, भाजपा और राजद जैसे राजनीतिक दलों से रहे हैं.

सुप्रीमकोर्ट के आदेश से 1993 के बाद से आवंटित सभी कोयला खदानें गैरकानूनी साबित हो गई हैं. यानी, 1993 से लेकर 2014 तक सत्ता पर जो भी सरकारें काबिज रहीं, वे सब कोयला खदानों के आवंटन के गोरखधंधों में कमोबेश लिप्त रहीं. चाहे वह पीवी नरसिम्हा राव रहे हों या एचडी देवेगौड़ा या इंद्र कुमार गुजराल या अटल बिहारी वाजपेयी. इन सरकारों ने भी अवैध तरीके से कोयला खदानें आवंटित कीं. आर्थिक विशेषज्ञ बताते हैं कि अकेले कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले से जो नुकसान हुआ वह देश के प्रति व्यक्ति के सिर पर नौ हजार रुपये का घाटा थोप गया. 2004 से 2012 के बीच सौ से अधिक कंपनियों ने खदान आवंटन घोटाले का फायदा उठाया. घोटाले से हुए नुकसान की राशि भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 12 प्रतिशत से भी अधिक है. इस घोटाले से 33 अरब टन कोयला गायब हो गया जिससे 50 साल तक देश के लिए बिजली पैदा होती. कोल ब्लॉक घोटाले से निजी क्षेत्र के उपक्रमों ने करीब 4.79 लाख करोड़ का लाभ कमाया तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 5.88 लाख करोड़ का लाभ कमाया और बहती गंगा में हाथ धोया. राजनीतिक-आर्थिक मसलों के तापमान का एहसास रखने वाले विशेषज्ञों का स्पष्ट कहना है कि सार्वजनिक तौर पर सत्ता पक्ष या विपक्ष कोयला घोटाले के नाम पर फिर से आरोप-प्रत्यारोप का खेल खलेंगे और चुनाव में भुनाएंगे, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इस मसले को संसद में बहस के लिए नहीं ले जाएंगी. क्योंकि कोयला घोटाले से कांग्रेस की शर्ट पूरी मैली है तो भाजपा की शर्ट भी सफेदी की झनकार वाली नहीं है. कोयला खदानों के आवंटन में करीब 1.86 लाख करोड़ रुपये और टू-जी स्पेक्ट्रम आवंटन में 1.76 लाख करोड़ रुपये गटक लिए गए. इसमें से ज्यादा रकम पूंजीपतियों के पास गई और उसके बाद नेताओं नौकरशाहों और दलालों ने खा लिए. घोटालों का यही राम नाम सत्य है. आम लोगों के बीच यह सवाल आम बातचीत के बीच उछलता रहता है कि कोयला या किसी अन्य घोटाले की राशि सरकार बचा ही लेती तो इससे आम आदमी को क्या मिल जाता? क्या वह पैसा आम आदमी की जिंदगी सुधारने पर खर्च होता? क्या वह इसे मजदूरों पर या किसानों को आत्महत्या की स्थिति आने से रोकने पर खर्च करती? क्या इस धन से वह सरकारी स्कूल और अस्पताल खोलती? क्या इससे वह सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बेहतर बनाती? इन सवालों का जवाब नकारात्मक शब्दों से ही सुनाई पड़ता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड स्थित आरएस रूंगटा का बंगला

खदानों को निजी हाथों में सौंपने का कांग्रेसी-भाजपाई कुचक्र

70 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कोयला खनन को पूंजीपतियों से छीन कर सरकार के हाथ में दे दिया था. उस समय सीएनएन अधिनियम लागू किया गया था. 1972 में कोकिंग कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया. फिर 1973 में गैर कोकिंग कोयला खदानों का भी राष्ट्रीयकरण हुआ. कोयला खदान राष्ट्रीयकरण अधिनियम (सीएमएन) 1976 में लागू हुआ. इस अधिनियम के तहत लोहा और इस्पात का उत्पादन करने वाले पूंजीपतियों को छोड़कर अन्य सभी पूंजीपतियों के कोल लीज रद्द कर दिए गए. पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में यानी वर्ष 1992 से कोयला खनन के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई. कोल इंडिया और सिंगरेनी के 143 कोल ब्लॉक पूंजीपतियों को सौंप दिए गए. फिर कोयला खनन में लोहा और इस्पात के अलावा बिजली उत्पादन करने वाले घरानों को भी शामिल कर अधिनियम में 1993 में संशोधन किया गया. राव के बाद प्रधानमंत्री बने एचडी देवेगौड़ा ने मार्च 1996 में इसमें सीमेंट घरानों को भी शामिल कर दिया. मनमोहन सिंह सरकार ने जुलाई 2007 में इसमें कोयला गैस उत्पादन और कोयला तरलीकरण को भी जोड़ दिया. कांग्रेस सरकार ने फरवरी 2006 में कोयला खनन में शत-प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष पूंजीनिवेश की इजाजत दे दी. मनमोहन सिंह सरकार ने वर्ष 2010 में एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन किया कि सभी खनिजों के खनन के लिए कोई भी बोली लगा सकेगा. इस तरह कांग्रेस सरकार ने कोयला खनन के निजीकरण का सारा आधार मज़बूत कर दिया और अब भाजपा इसका फायदा उठा रही है. इस समय कोयला क्षेत्र का निजीकरण दो जुगाड़ों से हो रहा है. कोल इंडिया के शेयर बड़े पूंजीपतियों को बेचे जा रहे हैं. हालही कोल इंडिया के और शेयर बिके हैं. दूसरी तरफ निजी क्षेत्र की कंपनियों को अपने इस्तेमाल के लिए कोयला खोदने की इजाजत दी जा रही है. 2014 में नया कानून बन जाने से निजी कंपनियों को आवंटित खदान का कोयला अपने लिए इस्तेमाल करने और किसी अन्य को बेचने की इजाजत मिल गई है. पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र को पहले ही बड़े पूंजीपतियों के धन कमाने के लिए निर्बाध रूप से खोला जा चुका है. अब वही कृत्य कोयला क्षेत्र में किया जा रहा है. इससे आने वाले दिनों में कोयले की कीमतें बढ़ेंगी. इससे बिजली की कीमतें बढ़ेंगी. फिर उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें खुद ब खुद बढ़ जाएंगी. ■

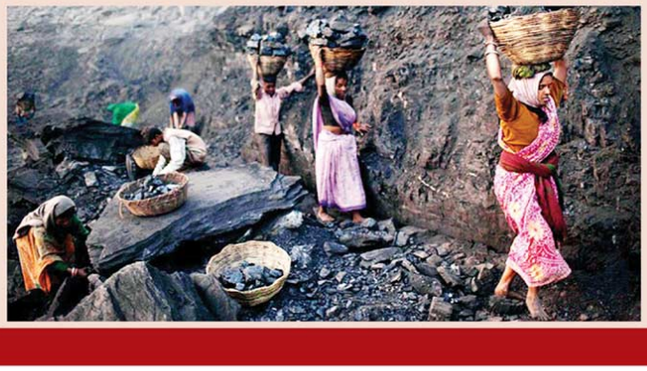

जिंदगी देकर अवैध खदानों से खोद रहे काला सोना

अब यह जगजाहिर है कि अवैध खनन पर अंकुश का प्रभावी उपाय नहीं होने या कारगर नीति नहीं होने के कारण भारी मात्रा में अवैध कोयला बाजार में पहुंच रहा है जिससे देश की अर्थ व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है. देश की परित्यक्त और बंद पड़ी खदानों से हर साल 35 से 40 मिलियन टन कोयला खोदा जाता है. कई खदानें तो राष्ट्रीयकरण के पहले से बंद पड़ी हैं, लेकिन उन खदानों से भी चोरी-चोरी खुदाई जारी है. अधिकतर अवैध खनन परित्यक्त और बंद पड़ी खदानों से ही किया जाता है और इन खदानों में हर साल बड़ी संख्या में मजदूर मरते हैं. मजदूरों की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है. अधिकांश मौतों के बारे में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती. अवैध खनन में लगे गरीब मजदूर परित्यक्त या बंद खदानों में सुरंग बनाकर कोयले की खुदाई करते हैं. जो भी कोयला निकलता है उसे स्थानीय डीलरों को बेच दिया जाता है. डीलरों के जरिए वही अवैध कोयला अवैध मंडियों तक पहुंचता है. ■

ये कंपनियां खोलती हैं यूपीए-एनडीए का असली चेहरा

कोल ब्लॉक आवंटन की कालिख से संप्रग का चेहरा तो काला हुआ ही, राजग का चेहरा भी इसमें कोई साफ-सुथरा नहीं है. काला सोना लूटने में यूपीए के साथ-साथ राजग भी शामिल रहा है. कुछ उन कंपनियों का भी हाल देखें जिन्हें सबने मिल बांट कर अवैध तरीके से कोल ब्लॉक दिए ...

- **पुष्प स्टील और माइनिंग कंपनी :** 20 जुलाई 2010 को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस कंपनी का गठन 2 जून 2004 को हुआ और इसी दिन उसने दिल्ली से हजार किलोमीटर दूर कांकेर में कच्चे लोहे की खदान पाने के लिए आवेदन भी कर दिया. पुष्प स्टील को मध्य प्रदेश सरकार ने 2007 में 550 लाख टन कोयले वाला ब्रह्मपुरी ब्लॉक दे दिया. उस समय भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह भाजपा की सरकार थी. ऐसी कंपनी जिसे खनन के काम का कोई अनुभव नहीं था.
- **थारीवाल ग्रुप :** गुटखा बनाने वाली कंपनी थारीवाल ग्रुप को भी कोल ब्लॉक मिल गया. थारीवाल इंफ्रा नाम की कंपनी ने स्पंज आयरन प्लांट लगाने के लिए जमीन खरीदी और इसी आधार पर उसे 22 नवंबर 2008 को मोहडारी कोयला ब्लॉक दे दिया गया. 240 लाख टन का कोल ब्लॉक प्राप्त करने वाली थारीवाल इंफ्रा सात महीने में ही बिक गई. गोयनका ग्रुप की कंपनी सीईएससी ने इसे करीब 300 करोड़ रुपये में खरीद लिया और कोयला खदानें हथिया लीं.
- **नवभारत ग्रुप :** विस्फोटक बनाने वाली कंपनी को 13 जनवरी 2006 को स्पंज आयरन प्लांट लगाने के लिए मदनपुर नॉर्थ कोयला खदान दे दी गई. खुद का प्लांट न होने की वजह से नवभारत ने सहयोगी कंपनी के प्लांट के आधार पर आवेदन किया था. बाद में उसने अपनी कंपनी बेच डाली. इस तरह तीन करोड़ 60 लाख टन कोयले का ब्लॉक भी नई कंपनी को मिल गया.
- **फील्ड माइनिंग एंड इस्पात लिमिटेड :** इस कंपनी को 8 अक्टूबर 2003 को दो कोयला खदानें चिनोरा और वरोरा वेस्ट दी गईं. दोनों खदानों को मिलाकर कोयला उत्पादन की कुल क्षमता 380 लाख टन थी. कंपनी ने पांच साल यानी 2008 तक खदान का काम शुरू नहीं किया. आखिरकार 2010 में फील्ड माइनिंग एंड इस्पात लिमिटेड को केएसके इनर्जी वेंचर्स ने खरीद लिया. ओहीशा में कोल ब्लॉक का आवंटन हासिल करने वाले तत्कालीन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री एस जगतरक्षकन की कंपनी जेआर पावर जेन प्राइवेट लिमिटेड ने भी ऐसी ही हरकत की थी और वर्ष 2010 में केएसके इनर्जी वेंचर्स को अपने 51 प्रतिशत शेयर बेच डाले थे. इस तरह मंत्री ने अपने प्रभाव से हासिल किया कोल ब्लॉक केएसके के हाथों बेच डाला.
- **बीएस इस्पात :** इस कंपनी को 25 अप्रैल 2001 को ही विदर्भ की मरकी मंगली कोयला खदान दी गई थी. उनके पास 60 हजार टन का स्पंज आयरन प्लांट था, लेकिन उसे 343 लाख टन कोयले वाली खदान दे दी गई. कंपनी आठ साल तक बैठी रही. 2010 में कंपनी बिक गई और कोल ब्लॉक दूसरे के हाथ चला गया.
- **गोंडवाना इस्पात :** इस कंपनी को भी 2003 में माजरा कोल ब्लॉक आवंटित किया गया था. इसके प्लांट की क्षमता 1 लाख 20 हजार टन कोयले की थी लेकिन उसे 15 लाख टन कोयले वाली खदान दे दी गई. यानि 100 साल तक का काम एक झटके में हो गया. 2008 में गोंडवाना इस्पात का बीएस इस्पात में विलय हो गया और बीएस इस्पात को गरिमा बिल्डकॉर्प ने खरीद लिया और फिर 2011 में उसे उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड ने खरीद लिया. इस तरह साजिश करके इतनी बेशकीमती खदान दूसरे के हाथ में दे दी गई.
- **वीरांगना स्टील कंपनी :** 2005 में मरकी मंगली नंबर 2,3,4 खदानें इस कंपनी को दी गई थीं. इनके पास पुराना 60 हजार टन का स्टील प्लांट था, उसके लिए जो खदानें दी गईं उनकी क्षमता 190 लाख टन थी. कंपनी ने पांच साल तक खनन शुरू नहीं किया. 2010 में कंपनी का नाम बदल कर टॉपवर्थ हो गया. इसके बाद केस्ट्रा नाम की कंपनी ने उसे खरीद लिया. जाहिर है नागपुर की इस छोटी सी कंपनी की बोली इसलिए लगी क्योंकि इसके पास बड़े कोल ब्लॉक थे.
- **वैद्यनाथ आयुर्वेद :** आयुर्वेद उत्पाद बनाने वाली कंपनी वैद्यनाथ आयुर्वेद को भी 27 नवंबर 2003 में कोल ब्लॉक दिया गया. 2010 तक यह भी खनन शुरू नहीं कर पाई. 2011 में आखिरकार स्क्रीनिंग कमेटी ने वैद्यनाथ को दिया गया कोल ब्लॉक रद्द कर दिया. उक्त आठ में से तीन मामले ऐसे हैं जब केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन(राजग) की सरकार थी. इसमें से दो मामले विदर्भ के उस समय के हैं जब महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी. यानी राज्य में कांग्रेस की सरकार और केंद्र में भाजपा की सरकार. ठीक वैसे ही जैसे 2004 के बाद केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में भाजपा की सरकारें. ■

पश्चिम बंगाल

भाजपा ममता की प्रतिद्वंद्वी या हमदर्द!

अमित शाह

अमित शाह का नारा भाग ममता भाग फिलहाल कामयाब होता नहीं दिख रहा. वामपंथी दलों को 2011 में 23 प्रतिशत मत मिले थे, जो भाजपा से सिर्फ़ छह प्रतिशत ज्यादा थे. अगर सही दिशा में प्रयास किया जाता, तो यह फ़ासला और कम हो सकता था और भाजपा आज पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के रूप में नज़र आती.

ममता बनर्जी

हेमेंद्र झा

पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है. 2014 के लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए 2015 कड़ी चुनौतियां लेकर आया और मोदी मैजिक दिल्ली-बिहार में नहीं चल सका. पश्चिम बंगाल में भाजपा के मजबूत बने रहने के कई फ़ायदे हैं. अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा, तो पूर्वोत्तर राज्यों की राजनीतिक बागडोर संभालने में उसे आसानी रहेगी. 2011 में भाजपा को पश्चिम बंगाल में एक भी विधानसभा सीट नहीं मिली थी, उसकी सहयोगी पार्टी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने दो सीटें ज़रूर हासिल की थीं. भाजपा के पक्ष में सिर्फ 4.1 प्रतिशत मत पड़े थे. कौन जानता था कि सिर्फ़ तीन वर्षों बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में यह मत प्रतिशत 17 तक जा पहुंचेगा. हालांकि, भाजपा को 42 संसदीय सीटों में से सिर्फ़ दो पर ही बढ़त मिली, लेकिन उसे खुशी के साथ-साथ उम्मीद थी कि वह पश्चिम बंगाल में अपने लिए अवसर ज़रूर तलाश लेगी. यह ऐसा सुनहरा अवसर था, जब पश्चिम बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी में शामिल करने की ज़रूरत थी. पश्चिम बंगाल में अभी भी सिर्फ़ साढ़े चार प्रतिशत लोग भाजपा के सदस्य हैं, जबकि पूरे देश में तक़रीबन आठ प्रतिशत लोग भाजपा के सदस्य हैं. मई 2014 के बाद भाजपा ने ऐसे कोई विशेष क़दम नहीं उठाए, जिससे पार्टी मेंबरशिप में इज़ाफ़ा होता. पार्टी को मिस्डकॉल कैंपेन से कुछ आगे सोचने की ज़रूरत थी. पार्टी को ज़मीनी स्तर पर मजबूत और संगठित करने के लिए राज्य में स्थानीय नेतृत्व का अभाव भी महसूस किया जा रहा है. ग़ौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के पास सिद्धार्थ नाथ सिंह के अलावा और कोई दमदार नेता नहीं है. रूपा गांगुली, जिन्होंने टीवी धारावाहिक महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाया था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र चंद्र कुमार बोस भाजपा में शामिल तो ज़रूर हुए हैं, लेकिन वे राजनीति में अभी नए हैं.

अमित शाह का नारा भाग ममता भाग फिलहाल कामयाब होता नहीं दिख रहा. वामपंथी दलों को 2011 में 23 प्रतिशत मत मिले थे, जो भाजपा से सिर्फ़ छह प्रतिशत ज्यादा थे. अगर सही दिशा में प्रयास किया जाता, तो यह फ़ासला और कम हो सकता था और भाजपा आज पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के रूप में नज़र आती. केंद्र सरकार को राज्यसभा में ममता बनर्जी के समर्थन-सहयोग की ज़रूरत है. शायद इसी वजह से पिछले वर्ष स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान भाजपा का कोई केंद्रीय मंत्री पश्चिम बंगाल में प्रचार करने नहीं आया और न राज्य भाजपा इकाई की वह मांग मंज़ूर हुई, जिसमें केंद्रीय पुलिस बल भेजने की बात कही गई थी. मालदा प्रकरण ने भी ज़्यादा तूल नहीं पकड़ा. ममता सरकार द्वारा आयोजित बंगाल व्यवसायिक सम्मेलन की भी भाजपा के शीर्ष नेताओं ने बढ़-चढ़कर प्रशंसा की. केंद्र सरकार की नीतियां भी भाजपा को तृणमूल का मुख्य प्रतिद्वंद्वी बनने में सहायक नहीं हो पा रही हैं. मोदी सरकार अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे करने वाली है, लेकिन जनता में काफी निराशा है. पश्चिम बंगाल की 72 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है. ममता और वाम दलों की पकड़ ग्रामीण क्षेत्रों पर ज़्यादा है. भाजपा को जो 17 प्रतिशत वोट मिले थे, वे ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों, युवाओं एवं शिक्षित मतदाताओं के थे. ग्रामीण मतदाताओं को लुभाने का कोई प्रयास केंद्र सरकार द्वारा अभी तक नहीं किया गया. खेतिहर मज़दूरों का मेहनताना सिर्फ़ चार प्रतिशत बढ़ा है, जबकि पिछले 10 वर्षों से मेहनताना औसतन 13-14 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ रहा था. प्रधानमंत्री ने किसानों को बाज़ार आधारित मूल्य से 50 प्रतिशत ज़्यादा देने का वादा किया था. यह वादा कभी पूरा होगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है. नए बजट में मनरेगा की धनराशि का 60 प्रतिशत हिस्सा कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों पर खर्च करने की बात एक अच्छी पहल है, लेकिन हक़ीकत में किसानों एवं ग्रामीणों को इसका कितना फ़ायदा मिलेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा.

मौजूदा स्थिति ऐसी नहीं है कि भाजपा पश्चिम बंगाल में ममता को मुख्य रूप से चुनौती दे सके. महाराष्ट्र के अलावा 2014 के बाद हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा का मत प्रतिशत गिरा है. पश्चिम बंगाल में इस बार भाजपा को सिर्फ़ 12 प्रतिशत मत मिलने के आसार हैं.

पश्चिम बंगाल में 27 प्रतिशत मतदाता मुस्लिम हैं. जुलाई 2013 से पहले आरएसएस का उद्देश्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक बदलाव लाने का था और राजनीतिक बदलाव का ज़िम्मा भाजपा के पास था. पिछले दो-तीन वर्षों में आरएसएस की राजनीतिक भूमिका बढ़ चुकी है और उसकी सलाह-मशविरे के बग़ैर राज्य भाजपा के मुख्य सदस्य तक नहीं चुने जाते. आरएसएस के हस्तक्षेप के चलते राज्य भाजपा के नेता असमंजस में हैं और कार्यकर्ताओं को भी सही दिशानिर्देश नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके नतीजे निराशाजनक हो सकते हैं. राज्य भाजपा प्रमुख राहुल सिन्हा की जगह आरएसएस प्रचारक दिलीप घोष दो हफ्ते पहले ही आए हैं. यह स्थिति भाजपा कार्यकर्ताओं के मन में अनेक उलझनें पैदा कर रही है. केंद्र सरकार की मौजूदा ज़रूरत खुद को एक धर्मनिरपेक्ष सरकार साबित करने की है, सबका साथ-सबका विकास का नारा ज़मीन पर उतारने की है. पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली के दौरान अजान की आवाज़ सुनकर मोदी द्वारा अपना भाषण रोक देना उनकी धर्मनिरपेक्ष भावनाओं को दर्शाता है और काबिले तारीफ़ भी है. आरएसएस प्रमुख मोहन भगवत ने भी यह कहकर कि भारत माता की जय कहने के लिए किसी पर दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है, साफ़ संकेत दिया है कि भारत में विकास का मुद्दा ही प्रमुख रहेगा. अगर भाजपा एवं आरएसएस के आम कार्यकर्ताओं में भी इसी विचारधारा का समावेश हो जाए, तो वह दिन दूर नहीं, जब भाजपा का झंडा पश्चिम बंगाल में लहराने लगेगा और राज्य सरकार भी उसी की होगी.

मौजूदा स्थिति ऐसी नहीं है कि भाजपा पश्चिम बंगाल में ममता को मुख्य रूप से चुनौती दे सके. महाराष्ट्र के अलावा 2014 के बाद हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा का मत प्रतिशत गिरा है. पश्चिम बंगाल में इस बार भाजपा को सिर्फ़ 12 प्रतिशत मत मिलने के आसार हैं. वाम दल-कांग्रेस गठबंधन आश्चर्यजनक उलटफेर कर सकता है. 2014 में वाम दलों को 30 प्रतिशत मत मिले थे और कांग्रेस को क़रीब 10 प्रतिशत. अगर दोनों के मत प्रतिशत आपस में मिला दिए जाएं, तो आंकड़ा तृणमूल से आधा प्रतिशत ज़्यादा बैठता है. 2011 के विधानसभा चुनाव में भी, जब तृणमूल-कांग्रेस गठबंधन था, यही स्थिति थी. यानी वाम दलों और कांग्रेस का मत प्रतिशत आपस में मिलाने के बाद तृणमूल से ज़्यादा था. वाम दलों को उम्मीद है कि इस बार उन्हें राज्य में क़रीब एक करोड़ 83 लाख मत मिलेंगे और कांग्रेस को क़रीब 50 लाख. इस तरह वाम दल-कांग्रेस गठबंधन को लगभग दो करोड़ 23 लाख मत मिलने की उम्मीद है, जो तृणमूल को मिलने वाले संभावित दो करोड़ 12 लाख मतों से ज़्यादा बैठते हैं. अगर बिहार वाला अंकगणित पश्चिम बंगाल में भी लागू हो गया, तो राज्य की बागडोर एक बार फिर वाम दलों के हाथों में होगी. ■

(लेखक प्राध्यापक हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

गैंगवार की गिरफ्त में राजस्थान, विधानसभा में घिरी सरकार

सिधारो म्हारे देश से...

सुनीता सिंह

राजस्थान के धोरे एक बार फिर गैंगवार की तपिश से तप रहे हैं. पुलिस की गिरफ्त से कुछ महीनों पहले फरार हो चुके कुख्यात आनंदपाल और उसके दुश्मन राजू ठेहट की आपसी रंजिश यहां के अमनपसंद समाज पर भारी पड़ती नज़र आ रही है. हाल की घटनाओं ने न सिर्फ सामाजिक चिंता को और विस्तार दिया है, बल्कि पुलिस और सरकार के माथे पर पड़ी शिकन भी और गहरी होती दिखाई दे रही है. विधानसभा में न सिर्फ विपक्ष, बल्कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी सरकार को इस मुद्दे पर घेरा. नतीजे में राज्य के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया को भी संसद में यह बयान देना पड़ा कि जब तक वे आनंदपाल के गिरोह को नेस्तनाबूद नहीं कर देते, चैन से नहीं बैठेंगे.

आनंदपाल सिंह

राजू ठेहट

जयपुर से शुरू, लेकिन नागौर में खत्म नहीं

सोमवार 21 मार्च की सुबह राज्य पुलिस के लिए एक सफलता की सूचना तो लाई, लेकिन साथ ही शाम होते-होते महकमे में उदासी भी पसर गई. दरअसल, दिन में जयपुर में एसओजी ने श्रीमाधोपुर निवासी शार्प शूटर शंकर को गिरफ्तार किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह कुख्यात अपराधी आनंदपाल के दुश्मन राजू ठेहट गिरोह के लिए पिछले दस साल से काम करता है. पुलिस के लिए इसी सफलता में उसकी विफलता का भी राज छिपा था. दरअसल, शंकर की गिरफ्तारी करके खुश हो रही पुलिस को यह तो पता चल चुका था कि शंकर और उसके चार साथी जयपुर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने आए थे और शंकर भले ही पकड़ में आ गया हो, लेकिन उसके चार साथी फरार हो चुके हैं. राज्य स्तर पर ए श्रेणी की नाकाबंदी की गई, लेकिन शायद पुलिस को भी यह आभास नहीं था कि राजू ठेहट गैंग इस समय किस कदर आधुनिक हथियारों से लैस हो चुका है. वरना ऐसी चूक उससे नहीं होती, जो नागौर में हो गई.

यह हुआ था नागौर में

कथित रूप से आनंदपाल और उसके गिरोह के गुर्गों पर हमला करने की फिराक में जयपुर पहुंचे राजू ठेहट गैंग के पांच शार्प शूटरों में से शंकर की गिरफ्तारी के बाद यहां से ठेहट गैंग के बाकी सदस्य आगरा निवासी शार्प शूटर गोल्डी, हरियाणा निवासी रोहित फौजी, ग्वालियर निवासी हरेंद्र यादव और एक अन्य ने नागौर की राह पकड़ी. ये लोग नागौर की सीमा में घुस गए, लेकिन कुछ ही दूर पहुंचकर उन्हें पता चल गया कि पुलिस की तगड़ी घेराबंदी है. ऐसे ही एक जगह नाकाबंदी देखकर जब फॉर्च्यूनर कार सवार बदमाशों ने अचानक ही कार को फलौदी मार्ग पर मोड़ दिया, तो दूर खड़ी पुलिस टीम की निगाह से वे नहीं बच सके. नतीजे में क्यूआरटी यानी क्विक रिस्पांस टीम उनके पीछे लग गई. बदमाश कुछ ही दूर गए थे कि पुलिस की जद में आ गए. मुठभेड़ हुई. दोनों ओर से दर्जनों राउंड गोलियां चलीं. नतीजे में बदमाशों की गोली से पुलिस को दो जांबाज खुमाराम और हरेंद्र चौधरी घायल हो गए, जिनमें से एक खुमाराम ने देर रात दम तोड़ दिया. इसके बाद बदमाश तेजी से वहां से भागे और मोटर साइकिल सवार दो लोगों को भी इसी दौरान उन्होंने कुचल दिया. हड़बड़ाहट में बदमाश कार छोड़कर खेतों से होते हुए वहां से भाग निकले. हिस्ट्रीशीटर राजू ठेहट के खिलाफ हत्या, लूट सहित अन्य धाराओं में 28 मुक़दमे दर्ज हैं. इनमें से 16 मामलों की कोर्ट में सुनवाई चल रही है.

पुलिस महकमे में हड़कंप

इधर, मुठभेड़ में दो पुलिसवालों के हताहत होने का समाचार मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. फॉर्च्यूनर कार बरामद हो चुकी थी और उसमें से बरामद असलहे देख पुलिस को अंदाजा हो गया था कि बदमाश किसी बड़ी गंभीर वारदात को अंजाम देने आए थे, लेकिन कहीं उनके प्लान में कुछ गड़बड़ हो गई और बीच में पुलिस आ गई. बहरहाल, यह घटना न सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बनी, बल्कि विधानसभा में भी सरकार इस मसले पर घिर गई.

कांग्रेस नेता के चाचा से लूटी गई थी फॉर्च्यूनर कार

पुलिस जांच में यह बात भी जल्द ही सामने आ गई कि जिस कार से बदमाश जयपुर से नागौर की तरफ गए, वह कार बीकानेर निवासी आशाराम डूडी से फरवरी माह में बीकानेर इलाके से ही लूटी गई थी. आशाराम विपक्ष के नेता रामेश्वर डूडी के चाचा हैं. खुद डूडी ने विधानसभा में इस मसले पर सरकार को यह कहकर घेरा कि उन्होंने खुद कार लूट की खबर आईजी को उसी समय दे दी थी, फिर क्या कारण है कि इस तरह की घटना को रोका नहीं जा सका.

आनंदपाल को जेल में ही थी मारने की योजना

जयपुर में पकड़े गए शंकर की मानें, तो पिछले साल नवंबर में आनंदपाल की जेल के अंदर अथवा जेल से पेशी पर ले जाते समय हत्या करने की योजना थी. शंकर ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के चार लड़कों से दोस्ती करके उनके घर से ही जेल परिसर की रेकी की थी, जो कारागर के पास में ही था. लेकिन इसी बीच उसके नए बने साथियों को पुलिस ने फायरिंग के एक मामले में सूचना मिलने के बाद नाकाबंदी में दबोच लिया. शंकर को खबर लगी, तो वह फरार हो गया, लेकिन पुलिस को पता चल चुका था कि युवकों के कमरे में कोई और नहीं बल्कि राजू ठेहट गैंग का कुख्यात गुर्गा शंकर छिपा था. वहां से पुलिस को एके-47 की मैगजीन के अलावा एक अत्याधुनिक पिस्टल और 71 राउंड कारतूस मिले थे, जिससे यह अंदाजा तो हो गया था कि कुछ गंभीर घटने वाला है.

मुठभेड़ से उठते कई सवाल

पुलिस और राजू ठेहट गैंग की मुठभेड़ से भले ही पुलिस यह कहती फिर रही हो कि ये शार्प शूटर अपने नंबर एक दुश्मन आनंदपाल की हत्या करने आए थे, लेकिन सच तो यह है कि पुलिस अफसरों के भी इस विचार के आते ही पसीने छूट जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शूटर कहीं उन पर तो निशाना नहीं साधे हुए हैं, जो आनंदपाल और राजू ठेहट के निशाने पर समान रूप से हैं. मसलन,कुछ राजनेता, ठेकेदार, बिल्डर, व्यवसायी आदि. बहरहाल पुलिस यही मानकर चल रही है कि शूटर्स आनंदपाल को ठिकाने लगाने आए थे. पुलिस की इस सोच से एक और सवाल उभरता है कि क्या पुलिस से फरारी के बाद से आनंदपाल सत्ता और शासन के ठीक नाक के नीचे ही रह रहा है. शार्प शूटर नागौर क्यों गए, यह भी एक सवाल है. पुलिस इसी आधार पर अंदाजा लगा रही है कि शायद आनंदपाल नागौर या जयपुर में ही कहीं है, जिसे ठिकाने लगाने की कोशिश में राजू ठेहट गैंग है. ■

feedback@chauthiduniya.com

आनंदपाल भागा या भगाया गया!

जयपुर सरकार और राजस्थान पुलिस के लिए गैंगस्टर आनंदपाल सिंह और राजू ठेहट गिरोह बड़ी चुनौती बन चुके हैं. दोनों गिरोहों का दबदबा शेखावाटी से पूरे प्रदेश में फैल चुका है. आनंदपाल की फरारी के बाद राजूठेहट गिरोह और भी सक्रिय हो गया है. 2014 में बीकानेर जेल में राजू ठेहट गिरोह के जयप्रकाश और रामपाल ने आनंदपाल के सबसे करीबी बानूड़ा को गोलियों से भून दिया था. जवाबी हमले में आनंदपाल गैंग ने जेल में ही जयप्रकाश और रामपाल की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी. आनंदपाल के पुलिस हिरासत से फरार होने के बाद से ही शेखावाटी क्षेत्र में खूनी संघर्ष की आशंका जताई जाने लगी थी. आनंदपाल के फरार होने के मामले में पुलिस कमांडो शक्ति सिंह सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया गया. लेकिन इसके बावजूद आनंदपाल की फरारी का रहस्य नहीं खुल सका. इस मामले में पुलिस की मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं. आनंदपाल चार सितम्बर को ही राजस्थान के परबतसर क्षेत्र से पुलिस हिरासत से फिल्मी अंदाज में फरार हो गया था. उसकी गिरफ्तारी के लिए दर्जनभर से अधिक टीमें बनाई गईं, आला अधिकारियों को शामिल किया गया, पूरा ताम्झाम दिखाया गया, लेकिन आनंदपाल सिंह का कहीं पता नहीं लगा. ■

उत्तराखंड में दो की लड़ाई में तीसरे को फ़ायदा वाला फार्मूला फिट कर रही सपा

पहाड़ पर भी सत्ता की आशा

प्रभात रंजन दीन

उत्तराखंड में राजनीतिक उठापटक के बीच समाजवादी पार्टी दो की लड़ाई में तीसरे को फायदा का फार्मूला फिट कर रही है. अब उत्तराखंड में भी सत्ता पाने की समाजवादी पार्टी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जोर मार रही है. सपा ने यह साफ–साफ ऐलान भी किया है कि उत्तराखंड के लोग अब राजनीतिक विकल्प चाहते हैं, क्योंकि वे भाजपा और कांग्रेस दोनों को देख चुकेहैं और प्रशासनिक नाकारेपन का स्वाद चख चुके हैं. सपा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की तरह ही समाजवादी पार्टी उत्तराखंड का भी समग्र विकास कर सकती है. 15 वर्षों के दरम्यान प्रदेश की जनता भाजपा और कांग्रेस की सरकारों से ऊब चुकी है और अब बदलाव चाहती है. उत्तराखंड में राजनीतिक विकल्प के रूप में खड़ा होने की समाजवादी पार्टी की कोशिशें काफी अर्से से चल रही थीं, लेकिन यह प्रक्रिया हाल के दिनों में तेज़ हुई है. सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने पिछले दिनों उत्तराखंड जाकर मुख्यमंत्री हरीश रावत से मुलाक़ात की थी और मेट्रो रेल से लेकर कई अन्य विकास परियोजनाओं में गहरी रुचि दिखाई थी. दोनों नेताओं के बीच कई परियोजनाओं को लेकर औपचारिक करार भी हुए.

दोनों राज्यों में विधानसभा चुनावों को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपने विस्तार की योजना बनाई है. शिवपाल ने ऐलान भी कर रखा है कि समाजवादी पार्टी पूरे उत्तराखंड राज्य में मुलायम संदेश यात्रा निकालेगी. राज्य के विधानसभा चुनाव में सपा ताकतवर तरीके से हिस्सा लेने की तैयारी कर रही है. यूपी से कटकर बने उत्तराखंड में अपनी राजनीतिक पकड़ स्थापित करने के उद्देश्य से ही उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच मेट्रो ट्रेन चलाने की पहल की है. उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री शिवपाल यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के बीच उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच मेट्रो ट्रेन के संचालन, बांध, नहरों और परिसम्पत्तियों के बंटवारे जैसे महत्वपूर्ण मसलों पर औपचारिक सहमति बनी है. सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने जब यह कहा कि उत्तर प्रदेश में मुरादनगर (गाजियाबाद) तक मेट्रो ट्रेन आ चुकी है और अब इसे उत्तराखंड के हरिद्वार तक लाया जाएगा, तो इसके राजनीतिक निहितार्थ साफ–साफ समझे जा रहे थे. शिवपाल ने यह भी कह दिया कि गंगा नहर के पास खाली पड़ी भूमि का मेट्रो ट्रैक बनाने के काम में इस्तेमाल किया जाएगा.

समाजवादी पार्टी का कहना है कि जिन मुद्दों को लेकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, वे आज भी यथावत हैं. वहां के बेरा़ज़गारों को रोजगार नहीं मिला, जिससे लोगों का पलायन जारी है. विकास के नाम पर उत्तराखंड में कुछ भी नहीं हुआ. उत्तराखंड के पांचों सांसद भाजपा के हैं और केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसके बावजूद प्रदेश को न तो विशेष राज्य का दर्जा दिया जा रहा है और न ही ग्रीन बोनस दिया जा रहा है, जबकि उत्तराखंड का पैंसठ प्रतिशत हिस्सा वन से आच्छादित है. शिवपाल ने अगले वर्ष उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों के बारे में कहा कि समाजवादी पार्टी समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों और संगठनों से तालमेल बनाकर चुनाव लड़ेगी. इसके लिए उत्तराखंड के समाजवादी, लोहियावादी और चौधरी चरण सिंह वादी विचारधारा के राजनीतिक दलों और संगठनों से समन्वय स्थापित कर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी. उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए अप्रैल के पहले सप्ताह से राज्यभर में मुलायम संदेश यात्रा निकाले जाने की भी तैयारी है. यात्रा के माध्यम से आम जनता को पार्टी द्वारा राज्य हित में किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी. समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड के अध्यक्ष सत्य नारायण सचान ने कहा कि समाजवादी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड में चल रही राजनीतिक उठापटक पर बारीक नज़र रखे हुए है. आलाकमान ने भी प्रदेश कमेटी को चुनाव के लिए तैयार रहने और प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों की पूरी रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

डिम्पल यादव होंगी उत्तराखंडी कार्ड!

समाजवादी पार्टी कन्नौज से सांसद व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को उत्तराखंड में अपना चुनावी चेहरा बनाकर प्रस्तुत कर सकती है. डिम्पल यादव (रावत) उत्तराखंड के कोटद्वार की रहने वाली हैं. संयोग यह है कि मुलायम की दोनों बहुएं उत्तराखंड की हैं. छोटी बहू अपर्णा यादव (बिष्ट) भी उत्तराखंड की ही हैं. यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश अपनी पत्नी डिम्पल के साथ जल्दी ही उत्तराखंड की तीर्थ यात्रा पर निकलने वाले हैं. स्पष्ट है कि इसके पीछे उनकी राजनीतिक मंशा क्या है. उत्तराखंड के दौरे के दरम्यान अखिलेश की सभाएं और रैलियां कराने की भी तैयारी चल रही है. समाजवादी पार्टी उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से अधिक मैदानी और तराई के इलाकों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है. सपा का लक्ष्य हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, नैनीताल और देहरादून जिले की विधानसभा सीटों पर मजबूती से अपनी मौजूदगी दर्ज कराना है.

मुलायम का भरता-पूरता राजनीतिक परिवार

अपर्णा यादव को टिकट दिए जाने की घोषणा के साथ ही मुलायम परिवार का 19वां सदस्य सक्रिय राजनीति में शामिल हो गया. मुलायम के भरे-पूरे राजनीतिक परिवार पर एक निगाह डालते चलें...

- **मुलायम सिंह यादव:** नेताजी मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. मुलायम तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में रक्षा मंत्री रहे.
- **शिवपाल सिंह यादव:** शिवपाल सिंह यादव ने सहकारिता आंदोलन के जरिए राजनीति में पैठ बनाई. 1988 में वे पहली बार इटावा के जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष चुने गए. 1996 में सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने अपनी जसवंतनगर की सीट छोटे भाई शिवपाल के लिए खाली कर दी थी. इसके बाद से शिवपाल का जसवंतनगर की विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार है.
- **रामगोपाल सिंह यादव:** मुलायम के चचेरे भाई रामगोपाल यादव लगातार राज्यसभा से सांसद हो रहे हैं. वे चुनाव लड़कर भी संसद पहुंचे थे जब वर्ष 2004 में मुलायम ने संभल सीट रामगोपाल के लिए छोड़ दी थी और खुद मैनपुरी से सांसद का चुनाव लड़ा था.
- **अखिलेश यादव:** मुलायम के बेटे अखिलेश यादव ने 1999 का लोकसभा चुनाव संभल और कन्नौज दोनों सीटों से लड़ा और जीते. अखिलेश कन्नौज से सांसद रहे. अब वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं.
- **धर्मेंद्र यादव:** मुलायम के भतीजे धर्मेंद्र यादव मुलायम द्वारा खाली की गई मैनपुरी सीट से चुनाव लड़े और जीते. बाद में धर्मेंद्र बदायूं से भी सांसद हुए.
- **डिंपल यादव:** अखिलेश यादव ने 2009 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज और फिरोजाबाद जीतकर फिरोजाबाद की सीट अपनी पत्नी डिंपल यादव के लिए छोड़ दी, लेकिन डिंपल वहां से हार गईं. 2012 में मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश ने कन्नौज लोकसभा सीट डिंपल के लिए खाली कर दी और डिंपल वहां से निर्विरोध जीतीं.
- **तेज प्रताप यादव:** तेजप्रताप यादव सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के पोते हैं. वे मैनपुरी से सांसद हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी और आजमगढ़ दोनों सीटों से चुनाव लड़ा था. इसके बाद उन्होंने मैनपुरी सीट खाली कर दी थी. तेज प्रताप यादव चुनाव लड़े और जीते.
- **अक्षय यादव:** अक्षय यादव मौजूदा समय में फिरोजाबाद से सपा सांसद हैं. अक्षय यादव भी पहली बार चुनाव जीतकर सक्रिया राजनीति में उतरे हैं. यह सीट यादव परिवार की पारंपरिक संसदीय सीट रही है. जब अखिलेश यादव ने वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद और कन्नौज से चुनाव लड़ा था, उस समय फिरोजाबाद के चुनाव प्रबंधन की कमान अक्षय यादव ने ही संभाली थी.
- **प्रेमलता यादव:** मुलायम सिंह यादव के भाई राजपाल यादव की पत्नी प्रेमलता यादव 2005 में इटावा की जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई थीं.
- **सरला यादव:** उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री शिवपाल यादव की पत्नी सरला यादव 2007 में जिला सहकारी बैंक इटावा की राज्य प्रतिनिधि बनाई गई थीं.
- **अरविंद यादव:** मुलायम की चचेरी बहन और रामगोपाल यादव की सगी बहन गीता देवी के पुत्र अरविंद यादव ने 2006 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा और मैनपुरी के करहल ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख के पद पर निर्वाचित हुए. 2012 में वह छिबरामऊ से विधानसभा चुनाव जीते थे. इससे पहले भी वह इसी सीट से विधायक बने थे.
- **आदित्य यादव:** शिवपाल यादव और सरला यादव के पुत्र आदित्य यादव 2010 में इटावा जिला विकास परिषद के चुनाव में हारे. वर्तमान में उत्तर प्रदेश प्रादेशिक को–ऑपरेटिव फेडरेशन के अध्यक्ष हैं. आदित्य यादव को भरथना विधानसभा सीट से इस बार प्रत्याशी बनाए जाने की तैयारी है.
- **अंशुल यादव:** मुलायम सिंह यादव के भाई राजपाल यादव और उनकी पत्नी प्रेमलता यादव के बड़े बेटे हैं अभिषेक यादव उर्फ अंशुल यादव. अंशुल 2016 में इटावा से निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं.
- **संध्या यादव:** सपा सुप्रीमो की भतीजी और सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन संध्या यादव ने जिला पंचायत अध्यक्ष के जरिए राजनीतिक एंट्री की है. उन्हें मैनपुरी से जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए निर्विरोध चुना गया है.
- **अपर्णा यादव:** मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है.
- **अनुराग यादव:** मुलायम के भाई अभयराम यादव के बेटे अनुराग को भी विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी चल रही है.
- **वंदना यादव:** सांसद धर्मेंद्र यादव की साली वंदना यादव हमीरपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष चुनी गई हैं.
- **मृदुला यादव:** मैनपुरी से सांसद तेज प्रताप यादव की मां मृदुला यादव सैफई ब्लॉक प्रमुख चुनी गई हैं.
- **अजंत सिंह यादव:** समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के साले अजंत सिंह यादव भी चौबइया ब्लॉक के प्रमुख चुने गए हैं.

डिम्पल यादव को उत्तराखंड की भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की अंदरूनी तैयारियां इसी से समझी जा सकती हैं कि प्रदेश इकाई इस बारे में अपना प्रस्ताव शीर्ष नेतृत्व को पहले ही भेज चुकी है. सपा की उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष सत्यनारायण सचान इसकी आधिकारिक पुष्टि करते हैं. उन्होंने कहा कि सपा की कोर कमेटी की बैठक में डिम्पल यादव को उत्तराखंड का प्रभारी बनाने संबंधी प्रस्ताव पर केंद्रीय नेतृत्व में विस्तार से चर्चा भी हो चुकी है और सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव इसे लेकर काफी गंभीर भी हैं. उल्लेखनीय है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड वाले हिस्से में भी समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रभाव था. उत्तराखंड की 23 सदस्यीय अंतरिम विधानसभा में समाजवादी पार्टी के तीन विधायक थे लेकिन उत्तराखंड में अब तक हुए तीनों विधानसभा चुनावों में सपा का खाता नहीं खुल पाया.

सपा ने पहल नहीं की तो चूकी

कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे यूपी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी से समाजवादी पार्टी के रिश्ते काफी अंतरंग हैं. सपा ने बुजुर्ग एनडी में सांस फुंकी है. सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव हों या मुख्यमंत्री अखिलेश या कोई अन्य सपा नेता, सबने एनडी को प्रतिष्ठा दी और उनका ख्याल रखा. अब चुनाव सामने है और सपा नेतृत्व उत्तराखंड को लेकर भी अपनी रणनीति बना रहा है. ऐसे में एनडी को लेकर सपा ने सटीक समय पर कोई पहल नहीं की तो यह सपा की चूक ही मानी जाएगी. एनडी का उत्तराखंड में अब भी काफी प्रभाव है और पहाड़ी प्रदेश में एनडी को विकास पुरुष के रूप में देखा जाता है. एनडी अपने डीएनए–पुत्र रोहित शेखर तिवारी को कांग्रेस का टिकट दिलाने का प्रयास कर रहे हैं. कांग्रेस कोई निर्णय ले उसके पहले ही सपा को लपक लेना चाहिए, ऐसा राजनीतिक समीक्षक जरूरी मानते हैं. अगर एनडी रोहित के लिए कांग्रेस का टिकट पाने में सफल हो जाते हैं तो सपा की रणनीति पर चोट आएगी. सपा का दांव उल्टा पड़ जाएगा. एनडी जैसे प्रभावशाली नेताओं के बगैर उत्तराखंड में सपा की पैठ मुश्किल है. हरिद्वार जिले के पंचायत चुनावों में सपा ने अपनी स्थिति देख ली है. पंचायत चुनाव में सपा समर्थित सारे प्रत्याशी हार गए. विधानसभा चुनाव में सपा एनडी तिवारी के भरोसे खाता खोल सकती है. सपा ने रोहित शेखर तिवारी को यूपी में परिवहन विभाग का सलाहकार बनाकर मंत्री का दर्जा दे रखा है. अब चुनाव में रोहित को सपा प्रत्याशी के रूप में उतारे जाने की घोषणा होनी बाकी है, दांव इसी क्षण पर टिका है.

अपर्णा बहू भी आ रहीं सपाई धारा में

सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को भी समाजवादी धारा में लाने की कोशिश की जा रही है. समानान्तर धारा रचने की कोशिशों में लगातार लगीं अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है. भाजपा अपर्णा को लपकती उसके पहले ही समाजवादी पार्टी ने अपर्णा यादव को लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया. वरिष्ठ सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने इसकी आधिकारिक घोषणा की. पार्टी ने फिर अलग से भी विज्ञप्ति जारी कर इस फैसले के बारे में बताया.

सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिम्पल यादव तो ससुराल की समाजवादी धारा पर चलती रही हैं, लेकिन मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव अपनी अलग धारा रचने में लगी रही हैं. इसे लेकर सपाई ससुराल चिंतित भी रही है और सतर्क भी. सपाई ससुराल की आशंका वाजिब थी कि अगर सपा की तरफ से डिम्पल उत्तराखंड में लॉन्च होती हैं तो कहीं ऐसा न हो कि अपर्णा भाजपा की तरफ से प्रक्षेपित हो जाएं. अपर्णा यादव उत्तराखंड को लेकर लखनऊ में होने वाली गतिविधियों में काफी सक्रिय हैं. पिछले ही दिनों अपर्णा ने उत्तराखंड महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया और पहाड़ की प्रतिभाओं को सम्मानित किया था.

मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव (बिष्ट) अपनी अलग धारा से ससुराल को लगातार चौंकाती रही हैं. पिछले दिनों लखनऊ के बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में अपर्णा की मौजूदगी खासी चर्चा में रही. इसके पहले भी अपर्णा नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की प्रशंसा कर चुकी हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर मोदी के साथ ली गई सेल्फी भी पोस्ट की थी. वह गोवध के खिलाफ अपने विचार भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चर्चित हो चुकी हैं. अपर्णा नरेंद्र मोदी की तुलना महात्मा गांधी व राम मनोहर लोहिया से करके भी सुर्खियां बटोर चुकी हैं. कुछ राजनीतिक पंडित यह भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित किए जाने पर अगर अपर्णा चुनाव लड़ने से मना कर देती हैं तो यह साफ हो जाएगा कि अपर्णा सोचे समझे इरादे से समानान्तर राजनीतिक धारा पर चल रही हैं. सपा की इस घोषणा से फिलहाल उन कयासों पर विराम लग गया जिनमें आने वाले विधानसभा चुनाव में अपर्णा को भाजपा द्वारा अपना प्रत्याशी बनाए जाने की संभावना जताई जा रही थी. वैसे, एक सोच यह भी रही है कि मुलायम के बाद सपा में अपर्णा के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी, इसलिए अपनी राजनीतिक धारा पहले ही निश्चित कर लेना अपर्णा के लिए जरूरी है. लोगों को अपर्णा के स्व–निर्णय का एहसास यदा–कदा होता रहा है. जब डिम्पल यादव ने अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षी 1090 महिला हेल्पलाइन सेवा की हिमायत की थी तो अपर्णा ने पुलिस की 100 नंबर सेवा को बेहतर बताया था. आमिर खान के असहिष्णुता वाले बयान के खिलाफ अपर्णा ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी थी जबकि सपा सुप्रीमो ने आमिर के प्रति समर्थन जताया था. गोरखनाथ धाम जाकर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के कारण भी अपर्णा देशभर में चर्चित हुई थीं. ■

सिर पर मैला ढोने की अमानवीय प्रथा

इस कलंक से मुक्ति के लिए सिर्फ़ क़ानून काफ़ी नहीं

चेन्नई के एक होटल ने सरवनन, कुमार, वेलमुरुगन एवं राजेश को बीते 15 मार्च की सुबह अपने सेप्टिक टैंक की सफ़ाई के लिए बुलाया. क़रीब दस बजे उक्त चारों लोग टैंक के अंदर गए, लेकिन फिर ज़िंदा वापस नहीं आ सके. हालांकि, हाथ से मैला उठवाना या सीवर की सफ़ाई के काम पर किसी शख़्स को लगाना क़ानूनन अपराध है, लेकिन फिर भी चेन्नई की यह घटना न तो अपनी तरह की पहली घटना है और न आख़िरी. सरवनन, कुमार एवं वेलमुरुगन का संबंध एक ही परिवार से था और यह काम करने वाले आम तौर पर एक ही परिवार के होते हैं. लिहाज़ा, जब कोई अनहोनी होती है, तो उसका दर्द पूरे परिवार को सहना पड़ता है...

भीम यात्रा की 10 मांगें

1. सीवर-सेप्टिक टैंक में इंसानों को प्रवेश कराकर उनकी हत्या करना तुरंत बंद करो.
2. पूरे देश से मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन करो.
3. वर्ष 1993 से लेकर अब तक सीवर-सेप्टिक टैंक में जितने लोगों की मौत हुई है, उनके आश्रितों को सुप्रीम कोर्ट के 27 मार्च, 2014 के आदेश के अनुसार तुरंत 10 लाख रुपये का मुआवज़ा दो.
4. देश भर में सीवर-सेप्टिक टैंक की सफ़ाई के काम का आधुनिकीकरण करो.
5. सफ़ाई कर्मचारियों को दी जाने वाली एकमुश्त राहत राशि चालीस हज़ार से बढ़ाकर तीन लाख रुपये की जाए.
6. सफ़ाई कर्मचारियों को इज्जतदार आजीविका के लिए पांच एकड़ कृषि भूमि दो.
7. सफ़ाई कर्मचारियों को राशनकार्ड और घर दो.
8. सफ़ाई कर्मचारी की अकेले जीवनयापन कर रही पत्नी को विशेष पेंशन दो.
9. पचास वर्ष से अधिक उम्र के सफ़ाई कर्मचारियों को पेंशन दो.
10. सफ़ाई के काम से ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करो.

शफ़ीक़ आलम

हाथ से मैला उठाने, उसे सिर पर ढोने या मैनुअल स्केवेंजिंग का घिनौना और अमानवीय कार्य आज भी हमारे देश में जारी है. मैला ढोने की यह प्रथा देश के माथे पर एक ऐसा बदनुमा दाग़ है, जिसे देखकर सबको शर्मिंदगी महसूस होती है और सभी एक स्वर में इसके ख़ात्मे की बात करते हैं. मौजूदा सरकार और पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इस अमानवीय व्यवसाय का संज्ञान लिया है. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे जातीय रंगभेद (कास्ट अपर्थाइड) कहा था, वहीं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसे देश के माथे पर कलंक बताते हुए इसके जल्द से जल्द ख़ात्मे के लिए आम लोगों का सहयोग चाहते हैं. यह प्रथा ख़त्म करने के लिए देश की संसद ने 1993 और 2013 में दो क़ानून पारित किए. यही नहीं, 1993 में सफ़ाई कर्मचारी आयोग का गठन भी हो चुका है. लेकिन, ज़मीनी हक़ीक़त यह है कि आज भी हाथ से मैला उठाने और सिर पर ढोने की प्रथा न सिर्फ़ जारी है, बल्कि इस पेशे को अपनाने पर मजबूर लोग सेप्टिक टैंकों एवं सीवरों की सफ़ाई के दौरान लगातार मौत का शिकार भी बन रहे हैं. एक अनुमान के मुताबिक, हर वर्ष तक़रीबन एक हज़ार लोग सीवर या सेप्टिक टैंक की सफ़ाई के दौरान ज़हरीली गैसों की चपेट में आकर मारे जा रहे हैं. हाथ से मैला उठाने और सिर पर ढोने वाले लोगों में जागरूकता फैलाने और उनके कल्याण के लिए 1980 के दशक से काम करने वाले संगठन सफ़ाई कर्मचारी आंदोलन की ओर से इस प्रथा के विरोध में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, 2015 से भीम यात्रा की शुरुआत हुई, जिसका समापन डॉ. बीआर अंबेडकर की 125वीं जयंती यानी 14 अप्रैल को दिल्ली में होगा. दरअसल, इस यात्रा का मकसद वही है, जिसके ख़िलाफ़ आज से 115 वर्षों पहले महात्मा गांधी ने आवाज़ उठाई थी. गांधी जी ने 1901 के कांग्रेस अधिवेशन में सिर पर मैला ढोने की घृणित एवं अमानवीय प्रथा और इससे जुड़ी सामाजिक परिस्थितियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी. लेकिन, आज़ाद भारत में भी इस आवाज़ को सत्ता में बैठे लोगों के कानों तक पहुंचने में तक़रीबन आधी सदी का समय लग गया. इस प्रथा के ख़िलाफ़ भारत में पहली बार 1993 में क़ानून बनाया गया.

क़ानून और क्रियान्वयन

वर्ष 1993 में मैला ढोने वालों को रोज़गार और शुष्क शौचालयों के निर्माण (निषेध) अधिनियम (1993) संसद में पारित करके मैला ढोने की प्रथा और शुष्क शौचालयों के निर्माण को ग़ैर क़ानूनी करार दिया गया. इस क़ानून के तहत दोषियों के ख़िलाफ़ एक वर्ष का कारावास और 2000 रुपये जुर्माने का प्रावधान रखा गया था. लेकिन, सफ़ाई कर्मचारी आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक बेजवाडा विल्सन कहते हैं कि यह क़ानून कभी लागू नहीं हुआ, क्योंकि इसके दुरुपयोग की आशंका के मद्देनज़र इसमें यह प्रावधान रखा गया कि ऐसे तमाम मामलों में सिर्फ़ ज़िलाधिकारी मुक़दमा दायर कर सकता था. नतीजा यह हुआ कि 1993 से 2002 के बीच इस क़ानून के तहत एक भी मुक़दमा दर्ज नहीं हुआ. लेकिन, इसका एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि 1993 से पहले इस प्रथा से जुड़े लोग बाहर आने और आवाज़ उठाने में शर्म महसूस करते थे, वे यह क़ानून लागू होने के बाद न सिर्फ़ बाहर आकर आवाज़ उठाने लगे, बल्कि इस काम को छोड़कर वैकल्पिक रोज़गार की तरफ़ भी जाने लगे.

इसमें कोई शक नहीं कि सरकारी स्तर पर यह क़ानून लागू करने में किसी तरह की कोई इच्छाशक्ति नहीं दिखाई दी. 1993 से लेकर 2012 के बीच केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ़ से यह प्रथा पूरी तरह ख़त्म करने के लिए कई बार समय सीमा तय की गई, लेकिन हालात ज्यों के त्यों बने रहे. 1993 में सफ़ाई कर्मचारी आयोग का गठन भी हुआ, लेकिन अपेक्षित नतीजे सामने नहीं आए, बल्कि उल्टा असर यह होने लगा कि अगर किसी ग़ैर सरकारी संस्था या सिविल सोसायटी का कोई व्यक्ति यह समस्या लेकर सरकार या ज़िम्मेदार अधिकारियों पास जाता था, तो उसे आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया जाता था. यानी सफ़ाई कर्मचारी आयोग या 1993 का क़ानून यह प्रथा ख़त्म करने में पूरी तरह नाकाम रहा. सिविल सोसायटी और इस क्षेत्र में काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं के दबाव के बाद 2013 में प्रोहिबिशन ऑफ एंप्लॉयमेंट एज मैनुअल स्केवेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट (2013) पारित हुआ. इसमें प्रावधान किया गया कि सेप्टिक टैंक और सीवर की सफ़ाई करने वालों को भी मैनुअल स्केवेंजर स्वीकार कर लिए गया. इसके अलावा यह भी प्रावधान किया गया कि कोई भी इंसान सफ़ाई के लिए सीवर के अंदर नहीं जाएगा. अगर जाएगा भी, तो आपात स्थिति में और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ. एक्ट में इस प्रथा से जुड़े लोगों के पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता का भी प्रावधान रखा गया था.

सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला

उक्त क़ानून सही तरीके से लागू कराने के लिए सफ़ाई कर्मचारी समुदाय ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की, क्योंकि सरकारी स्तर पर सिर्फ़ खानापूर्ति हो रही थी. उक्त क़ानून लागू होने के बाद से 2003 तक किसी भी शख़्स के ख़िलाफ़ कोई मुक़दमा दर्ज नहीं किया गया. सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा यह सफ़ाई दी जाती रही कि उनके यहां यह प्रथा ख़त्म हो गई है और सेप्टिक टैंक-सीवर सफ़ाई के दौरान कोई मौत नहीं हुई है. इसके बाद याचिका दाखिल करने वालों ने वह काम अपने हाथ में ले लिया, जो सरकार को करना चाहिए और उन्होंने पूरे देश में एक रैंडम सर्वे करके सुप्रीम कोर्ट में उसे साक्ष्य के तौर पर पेश किया (देखें टेबल). बहरहाल, 12 वर्षों के बाद 27 मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर अपना फ़ैसला सुनाया, जिसमें सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 2013 का क़ानून पूरी तरह लागू करने, सीवरों एवं सेप्टिक टैंकों में होने वाली मौतें रोकने, 1993 के बाद सीवर-सेप्टिक टैंक की सफ़ाई के दौरान सभी मरने वालों के आश्रितों को 10 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया गया. लेकिन, दो वर्ष बीत जाने के बावजूद सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई सर्वे नहीं कराया. बेजवाडा विल्सन कहते हैं कि उनके संगठन ने सीवर-सेप्टिक टैंक में होने वाली 1,327 मौतों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके सरकार को दी, जिनमें से सिर्फ़ तीन प्रतिशत मामलों में मुआवज़ा मिला. शेष मौतों को सरकारी परिभाषा में उलझा कर रख दिया गया है.

सामाजिक प्रभाव

इस प्रथा से जुड़े ज़्यादातर लोग अनुसूचित जाति के हैं, जो सैकड़ों वर्षों से छुआछूत का शिकार रहे हैं. लेकिन, सफ़ाई कर्मियों की विडंबना यह है कि उनका काम उन्हें अनुसूचित जातियों में भी सबसे निचली पायदान पर खड़ा कर देता है. जस्टिस एपी शाह कहते हैं कि इस समुदाय को न सिर्फ़ उनकी जाति से जुड़े पूर्वाग्रह सहने पड़ते हैं, बल्कि मैला ढोने के कारण अनुसूचित जाति से बहिष्कृत भी रहना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि वे यह काम छोड़ना नहीं चाहते. चूंकि उनका संबंध ऐसे समुदाय से है, जो सामाजिक बहिष्कार का शिकार रहा है, इसलिए उनके लिए कोई दूसरा रोज़गार तलाश करना बहुत मुश्किल होता है. माया गौतम दस वर्ष पहले सफ़ाई का काम करती थीं, लेकिन आज वह सफ़ाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए काम करती हैं. वह कहती हैं कि शादी के बाद आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने यह काम शुरू किया था, लेकिन कभी भी अच्छा नहीं लगा. इसमें कोई शक नहीं कि मैला प्रथा जाति से जुड़ी हुई है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है. इस काम में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कहीं ज़्यादा है. बेजवाडा विल्सन कहते हैं कि कहीं न कहीं इसमें पितृसत्ता का भी अमल दखल है, क्योंकि 93 प्रतिशत स्केवेंजर महिलाएं हैं.

आंकड़े क्या कहते हैं

वर्ष 2011 की सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना के मुताबिक, देश में कुल 1.8 लाख हाउसहोल्ड मैला ढोने के काम में लगे हुए हैं. इसमें सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र की है, जो 63 हज़ार है. उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा एवं कर्नाटक का नंबर आता है. यहां भी बेजवाडा विल्सन आंकड़ों में हेराफेरी का आरोप लगाते हैं. उनका कहना है कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक मैनुअल स्केवेंजर्स होने की बात एक चौंकाने वाला तथ्य है. उनके मुताबिक, जनगणना के समय अफ़वाह फैल गई थी कि मैनुअल स्केवेंजर्स को सरकार द्वारा बहुत सारी रियायतें दी जाएंगी. इसी लालच में उन लोगों ने भी इसे अपना पेशा दर्ज करा लिया, जो यह काम नहीं करते हैं. आंकड़ों में हेराफेरी की उनकी बात में सच्चाई भी नज़र आती है, क्योंकि चेन्नई में सेप्टिक टैंक साफ़ करते समय जिन चार लोगों की मृत्यु हुई, उनमें से सिर्फ़ एक का नाम मैनुअल स्केवेंजर के रूप में दर्ज था. सुप्रीम कोर्ट के 2014 के फैसले में यह माना गया था कि देश में 96 लाख शुष्क शौचालय हैं, जिनकी सफाई हाथ से होती है, लेकिन इस कार्य से कितने सफाई कर्मी संबद्ध हैं, इस पर मतभेद है. दरअसल, शुष्क शौचालयों के साथ भी जनगणना के इंट्राज में घालमेल का आरोप है, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना के फॉर्म में शुष्क शौचालय के बजाय गंदा अनसेनेटरी टॉयलेट का कॉलम लाकर यह मसला भी शब्दों के मायाजाल में उलझा दिया गया. सवाल यह भी उठता है कि शुष्क शौचालय किस वर्ग के लोगों के यहां और किस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं. जनगणना में यह तथ्य बखूबी छिपा दिया गया है. बेजवाडा विल्सन के मुताबिक, इसमें हर वर्ग, धर्म और आय वर्ग के हाउसहोल्ड शामिल हैं. उनका कहना है कि जहां बुंदेलखंड में ऊंची जाति के राजपूतों के घर में शुष्क शौचालय पाए गए हैं, वहीं लखनऊ जैसे शहर में भी अभी यह प्रथा विद्यमान है.

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत दो अक्टूबर, 2014 को देश के 4,041 वैधानिक शहरों में की गई थी, लेकिन इसमें मैला ढोने से मुक्ति जैसी कोई बात नहीं कही गई, सारा जोर सिर्फ़ शौचालय निर्माण पर है. ज़ाहिर है, जब देश में करोड़ों शौचालय बनेंगे और उनके सेप्टिक टैंक की सफ़ाई का कोई मैकेनिकल बंदोबस्त नहीं होगा, तो उसे किसी इंसान को ही अपने हाथों से साफ़ करना होगा. यानी यह अमानवीय प्रथा बदस्तूर जारी रहेगी और सेप्टिक टैंकों में सफ़ाई कर्मियों की मौत होती रहेगी. रेलवे के खुले टॉयलेट्स मानव मल रेलवे ट्रैक्स पर गिरा देते हैं, जिसे कोई सफ़ाई कर्मी अपने हाथों से साफ़ करता है. इस बार के बजट में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल डिब्बों में 17,000 बायो टॉयलेट लगाने का प्रस्ताव रखा है. बजट में यह भी कहा गया कि वर्ष 2020-21 तक सभी रेल डिब्बों को खुले शौचालयों से मुक्त कर लिया जाएगा. ज़ाहिर है, कम से कम 2020-21 तक रेलवे ट्रैक्स पर मैनुअल स्केवेंजिंग का काम चलता रहेगा. दरअसल, स्वच्छ भारत अभियान इन सफ़ाई कर्मियों को नज़रअंदाज करके सफल नहीं हो सकता.

बहरहाल, भीम यात्रा अंतिम चरणों में है. इस यात्रा का नारा है, हमारी हत्याएं बंद करो! इसमें कोई शक नहीं कि 21वीं सदी में इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है. भारत भी बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया, चांद एवं दूसरे ग्रहों पर जाने की बात कर रहा है, वहीं एक ऐसी अंधकारमय दुनिया भी है, जो सबके सामने रहते हुए भी सबकी आंखों से ओझल है. इस दुनिया में एक इंसान अपने सिर पर किसी दूसरे इंसान का मल ढोता है. सबसे दुःखद बात यह है कि चिंता तो सब जताते हैं, लेकिन इस प्रथा के उन्मूलन के लिए कोई कुछ नहीं करता. भीम यात्रा के आयोजक कहते हैं कि उनकी बस जहां भी गई, वहां वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने उनका खूब स्वागत किया, लेकिन समाज के दूसरे वर्गों में उनके प्रति घोर उदासीनता दिखी. जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सदस्य केसी त्यागी ने एक बहुत अच्छी बात कही. उन्होंने कहा कि बेवजह की बातों पर दर्जनों बार संसद स्थगित होती है. एक दिन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य कसम खाएं कि इस विषमता के विरुद्ध, इस शोषण के विरुद्ध एक दिन संसद ठप रहेगी. त्यागी का बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि शायद इसी वजह से इस अमानवीय प्रथा के प्रति आम लोगों में कुछ जागरूकता पैदा हो. ■

मैला सफाई से जुड़े लोगों की कुल संख्या

क्रमांक	राज्य	मैला ढोने वाले	सेप्टिक टैंक की सफाई	रेलवे ट्रैक की सफाई	सीवर लाइन की सफाई	कुल
1	उत्तर प्रदेश	6,289	411	93	269	7,062
2	बिहार	1,133	2,337	63	50	3,583
3	राजस्थान	818	30	2	21	871
4	उत्तराखंड	493	385	19	71	968
5	जम्मू-कश्मीर	178	41	0	5	224
6	ओडिशा	82	2,332	24	234	2,672
7	पश्चिम बंगाल	48	31	0	1,728	1,807
8	हिमाचल प्रदेश	28	101	0	0	129
9	असम	22	135	18	0	175
10	पंजाब	98	12	2	5	117
11	झारखंड	28	153	0	7	188
12	महाराष्ट्र	82	1	8	2,500	2,591
13	गुजरात	4	0	0	0	4
14	छत्तीसगढ़	1	253	24	1	279
15	मध्य प्रदेश	461	536	14	56	1,067
16	नगालैंड	0	22	0	0	22
17	कर्नाटक	0	44	0	2,657	2,701
18	हरियाणा	378	0	9	0	387
19	दिल्ली	22	0	0	8	30
20	तमिलनाडु	–	–	–	2,830	2,830
21	आंध्र प्रदेश	–	–	–	2,803	2,803
	कुल	10,165	6,824	276	13,245	30,510

नोट: सफाई कर्मचारी आंदोलन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सबूत के तौर पर दाखिल किए गए दस्तावेज मामलों का सारांश (रैंडम सर्वे).

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड में स्थानीय नीति लागू करने को लेकर उबाल

बाहरियों को तीर-धनुष लेकर खदेड़ेंगे भीतरी

झामुमो ने विधानसभा का बजट सत्र चलने नहीं दिया. 15 दिन का सत्र स्थानीयता के मुद्दे की वजह से हंगामे की भेंट चढ़ गया. विधानसभा में विरोधी दल के नेता एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ शब्दों में मुख्यमंत्री को कहा कि जब तक मुख्यमंत्री सदन में स्थानीयता के संबंध में घोषणा नहीं करेंगे और इसे लागू करने की तिथि के बारे में नहीं बताएंगे तब तक सदन को नहीं चलने दिया जाएगा.

झामुमो ने हिंसक कार्रवाई की खुली चेतावनी दी.

झाविमो ने कहा झारखंड का चक्का जाम कर देंगे.

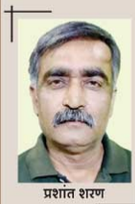

प्रशांत शरण

झारखंड में बाहरी बनाम भीतरी का मुद्दा फिर गरमा गया है. स्थानीय नीति लागू करने की मांग फिर से परवान चढ़ने लगी है और यह मसला उग्र रूप धारण करता दिख रहा है. एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन बाहरियों को झारखंड से भगाने के लिए तीर-धनुष उठाने की हिंसक चेतावनी दे रहे हैं तो दूसरी तरफ झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबू लाल मरांडी खनिज संसाधनों के निष्कासन को ठप्प करने और प्रदेश की नाकाबंदी करने का ऐलान कर रहे हैं. वहीं सत्तारूढ़ भाजपा स्थानीय नीति को लेकर उहापोह में है.

झारखंड में स्थानीयता की नीति ऐसी अबूझ पहेली बन गई है जिस पर हर सरकार हाथ डालने से हिचकती रही है, पर कोई भी राजनीतिक दल स्थानीयता को मुद्दा बनाने में पीछे नहीं रहना चाहती है और इसे जीवित रखने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना नहीं चाहती है. पार्टी जब सत्ता में आती है तो इसे लागू करने को लेकर खामोश हो जाती है और यही दल जब विपक्ष में आता है तो उसे स्थानीयता की याद सताने लगती है. भारतीय जनता पार्टी हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा, कोई भी इस मुद्दे को खत्म नहीं करना चाहता है ताकि वोट की राजनीति चलती रहे. कोई भी दल बाहरी या भीतरी किसी को नाराज़ किए बगैर स्थानीयता पर राजनीति की रोटी सेंकने का काम करती रहती है.

झारखंड में 65 प्रतिशत आबादी आदिवासी एवं मूलवासियों की है. आदिवासी एवं महतो वोट पर सभी दलों की नजरें रहती हैं. बाहरी लगभग 35 प्रतिशत हैं, पर राज्य की अधिकांश विधानसभा सीटों पर इनकी निर्णायक भूमिका रहती है. यही कारण है कि कोई भी राजनीतिक दल बाहरियों को भी नाराज़ नहीं करना चाहता. राज्य में कार्यरत 70 प्रतिशत से भी अधिक अधिकारी-कर्मचारी बाहरी हैं इस कारण प्रशासन पर भी बाहरियों की मजबूत पकड़ है. इसी वजह से मूलवासी एवं आदिवासी बाहरी लोगों का विरोध कर रहे हैं. इन लोगों का मानना है कि बाहरियों के कारण उनका हक मारा जा रहा है. स्थानीयता को लेकर झारखंड की सियासत में रुक-रुक कर गर्माहट आती रहती है. कोई भी राजनीतिक दल इस मुद्दे को समाप्त करना नहीं चाहता.

इस मामले को लेकर इस बार विपक्षी पार्टियां कुछ ज्यादा ही आक्रामक दिखीं. झामुमो ने विधानसभा का बजट सत्र चलने नहीं दिया. 15 दिन का सत्र स्थानीयता के मुद्दे की वजह से हंगामे की भेंट चढ़ गया. विधानसभा में विरोधी दल के नेता एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ शब्दों में मुख्यमंत्री को कहा कि जब तक मुख्यमंत्री सदन में स्थानीयता के संबंध में घोषणा नहीं करेंगे और इसे लागू करने की तिथि के बारे में नहीं बताएंगे तब तक सदन को नहीं चलने दिया जाएगा. हेमंत अपनी मांग पर अड़े रहे और सदन को चलने नहीं दिया. उन्होंने यहां तक कह दिया कि बाहरी को भगाने के लिए अगर तीर-धनुष का भी सहारा लेना पड़े तो उनकी पार्टी इसके लिए तैयार है. एक तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हिंसा की खुली चेतावनी दे डाली है. झामुमो की आदिवासी वोट बैंक पर शुरू से अच्छी पकड़ रही है और अब इसे दरकता देख स्थानीयता का मुद्दा उठाकर आदिवासियों को फिर से अपने पक्ष में करने में जुट गई है. झामुमो आदिवासियों को यह एहसास कराने में लगी है कि वह ही उनकी सच्ची हितैषी है. भारतीय जनता पार्टी भी आदिवासी वोट बैंक में सेंधमारी में लगी हुई है. वह दुमका सहित अन्य आदिवासी जिलों में कुछ ज्यादा ही सक्रिय दिखाई दे रही है. आदिवासियों पर पकड़ बनाने को लेकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी पर्दे के पीछे से भाजपा का हाथ मजबूत करने में लगा हुआ है. महतो (कुर्मी) जाति, जिसकी आबादी लगभग 40 प्रतिशत है, पर भाजपा की पकड़ पहले से ही मजबूत है और इसी वोट बैंक को लेकर दोनों प्रमुख पार्टियां स्थानीयता के मुद्दे को भंजाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं. दरअसल झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की दूरदर्शी नज़र इन्हीं वोटों पर थी और वे इसी वोट को अपना राजनीतिक आधार बनाना चाहते थे. वे किसी भी कीमत पर इस वोट बैंक को दरकने नहीं देना चाहते थे. इसी वजह से वे हमेशा विवादित बयान दिया करते थे. झारखंड के गठन के तुरंत बाद उन्होंने लोटा-सोंटा और झोंटा को राज्य से बाहर निकालने का नारा खुलेआम दिया था. वे यहां तक कहते थे कि मारवाड़ी, पंजाबी और बिहारी को लाठी डंडे से पीटकर बाहर भगा दो.

राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी जब सत्ता में आए और गठबंधन दलों के कारण जब उनकी ज़मीन खिसकती नज़र आई तो उनके सलाहाकारों ने उन्हें यह राय दी कि राज्य में डोमिसाइल लागू कर दीजिए और गठबंधन के नेता अगर उनकी बातें नहीं मानते हैं तो विधानसभा भंग कर चुनाव करा दें तो पार्टी को पूरा लाभ मिल जाएगा. मूलवासी के वोट से वे बहुमत की सरकार बनाने में सफल रहेंगे. सिपहसालारों की राय मानकर बाबूलाल मरांडी ने झारखंड को बारूद की ढेर पर ला खड़ा किया. उन्होंने इस नीति को लागू कर अपने हाथ जला लिए. इस मसले पर न केवल आदिवासी-गैरआदिवासी द्वंद्व हुए बल्कि यह हिंसा-प्रतिहिंसा में भी तब्दील हुई. झारखंड डोमिसाइल की आग में झुलस गया. इसके बाद सत्ता में आई सभी सरकारें इस विषय को छूने से हिचकती रहीं. इस पर केवल दिखावे के लिए दिलचस्पी जाहिर करती रहीं, लेकिन निर्णय लेने में टालमटोल की नीति अपनाती रहीं. ऐसा भी नहीं है कि स्थानीयता की नीति तय हो जाने से उच्च श्रेणी की नौकरियों पर कोई असर पड़ेगा या किसी को बहुत कुछ हासिल हो जाएगा. इसको किस तिथि से लागू किया जाए यह मसला वोट के हिसाब से अधिक संवेदनशील है, इस वजह से इस मुद्दे पर कोई राजनीतिक निर्णय नहीं लिया जा रहा है.

अब चूंकी सत्ताधारी दल के आधे से अधिक विधायक भी इसे मुद्दा बना रहे हैं और सत्ता में सहयोगी आजसू भी अपने लिए इसी आधार पर राजनीतिक आधार तलाशने के संकेत दे रही है तो राजनीतिक दल भी मानते हैं कि इस मसले को जितनी जल्दी निष्कर्ष तक पहुंचा दिया जाए उतना ही अच्छा होगा. वैसे, प्रदेश के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस नीति को लागू नहीं होने का सारा दोष विपक्ष पर मढ़ दिया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष अगर साथ दे एवं स्थानीयता पर अपने सुझाव दे तो इसे वह दो माह में ही लागू कर देंगे. लेकिन विपक्ष केवल इस पर राजनीति कर रहा है और भोले-भाले लोगों को गुमराह कर वोट की राजनीति कर रहा है. अगर उसे इतनी ही चिंता है तो वे इस मुद्दे पर गंभीरता से अपने सुझाव दे. हमारी पार्टी इसे लाने पर सहमत है. झामुमो पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन लोगों ने जिस तरह झारखंड आंदोलन को बेच डाला था उसी तरह ये स्थानीयता के मुद्दे पर भी सस्ती राजनीति कर रहे हैं.

झारखंड सरकार ने स्थानीयता की नीति तय करने के लिए प्रतिपक्ष सहित सभी दलों के साथ रायशुमारी की, लेकिन किसी भी दल ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई. राजनीतिक समीक्षक मानते हैं कि भाजपा सरकार बहुमत में है इसलिए उसे इस संवेदनशील विषय पर स्पष्ट निर्णय लेने में संकोच नहीं करना चाहिए. अन्य राज्यों में भी यह नीति लागू है, लेकिन झारखंड में इस विषय को जटिल बना दिया गया है. समीक्षकों की नज़र इस बात पर है कि भाजपा सरकार इस मुद्दे पर क्या चाल चलती है और विपक्षी दलों को कैसे मात देती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

बाहरियों को भगाने के लिए उठाएंगे तीर-धनुषः हेमंत सोरेन

झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता एवं विधानसभा में विरोधी दल के नेता हेमंत सोरेन के बाहरियों को लेकर तेवर आक्रामक हैं. हेमंत का मानना है कि बाहरी लोगों के कारण ही झारखंड की दुर्दशा हो रही है. उन्होंने कहा कि हर कानून झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों के खिलाफ बनाया जा रहा है. राज्य में जनता के लिए नहीं पूंजीपतियों और औद्योगिक घरानों के लिए हो रहा है, इसलिए राज्य से बाहरी लोगों को भगाना होगा. एक बार फिर तीर-धनुष उठाकर उलगुलान करना होगा. अगर राज्य सरकार स्थानीयता की नीति जल्दी लागू नहीं करती है तो महाजनी प्रथा हटाने के लिए जो आंदोलन हुआ था उससे भी उग्र आंदोलन पूरे राज्य में होगा. भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार स्थानीयता की नीति को लागू नहीं करना चाहती है. सरकार टाल-मटोल की नीति अपना रही है. सोरेन ने कहा कि भाजपा को इस बार बहुमत मिल गया है तो वह यह न सोचे कि वह जो चाहेगी कर लेगी. स्थानीयता की नीति के बनने से पहले यदि किसी भी पद के लिए बहाली प्रक्रिया शुरू की गई तो पूरे राज्य में उग्र आंदोलन चलाया जाएगा. यह पूछे जाने पर कि वे भी चौदह महीने सत्ता में रहे , तब उन्होंने स्थानीय नीति क्यों नहीं लागू की इस पर सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार बहुमत की नहीं थी, गठबंधन की सरकार थी, इस कारण वे स्थानीय नीति लागू नहीं कर सके. उन्होंने स्थानीयता की नीति को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. सभी दलों की राय भी ली थी, पर तब कुछ कारणों से नीति को लागू नहीं किया जा सका. इस नीति से संबंधित ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका था पर आदर्श आचार संहिता के लागू होने की वजह से इस पर फैसला नहीं लिया जा सका था. इस साल अगर भाजपा ने स्थानीय नीति लागू नहीं की तो विधानसभा के अगले सत्र को किसी भी हाल में नहीं चलने दिया जाएगा.

झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास पर हमला बोलते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री स्थानीय नीति लागू करने के लिए एक साल का समय इसलिए मांग रहे हैं ताकि इस बीच वे भारी संख्या में बाहरी लोगों की नियुक्ति कर सकें. मुख्यमंत्री पर भाजपा के शीर्ष नेताओं का भी दबाव है. भाजपा चार बार सत्ता में आ चुकी है पर वह इस नीति को लागू नहीं करना चाहती है. मुख्यमंत्री ने पहले तो 30 अप्रैल तक स्थानीय नीति बनाने की सदन में घोषणा भी कर दी थी, लेकिन अब वह टालमटोल कर रहे हैं. सोरेन ने कहा कि स्थानीय नीति के लागू होने तक मुख्यमंत्री को सारी नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित कर देनी चाहिए. उन्हें इसकी सार्वजनिक घोषणा करनी चाहिए क्योंकि वे झूठ बोलते हैं. आजसू के स्टैंड पर हेमंत ने कहा कि सुदेश महतो भी स्थानीयता पर घड़ियाली आंसू ही बहा रहे हैं. नियुक्ति परीक्षा में वे स्थानीय भाषा को लागू नहीं होने दे रहे हैं. आजसू की पृष्ठभूमि सबको मालूम है. वह मछली की तरह है जो बिना पानी के रह ही नहीं सकती. ■

मरांडी ने भी ठोकी ताल

झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबू लाल मरांडी ने घोषणा की है कि राज्य सरकार स्थानीय नीति लागू करे नहीं तो शीघ्र ही प्रदेशभर में नाकेबंदी शुरू कर दी जाएगी. मरांडी ने भाजपा, झामुमो और आजसू सभी को आदिवासियों और मूलवासियों का विरोधी बताया और कहा कि वे सभी एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं और वोटों की राजनीति के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं. मरांडी ने कहा कि झामुमो तीन बार और भाजपा दस साल से भी अधिक समय तक सत्ता में रही है पर अब तक किसी ने इन लोगों की सुध नहीं ली. अगर इन्हें आदिवासियों की थोड़ी भी चिंता रहती तो अभी तक राज्य में स्थानीय नीति बन जाती और इसका लाभ यहां के लोगों को मिल रहा होता. सत्ता में और प्रशासन में बाहरियों का ही बोलबाला है जो स्थानीय नीति के पक्षधर कभी नहीं हो सकते. सरकार केवल लोगों को गुमराह करने के लिए सर्वदलीय बैठकें बुलाती है, पर इसका नतीजा कुछ नहीं निकलता. मरांडी ने झारखंड सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि पंद्रह अप्रैल तक अगर राज्य सरकार ने स्थानीय नीति लागू नहीं की तो पूरे राज्य में नाकेबंदी शुरू की जाएगी. कोयला, लोहा, बॉक्साइट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का उठान नहीं होने दिया जाएगा. इसके बाद देखते हैं कि दिल्ली में बैठी सरकार झारखंड की जनता की बात कैसे नहीं सुनती है. उन्होंने कहा कि सरकार ने झारखंड को धर्मशाला बना दिया है. बाहरी लोग आ रहे हैं और उन्हें नौकरियां भी मिल रही हैं. औद्योगिक घरानों को आदिवासियों और गरीब मूलवासियों की जमीनें कौड़ियों के भाव दी जा रही हैं. यहां के मूलनिवासी भूमिहीन और गरीब होते जा रहे हैं जबकि बाहरी लोग अमीर और उद्योगपति. सीधे-सादे झारखंडियों को गुमराह किया जा रहा है. मरांडी कहते हैं कि उनकी पार्टी पूरे झारखंड में उग्र आंदोलन चलाकर लोगों को जागरूक करेगी, क्योंकि अगर अभी भी हमलोग नहीं चेते तो इसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतान पड़ेगा. मरांडी ने कहा कि चतुर्थ एवं तृतीय वर्ग की नियुक्ति केवल स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित हो, साथ ही अन्य पदों पर होने वाली बहाली प्रक्रिया पर भी रोक लगाई जाए, जब तक स्थानीय नीति लागू नहीं हो जाती. गौरतलब है कि मरांडी ने 2001 में डोमिसाइल लाने की कोशिश की थी. उन्होंने स्थानीय लोगों को खुश करने की रणनीति तो बनाई थी पर राज्य में इस मुद्दे को लेकर भारी उत्पात और हंगामा मचा था. इस वजह से स्थानीय नीति लागू नहीं हो सकी थी. मरांडी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था. भाजपा आलाकमान ने बाबूलाल मरांडी को हटाकर अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनाकर राज्य की कमान सौंप दी थी. ■

चंद्रशेखर जी के 90वें जन्म दिवस पर विशेष

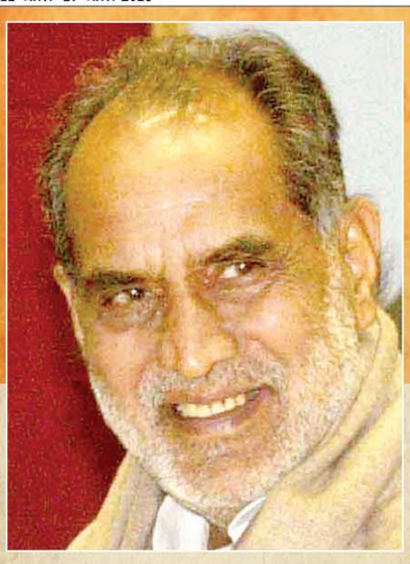

प्रधानमंत्री के रूप में चंद्रशेखर जी का राष्ट्र के नाम प्रथम संदेश

मेरे देश के लोगों! आप आज की शक्ति और कल की आशा हैं और इसलिए आपसे निवेदन करने के लिए मैं आया हूं. देश कठिनाई में है. सबसे बड़ी कठिनाई है कि हमारे लोगों का विश्वास टूट रहा है. देश की समस्याओं का समाधान अगर करना है, तो इस विश्वास को फिर से पैदा करना होगा. लोगों में हमें एक नए उत्साह, एक नए साहस की आवश्यकता है. इसी के सहारे कल का हिंदुस्तान बनेगा. अगर नया भारत बनाना है, तो पहला काम यह है कि हमें आपस में लड़ना बंद करना होगा. ग़रीबी, भुखमरी, बेकारी, बेरोज़गारी आज हमारे समाज को ग्रसित किए हुए है. कैसे हम इससे छुटकारा पा सकेंगे, यदि भाई–भाई से लड़ता रहेगा. आज आवश्यकता इस बात की है कि जो लोगों के बीच में तनाव है, आपस में जो कटुता है, उससे हम मुक्ति पाएं. भाई–भाई के खून का प्यासा हो, इससे बड़ी लज्जा की बात हमारे लिए और कोई नहीं है.

धर्म आदमी और भगवान में रिश्ता जोड़ने का एक साधन है. खुदा तक पहुंचने के लिए गर मज़हब का इस्तेमाल किया जाए, तो इसमें किसी को कोई द्वेष नहीं, कोई झगड़ा नहीं, लेकिन अगर मज़हब का इस्तेमाल धर्म की मान्यताओं को भाई–भाई में दुश्मनी पैदा करने के लिए किया जाए, तो इससे बढ़कर कोई अपराध नहीं होगा. मैं चाहता हूं कि भारत, जो हज़ारों वर्षों से सभ्यता और संस्कृति का, तहज़ीब और तम्मदुम का मरकज़ रहा है, केंद्र रहा है, वहां पर मानवता में आपसी भाई–चारे का एक नया व्यवहार पैदा हो. धर्म मनुष्य में मोहब्बत और स्नेह पैदा करने के लिए है, कटुता और बैर–भाव पैदा करने के लिए नहीं है. राज्य की ओर से सभी धर्मों को समान अवसर और समान सम्मान मिलेगा, लेकिन धर्म के नाम पर यदि किसी के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की जाएगी, तो विवशतावश हमें सरकार की शक्ति का उपयोग इसलिए करना होगा कि किसी के मन में आशंका, भय या कटुता पैदा न हो. मुझे विश्वास है कि जिस देश में कभी एक बार कहा गया था कि सब धर्मों की ओर से मनुष्य–मनुष्य बराबर है, वहां आपस में धर्म के नाम पर कटुता नहीं फैलाई जाएगी.

आज मस्जिद और मंदिर के नाम पर लोगों को लड़ाने की कोशिश हो रही है. आप जानते हैं कि मंदिर और मस्जिद में जो भगवान बसता है, वह भगवान मनुष्य की पीड़ा को दूर करने का संदेश देता है. तभी कहा गया था कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गिरजे के आसपास में, ढूंढ ले कोई राम मिलेगा, दीन–जनों की भूख प्यास में.

आज हमें रिश्ता इन ग़रीबों की भूख–प्यास से जोड़ना होगा. हमारे लिए तो लज्जा की बात है, दुःख की बात है कि जिस देश में प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है, यह धरती जो उपजाऊ है, यह जलवायु जो दुनिया में हर तरह की जलवायु का मुक़ाबला कर सकती है, यह हमारे खनिज पदार्थ और सबसे बढ़ करके हमारे करोड़ों लोगों की बाहों की ताकत, जिसके बल पर हम इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं, लेकिन क्या कारण है कि आज हम अपने में बेबसी और उदासी का अनुभव करते हैं. गुलामी के दिनों में इस निर्धन देश के लोगों ने एक बड़े साम्राज्यवाद का मुक़ाबला किया था. उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था. ना फौज थी, ना पुलिस थी, ना सरकारी खजाना था. विगत वर्षों की आज़ादी में हमारे पास सब कुछ है, फिर भी यह विवशता क्यों? यह विवशता इसलिए है कि जनशक्ति, जो हमारा सबसे बड़ा साधन है, जो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, उस जनशक्ति का उपयोग हम देश के विकास में नहीं कर सके. जनशक्ति का उपयोग करने के लिए एक नया माहौल, एक नया वातावरण बनाना होगा. किसी भी लोकतंत्र में, जम्हरियत में यह ज़रूरी है कि लोगों के मन में यह विश्वास पैदा किया जाए कि अपनी मेहनत से जो कमाई करेंगे, वह कमाई चंद लोगों की खुशहाली के लिए नहीं, करोड़ों बच्चों की बेबसी को मिटाने के लिए की जाएगी.

आज हमारा किसान और मज़दूर, आज हमारा ग़रीब, उनके मन में पीड़ा है, एक दर्द है. वे समझते हैं कि उनकी मेहनत के बावजूद भी उनके बच्चों के लिए कोई सुनहरा सवेरा नहीं और दूसरी तरफ़ चंद लोगबाग वैभव की ज़िंदगी बिताते हैं. मुझे किसी के धन से कोई दुश्मनी नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, लेकिन मैं एक बात बड़ी नम्रता से कहना चाहूंगा कि अगर चारों ओर ग़रीबी का समुद्र हिलोरें ले रहा हो, तो वैभव के टापू बहुत दिनों तक नहीं रह सकते.

इसलिए गांधी और बुद्ध के इस देश में हम चाहते हैं कि एक बार सब सीखें–बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय के नारे को हम आत्मसात करें. यदि हमें करना होगा, तो ग़रीब की ज़िंदगी में एक नई रोशनी लानी होगी. अगर हर बच्चे को जीने का अधिकार देना होगा, तो जो बच्चा दुनिया में आता है, उसे इस बात का अधिकार है कि उसे पीने के लिए स्वच्छ पानी तो मिले. कम से कम इतना खाना तो मिले कि वह शक्तिशाली बन सके, जीवित रह सके. उसे प्रारंभिक शिक्षा मिले, बीमार पड़े तो दवा–दारू का इंतज़ाम हो. अगर हर बच्चे को मिल जाए, तो एक स्वस्थ नागरिक वह बन जाएगा. लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि जाति और धर्म के नाम पर, भाई–भाई, आदमी–आदमी के बीच में विभेद किया जाता है. जाति और धर्म के नाम पर विभेद मिट जाए, तो ये करोड़ों लोग, जो आज देश के अंदर हैं, इनके सहारे एक नया हिंदुस्तान बन जाएगा. इन करोड़ों लोगों की आत्मशक्ति को, संकल्प–शक्ति को जगाने का काम हमारा और आपका है. इसलिए जब हम इनकी शक्ति को जगाने की बात करते हैं, तो बरबस हम यह कहने के लिए विवश होते हैं कि जो आज धनवान हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास सुख–संपत्ति है, वे गांधी को याद करें. मितव्ययिता का नारा, सादगी का जीवन, यह केवल नारा नहीं था. करोड़ों लोगों के मन में एक नया यकीन पैदा करने के लिए, एक नया विश्वास पैदा करने के लिए यह एक ऐसा रास्ता था, जिस रास्ते में हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं.

मैं जानता हूं, आज देश की आर्थिक हालत खराब है. मैं जानता हूं, आज कई कठिनाइयों से हम घिरे हुए हैं, लेकिन लोगों के मन में यह विश्वास होना चाहिए कि हमारे देश में एक ऐसी शक्ति भी है, जिसके सहारे इस कठिनाई से हम पार पा सकते हैं. पिछले कुछ दिनों में दुनिया के सामने ऐसा कहा गया, जैसे भारत बेबस हो. ऐसा कहा गया, जैसे हमारे पास कोई रास्ता नहीं हो. आज हमें एक नया संकेत देना पड़ेगा, हमें दुनिया से यह कहना पड़ेगा कि भारत अपने पैरों पर स्वावलंबन और स्वदेशी के नारे को लेकर फिर खड़ा हो सकता है. मैं मानता हूं, आज की दुनिया में दूसरों का सहयोग चाहिए, सहायता चाहिए. वह सहयोग और सहायता हम लेंगे, लेकिन हमें तो विशेष रूप से अपने ही बल पर, अपने ही पौरुष के सहारे आगे बढ़ना पड़ेगा.

मुझे विश्वास है कि देश के उद्योगपति, देश के व्यापारी और देश से बाहर रहने वाले भारतवासी, जिनमें उतना ही देश–प्रेम है, जितना हम में. वे आज की हालत में हमारी सहायता करने के लिए तैयार होंगे. सहायता केवल पैसे की नहीं चाहिए, सहायता केवल धन की नहीं चाहिए. हम सबको मिल करके एक नया भारत बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एक–दूसरे से सहयोग करना पड़ेगा. सहयोग और सद्भावना के इसी वातावरण में हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं.

आज दुर्दिन से हमारे देश में जगह–जगह झगड़े हैं, कलह है, पंजाब में पीड़ा है, कश्मीर कराह रहा है, असम में आतंकवाद का एक नया दौर शुरू हो रहा है, तमिलनाडु में भी लोग परेशान हैं. इसका अंत होना चाहिए. मैं देश के लोगों से यह कहना चाहूंगा कि मौत, मौत है, चाहे मौत किसी आतंकवादी की गोली से हो या पुलिस की गोली से हो. गोली चलाना बंद होना चाहिए. अहिंसा का नारा, शांति का नारा, भाई–चारे का नारा, जो हमारी विरासत है, उसे इस देश में लागू होना चाहिए. मैं उन सारे लोगों को, जो एक कारण से या दूसरे कारण से, चाहे जो भी वजह है, अगर दुःखी हैं, नाराज़ हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि नाराज़गी को दूर करें. यह व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सम्मान और इज्जत का सवाल नहीं है, यह मुल्क के मुस्तकबिल का, इस भारत के भविष्य का सवाल है. पंजाब के नौजवानों से, कश्मीर के नौजवानों से मैं कहना चाहूंगा कि हथियार रख दें और प्रेम और शांति के रास्ते से समस्याओं का समाधान करें. सरकार उनसे हर तरह से बातचीत करने के लिए, उनसे नई राह ढूंढने के लिए तैयार है. लेकिन एक बात याद रखें कि इस भारत भूमि की अखंडता के सवाल पर, इसकी सार्वभौमिकता के सवाल पर, इसके गौरव के सवाल पर कोई सहयोग करना न उचित होगा, न हमारे लिए संभव होगा. इसलिए मैं उन सारे नौजवानों से, जिनके अंदर शक्ति है, पुरुषार्थ है, निवेदन करूंगा कि आज के बाद यदि हम कोई ऐसा माहौल बनाएं, ऐसा कोई क़दम उठाएं, जिससे हम लोग शांति से रह सकें, तो फिर आपसी बातचीत के सहारे कोई रास्ता निकल सकता है.

मैं आपका ध्यान एक ओर ले जाना चाहूंगा. आज अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के सवाल को लेकर विवाद खड़ा है. राम हमारी सभ्यता और संस्कृति के एक महान व्यक्तित्व हैं. उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा है. हम सब लोग उनको एक व्यक्ति के रूप में नहीं, एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में याद करते हैं. राम की जन्मभूमि में मर्यादा का निर्माण होना चाहिए. हमें बड़ी प्रसन्नता होगी, यदि राम के मंदिर को भव्य रूप में हम बनाएं. सब लोगों को मिल करके अपनी सभ्यता और संस्कृति की इस धरोहर को संजोने के लिए, उसकी स्मृति को बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए. मंदिर बने, लेकिन किसी दूसरे पूजा स्थल को गिरा करके नहीं. मैं उन सारे लोगों से, जो आज राम मंदिर के लिए आंदोलन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आप बड़ा मंदिर बनाएं, लेकिन मस्जिद न टूटे, तो आप देश के साथ उपकार करेंगे. आप उस सब भावना को अक्षुण्ण रखेंगे, जो हिंदू धर्म की सबसे बड़ी धरोहर है. यदि हिंदू और मुसलमान मिल करके किसी एक फैसले पर पहुंच जाएं, तो सरकार को इससे बढ़कर कोई प्रसन्नता नहीं होगी. लेकिन किसी दूसरे की भावना को, उनके जज्बातों को ठेस लगाकर अगर राम का मंदिर बने, तो न यह मर्यादा के अनुरूप होगा और न धर्म की मान्यताओं के अनुरूप होगा. मेरा विश्वास है कि इस मामले का हल हम सद्भावना और आपसी बातचीत से निकालेंगे. इससे तनाव पैदा करना, इससे कोई कठिनाई का दुराव पैदा करना न देशहित में होगा और न धर्म की मर्यादाओं के अनुरूप होगा.

मुझे विश्वास है कि हमारे देश के लोग दूसरे सवालों पर भी ग़ौर करेंगे. आज ग़रीब लोगों के सवाल को लेकर, पिछड़े लोगों के सवाल को लेकर आपस में टकराव का एक माहौल बना हुआ है. यह हमारा दुर्भाग्य है कि जाति प्रथा एक ऐसी प्रथा है, जो पिछले सैकड़ों वर्षों से हमारे समाज में एक विभेद पैदा करती रही है. यह सही है कि जो लोग पिछड़े हैं, दुर्भाग्यवश उसमें ही से अधिक लोग ग़रीब हैं. यदि जाति के नाम पर कोई आरक्षण होता है, तो उस पर नाराज़गी नहीं होनी चाहिए. लेकिन जिस तरह से आर्थिक विकास हुआ है, उसमें दूसरे वर्ग के लोगों में भी ग़रीब लोग हैं, उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखना होगा. अगर अशांति होती है, अराजकता होती है, तो उससे ग़रीब ही परेशान होता है. ग़रीब, ग़रीब है, चाहे वह किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो और ग़रीबी को मिटाने के लिए सभी ग़रीबों को मिलकर एक साथ काम करना पड़ेगा. अगर हम आपस में लड़ेंगे, तो ग़रीबी से नहीं लड़ सकते. जैसे हम अपने देश के लिए बातें कर रहे हैं, उसी तरह हम यह कहना चाहेंगे कि यह पूरा उपमहाद्वीप एक ग़रीबी का इलाका है. अगर हम आपस में लड़ेंगे, तो ग़रीबी के ख़िलाफ़ जेहाद नहीं बोल सकते. चाहे वे हमारे पड़ोसी देश हों. इस सारे हिस्से में हमको एक–दूसरे से दोस्ती रखनी होगी. हमारी सरकार पूरी कोशिश करेगी कि दुनिया के सब देशों से सहयोग करे, लेकिन ख़ास तौर से अपने पड़ोसियों के साथ हम मित्रता का व्यवहार रखेंगे. उनके साथ हम मिलजुल कर एक कोशिश करेंगे एक नया माहौल बनाने के लिए, जो न केवल इस इलाके के लिए उपयोगी हो, बल्कि शांति के रास्ते पर सारी दुनिया को ले जाने के लिए एक नई राह दे सके. हमें दुःख है कि आज दुनिया में फिर से टकराव की हालत पैदा हो रही है. फिर लड़ाई के लिए नया माहौल बन रहा है. अच्छा होता कि जो लड़ाई की ओर जा रहे हैं, वे पीछे हटें. अमन और शांति के रास्ते से ही मानवता को हम आगे बढ़ा सकते हैं. इस बड़े काम में हमको सबका सहयोग चाहिए. जिनकी भी पार्टियां हैं, उनसे मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप ही के सहारे इस देश को बनाना है. ग़रीबी, भूख, प्यास के ख़िलाफ़ एक नया अभियान चलाना है. आप सब लोगों के सहकार, सहयोग से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इस देश को फिर उस गौरव की ओर ले जा सकेंगे, जो इसके इतिहास की परंपरा रही है. आप और हम, आइए मिलकर साथ काम करें और आपके सहारे एक उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ें. भारत को दुनिया में वही स्थान दिला सकें, जिस स्थान के योग्य भारत हमेशा से रहा है.

यहां तरह–तरह के धर्मों के लोग हैं, तरह–तरह की ज़ुबान बोलते हैं, भारत के चमन में तरह–तरह के फूल खिले हैं. हम चाहते हैं कि इस चमन की हर कली मुस्कराए, इसके कूंचे–कूंचे में बहार आए, अगर एक कली भी मुरझा गई, तो इसमें बहार नहीं आएगी. आइए, हम अपने ख़ून–पसीने से धरती को नई ताकत दें, इसकी हर कली मुस्कराए, जिसकी ख़ुशबू से न केवल देश, बल्कि सारी दुनिया महक उठे. इस बड़े काम में हमें आप सबका सहयोग चाहिए. आपसे यही आशीर्वाद, आपसे यही सहकार, यही सहयोग पाने के लिए मैं आपके बीच आया हूं. मुझे विश्वास है, आपका सहकार, सहयोग मुझे मिलेगा.

बहुत–बहुत धन्यवाद

जयहिंद.

(17 नवंबर, 1990)

चंद्रशेखर जी की आत्मकथा चंद्रशेखर जी के खुद के लिखे इस पत्र से शुरू होती है.

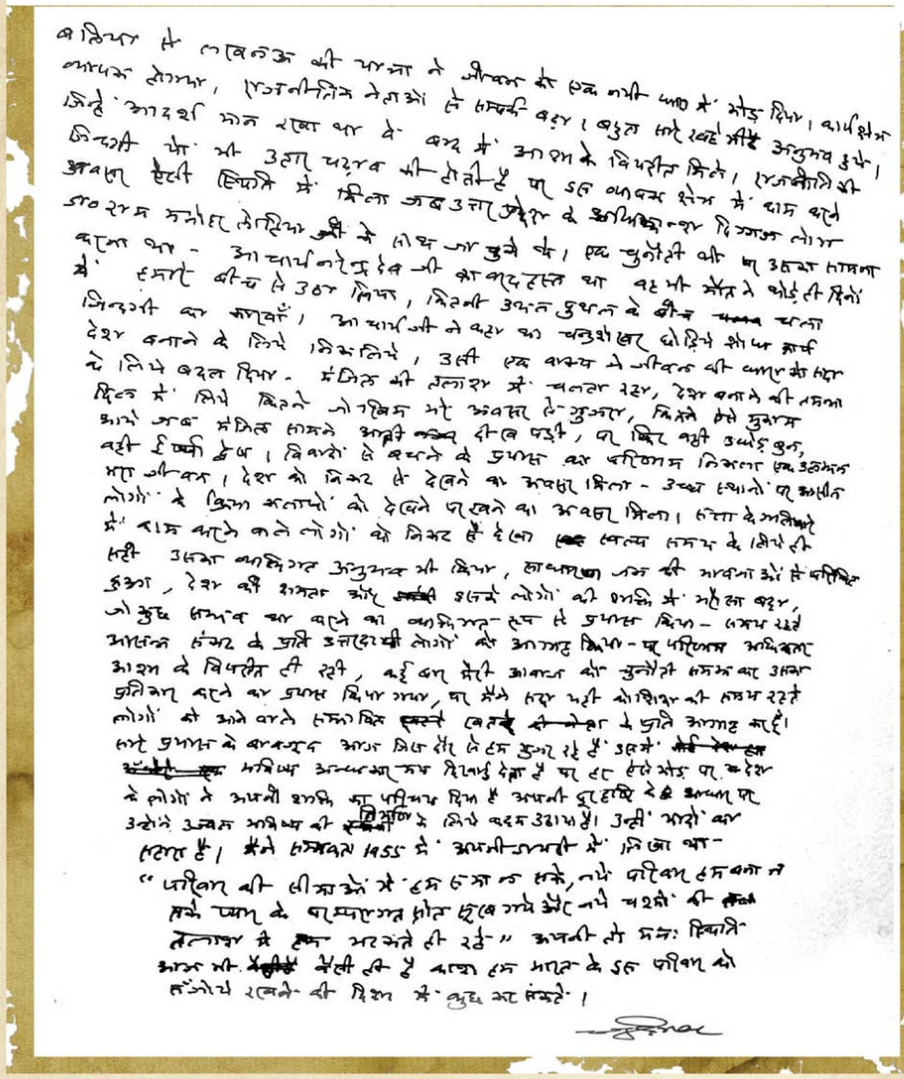

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

चंद्रशेखर होने का मतलब

17 अप्रैल को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर का 90वां जन्मदिन है. चंद्रशेखर जी को लोग भूतपूर्व प्रधानमंत्री के नाते नहीं जानते और न भूतपूर्व प्रधानमंत्री कहने से चंद्रशेखर जी का सम्मान बढ़ता है. चंद्रशेखर की ज़िंदगी में जो करिश्मे हुए, वे उन्होंने खुद किए. बलिया के एक छोटे-से गांव इब्राहिम पट्टी में पैदा हुए, मीलों पैदल चलकर स्कूल गए. इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति की. समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हुए और अपनी बेबाकी, निर्भीकता एवं अक्खड़पन की वजह से सारे देश में जाने गए. चंद्रशेखर जी ने मुझे अपनी ज़िंदगी के उत्थान-पतन के बहुत सारे किस्से सुनाए और उन किस्सों को सुनकर मेरे मन में चंद्रशेखर जी की जो छवि बनी, वह एक ऐसे महानायक की थी, जिसने ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी, जो हमेशा लोगों के लिए लड़ा और जिसके लिए सत्ता या सत्ताधीश जनता की तकलीफें दूर करने का साधन तो थे, पर साध्य नहीं थे.

आज हमारा देश जहां खड़ा है, खासकर आर्थिक नीतियों के चलते हर वर्ग परेशान है. जो पैसा कमाने वाला वर्ग है और जिसे हम कॉरपोरेट्स कहते हैं, वह भी दु:खी है. जो देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ रखने में हमेशा सबसे आगे रहा यानी इस देश का किसान वर्ग, वह भी दु:खी है. इस दु:ख और अर्थव्यवस्था के रास्ते को, अगर चंद्रशेखर जी होते, तो कैसे सुधारते, यह सवाल मन में बार-बार उठता है. दरअसल, जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, उस समय की लोकसभा में हुआ आपसी संवाद इस समस्या को समझने का एक रास्ता देता है.

नरसिम्हा राव सदन में प्रधानमंत्री के स्थान पर बैठे थे और उनके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह नई आर्थिक नीतियों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे. उन्होंने देश को बताया कि अब हम जो आर्थिक नीतियां लागू करने जा रहे हैं, उनसे अगले बीस वर्षों में देश में ग़रीबी घटकर 30 से 35 प्रतिशत रह जाएगी, सबको बिजली मिल जाएगी, सबको सड़क मिल जाएगी, सबको पानी मिल जाएगा और हम महाशक्ति बनने के रास्ते पर चल निकलेंगे. सत्तारूढ़ दल ने मेजें थपथपा कर उनका स्वागत किया. सदन में भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी बैठे थे. चंद्रशेखर जी खड़े हुए और उन्होंने कहा, मनमोहन सिंह जी ने जो भाषण दिया है, वह बीस वर्ष बाद की जो तस्वीर पेश कर रहा है, मैं उससे बिल्कुल अलग तस्वीर देख रहा हूं. बीस वर्ष बाद इस देश में ग़रीबी बढ़ जाएगी, असमानता बढ़ जाएगी, लोग अपने हक़ों के लिए शायद हथियार उठाने लगेंगे. न देश को बिजली मिलेगी, न पानी मिलेगा पीने के लिए, सिंचाई के लिए तो होगा ही नहीं. मैं वित्त मंत्री की दी हुई तस्वीर से बिल्कुल उलट तस्वीर देखता हूं, जिससे मुझे डर है कि देश भटकाव या टूटन के रास्ते पर चल पड़ेगा. प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव उठे और चंद्रशेखर जी बैठ गए. नरसिम्हा राव जी ने कहा, चंद्रशेखर जी, जब आप प्रधानमंत्री थे, तो मनमोहन सिंह आपके वित्तीय सलाहकार थे और मैंने तो यह मान रखा था कि ये जो चीजें यहां कह रहे हैं, उसमें आपकी सहमति होगी और आप इनसे असहमति दिखा रहे हैं. चंद्रशेखर जी फिर खड़े हुए और उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी, मैंने आपको सब्जी काटने के लिए चाकू दिया था, लेकिन आप तो उस चाकू से दिल का ऑपरेशन करने लगे. पूरा सदन ठहाका मारकर हंस पड़ा, लेकिन चंद्रशेखर जी के इस तीखे व्यंग्य ने बीस वर्ष बाद की तस्वीर क्या होगी, यह साफ़ कर दिया. और, आज बीस वर्षों के बाद देश की तस्वीर, जिसकी ओर चंद्रशेखर जी ने इशारा किया था, उससे ज़्यादा खराब है.

आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था दिशाहीन है और इसकी गवाही दुनिया के अर्थशास्त्री तो देते ही हैं, हमारे खुद के रिजर्व बैंक गवर्नर इसके सबसे बड़े चश्मदीद गवाह हैं. नतीजे के तौर पर बहुत सारे उद्योग बैठ गए हैं, बहुत सारे सेक्टरों को पुनर्जीवित करने का कोई रास्ता सरकार के पास नहीं है. सरकार जिस तरह का बजट ला रही है, उससे देश के 80 प्रतिशत लोगों की ज़िंदगी में कोई बदलाव होने वाला नहीं है. यह सरकार अर्थव्यवस्था में कोई भी बुनियादी परिवर्तन नहीं करना चाहती और इसी का परिणाम है कि जिस एनपीए को सरकार 1.14 लाख करोड़ रुपये बता रही है, दरअसल वह कुल मिलाकर 18 लाख करोड़ रुपये के आसपास है.

उस अर्थव्यवस्था, जिसका ज़िक्र मनमोहन सिंह ने नरसिम्हा राव के समय किया था और जिसे मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार अक्षरश: अपनाए हुए है, ने इस देश के सारे पब्लिक सेक्टर को बर्बाद कर दिया है. अटल जी की सरकार ने तो

आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था दिशाहीन है और इसकी गवाही दुनिया के अर्थशास्त्री तो देते ही हैं, हमारे खुद के रिजर्व बैंक गवर्नर इसके सबसे बड़े चश्मदीद गवाह हैं. नतीजे के तौर पर बहुत सारे उद्योग बैठ गए हैं, बहुत सारे सेक्टरों को पुनर्जीवित करने का कोई रास्ता सरकार के पास नहीं है. सरकार जिस तरह का बजट ला रही है, उससे देश के 80 प्रतिशत लोगों की ज़िंदगी में कोई बदलाव होने वाला नहीं है. यह सरकार अर्थव्यवस्था में कोई भी बुनियादी परिवर्तन नहीं करना चाहती और इसी का परिणाम है कि जिस एनपीए को सरकार 1.14 लाख करोड़ रुपये बता रही है, दरअसल वह कुल मिलाकर 18 लाख करोड़ रुपये के आसपास है.

पब्लिक सेक्टर्स को बेचना शुरू किया था. अब नए सिरे से फिर उन्हें बेचने की बात भारत सरकार कर रही है. सरकारी बैंकों से रुपया कैसे लूटा जाए, रुपया लूटकर उसे कैसे विदेश भेजा जाए और फिर खुद भी विदेश निकल लिया जाए, यही सब करने वाला वर्ग मौजूदा अर्थव्यवस्था या मौजूदा सरकार के दौर में सुखी है, खुश है. मैं मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा. मैं आरोप लगा रहा हूं, उन नीतियों के ऊपर, जिन्हें मनमोहन सिंह ने शुरू किया था और नरेंद्र मोदी अक्षरश: अपनाए हुए हैं.

अगर आज चंद्रशेखर जी होते, तो वह मौजूदा प्रधानमंत्री के घोषित किए हुए कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने के बजाय सबसे पहले देश के सबसे बड़े औद्योगिक संसाधन कृषि के ऊपर ध्यान देते. वह कृषि क्षेत्र की समस्याओं का राजनीतिक हल नहीं, बल्कि आर्थिक हल निकालते. चंद्रशेखर जी यह हल निकालते कि किसान कैसे पैदावार ज़्यादा करे, कैसे पैदावार का उसे पूरा मूल्य मिले, वह कैसे खुशहाल हो और किस तरह गांव में रहने वाले लोग बिना शहरों पर बोझ पड़े, एक नए संपूर्ण उद्योग के क्षेत्र में स्वयं को ट्रांसफॉर्म कर लें. चंद्रशेखर जी होते, तो वह देश के बैंकों को मजबूत करते, न कि उन्हें क्षमादान देते, जो 18 लाख करोड़ रुपये लेकर देश से भाग गए. हज़ारों लोग बैंकों से पैसा लेकर देश से बाहर चले गए हैं और मौजूदा सरकार के पास ऐसा कोई साधन नहीं है, जिससे पता चल सके कि कितने लोग पैसा लेकर देश से बाहर चले गए हैं. पहले एक योजना आयोग हुआ करता था, जो इन सारी चीजों के ऊपर नज़र रखता था और उत्पादन से लेकर संपत्ति के विभिन्न समूहों में बंटवारे तक के सर्वे कराकर जानकारी एकत्र रखता था. अब नीति आयोग है, अवश्य कुछ कर रहा होगा, लेकिन देश को नहीं पता कि नीति आयोग क्या कर रहा है? नीति आयोग का कोई भी ऐसा अध्ययन अब तक सामने नहीं आया, जिससे देश को पता चले कि हमारे आर्थिक संसाधनों का जमाव कहां हो रहा है, वे देश से सायफन कितने हो रहे हैं? चंद्रशेखर जी अगर आज होते, तो वह बैंकों को मजबूत करने और उन्हें यह अधिकार देने पर अवश्य ज़ोर देते कि जिसने भी बैंकों से 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा का कर्ज लिया है, बैंक उसकी जांच करें कि वह अपना काम ठीक ढंग से कर रहा है या नहीं. चंद्रशेखर जी बाज़ारू अर्थव्यवस्था के ख़िलाफ़ थे, मुक्त अर्थव्यवस्था के ख़िलाफ़ थे, लेकिन अगर मुक्त अर्थव्यवस्था विश्व में आगे बढ़ने के लिए अवश्यंभावी है और यही बुनियादी शर्त है, तो चंद्रशेखर जी उसे लागू करने से पहले उन सारे उपायों का अध्ययन करते, जिनसे देश का पैसा बाहर जाने का मार्ग बंद होता. चंद्रशेखर जी शायद देश से पैसा विदेश में सायफन करने को देशद्रोह की श्रेणी में लाते और उन सारे पूंजीपतियों को, पैसे वालों को, जो देश का पैसा विदेश ले जाते हैं, देशद्रोही करार देते और उनके ऊपर देशद्रोह का मुक़दमा चलवाते. और, अगर वह विपक्ष में होते, तो सरकार के ऊपर दबाव डालते कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ देशद्रोह का मुक़दमा चले.

चंद्रशेखर होने का मतलब देश के ग़रीब और वंचित व्यक्ति के लिए प्राथमिकता से सोचना होता है. चंद्रशेखर होने का मतलब देश को केंद्र में रखना, देश को फासिस्ट टर्मिनोलॉजी में परिभाषित न करना, बल्कि देश को विकास के सही अर्थ में परिभाषित करना होता है. चंद्रशेखर होने का मतलब इस देश के हर ब्लॉक में उद्योग-धंधों का जाल बिछाना होता है. और, वह चंद्रशेखर जी के मन की वह तड़प है, जो कई और राजनेताओं में भी होगी. लेकिन जिस त्वरा से, जिस जिजीविषा से, जिस हिम्मत से चंद्रशेखर जी इस सबके लिए लड़ते, वह आज की तारीख में किसी नेता में दिखाई नहीं देता. इसलिए आज की अर्थव्यवस्था का अंतर्विरोध चंद्रशेखर जी को स्मरण करने पर याद दिला जाता है कि 1991 में लोकसभा में जो चेतावनी उन्होंने दी थी, अगर उसका विश्लेषण करें, तो आज इससे निकलने का रास्ता मिल सकता है. अफ़सोस की बात यह है कि मौजूदा सरकार देश के उन सारे नेताओं के बारे में सोचना भूल गई है, जिन्हें सोचना हमारे लिए बहुत लाजिमी है. वह चंद्रशेखर और वीपी सिंह जैसों को तो भूल ही गई है, अटल बिहारी वाजपेयी को भी भूल गई है. वह यह सोचना भूल गई है कि क्यों अटल बिहारी वाजपेयी को देश के लोग अपना आदरणीय मानते थे. इसलिए देश के हित में सरकार अगर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में नए सिरे से सोचे, तो शायद हम इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएं. ■

editor@chauthiduniya.com

राजनीतिक हथियार के रूप में राष्ट्रवाद

मेघनाद देसाई

राष्ट्रवाद एक सरल कारण के चलते विवाद के नए क्षेत्र के रूप में उभरा है. कारण यह है कि भाजपा खुद को सभी के लिए न सिर्फ़ हिंदुओं के लिए एक पार्टी के रूप में पुनर्परिभाषित कर रही है. समावेशी विकास यानी सबका विकास जैसी नई थीम पर नरेंद्र मोदी आगामी चुनावों के लिए प्रचार करना पसंद करेंगे, लेकिन भाजपा नेताओं को यह रास नहीं आता, इसलिए राष्ट्रवाद का विवाद सामने है. ज़ाहिर है, यह क़दम हिंदू बहुसंख्यकवाद से दूर देश के अधिक तटस्थ क्षेत्र की ओर जा रहा है. राष्ट्रवाद इस हिसाब से और राजनीतिक रूप से एक चतुर चाल है. सिद्धांत रूप में यह देश हिंदू, मुस्लिम और अन्य सभी अल्पसंख्यकों के लिए है, लेकिन भाजपाई सिर्फ़ एक नए मंच की तुलना में कुछ और अधिक चाहते हैं. इसलिए वे भारत माता की जय जैसे नारे लगाने की बात कहते हैं. हम सभी जयहिंद कह सकते हैं और कोई भी मुस्लिम या ईसाई इस पर आपत्ति नहीं कर सकता है. लेकिन, भारत माता की जय का नारा वंदे मातरम की तरह है, जो मुसलमानों की पसंद के मुताबिक नहीं है. इसका कारण यह नहीं है कि वे भारत से प्यार नहीं करते. उनके लिए जयहिंद या हिंदुस्तान ज़िंदाबाद ठीक नारा रहेगा. भारत माता की जय का नारा एक देवी को सम्मान देता है, जबकि इस्लाम में सिर्फ़ एक ही देवता है, अल्लाह.

यह भी अन्य दलों, खासकर कांग्रेस के लिए एक जाल में फंसने जैसा है. कांग्रेस मानती है कि भाजपा पर हिंदू लेबल का दाग़ है, लेकिन अब भाजपा ने खेल बदल दिया है. महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस विधायक उसके जाल में घिर गए और ज़ोर देते हैं कि हर किसी को भारत माता की जय कहना चाहिए और वे इस मुद्दे पर भाजपा एवं शिवसेना के साथ हो गए हैं. भाजपा के लिए कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि माकपा या भाकपा क्या करती है. वह सिर्फ़ कांग्रेस को नीचा दिखाना चाहती है. जैसे-जैसे भाजपा आगे बढ़ रही है, कांग्रेस क्षीण होती जा रही है. उसने पिछले कुछ वर्षों में वैचारिक तीखापन खो दिया है और वह सिर्फ़ सत्ता के लिए काम कर रही है. कोई भी कांग्रेस की सदस्यता इसलिए नहीं ले रहा है कि उसे देश की सेवा करनी है. यह बात हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे अभियान में देख सकते हैं. कांग्रेस ने अपने चुनाव सलाहकार के रूप में प्रशांत किशोर को चुना है,

क्योंकि उन्होंने पहले नरेंद्र मोदी की मदद की और उसके बाद नीतीश कुमार को चुनाव जिताया. प्रशांत किशोर ने प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में 25 स्वयंसेवकों की शर्त रखी है, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है. कोई भी स्वयंसेवक नहीं बनना चाहता है. लगता है, सब एक टिकट भर चाहते हैं. और, क्यों कोई कांग्रेस में शामिल होगा?

यह वर्ष कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है. अगर वह असम या केरल जीतने में असफल होती है, तो उसका अवसान शुरू हो जाएगा. असम के लिए यह बात खासकर लागू होती है, जहां तरुण गोगोई चौथी बार मुख्यमंत्री पद पाने की उम्मीद कर रहे हैं. चूंकि राष्ट्रीय नेतृत्व एक परिवार के बीच सिमटा हुआ है. इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी शख़्स गंभीर महत्वाकांक्षा पालकर कांग्रेस में नहीं रह सकता. अगर कांग्रेस राज्य स्तर पर सत्ता बनाए रखने में विफल रहती है, तो प्रतिभाशाली कांग्रेस नेताओं के लिए एक स्पष्ट संदेश जाएगा. संदेश यह कि वे अपनी खुद की कांग्रेस पार्टी बनाएं. विखंडन सिर्फ़ आसपास है, जब तक कांग्रेस फिर से लोकप्रिय न हो जाए. कांग्रेस ने अपने मतदाताओं का पुराना गठबंधन खो दिया है, अब युवा कांग्रेस के साथ नहीं हैं. राहुल गांधी एक रणनीति विकसित कर रहे हैं. वह हर उस जगह जा रहे हैं, जहां समस्या है और फिर उसके लिए मोदी को दोषी ठहरा देते हैं. एक छोटे विपक्षी दल के लिए यह भावना बहुत काम की है, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए इसके ख़तरे भी हैं. जैसा कि हमने जेएनयू प्रकरण में देखा. अगर राहुल गांधी सीपीएम के युवा मतदाताओं का दिल जीतने के लिए गए थे, तो कांग्रेस एक संकरी गली में बंद होकर व्यापक मतदाता गठबंधन खो सकती है. कांग्रेस को अपने ब्रांड वाला राष्ट्रवाद लेकर आगे आना होगा. ■

यह वर्ष कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है. अगर वह असम या केरल जीतने में असफल होती है, तो उसका अवसान शुरू हो जाएगा. असम के लिए यह बात खासकर लागू होती है, जहां तरुण गोगोई चौथी बार मुख्यमंत्री पद पाने की उम्मीद कर रहे हैं. चूंकि राष्ट्रीय नेतृत्व एक परिवार के बीच सिमटा हुआ है. इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी शख़्स गंभीर महत्वाकांक्षा पालकर कांग्रेस में नहीं रह सकता. अगर कांग्रेस राज्य स्तर पर सत्ता बनाए रखने में विफल रहती है, तो प्रतिभाशाली कांग्रेस नेताओं के लिए एक स्पष्ट संदेश जाएगा. संदेश यह कि वे अपनी खुद की कांग्रेस पार्टी बनाएं.

feedback@chauthiduniya.com

पूर्वी चंपारण : सांसद आदर्श ग्राम खैरीमाल

50 दलित परिवारों के घर तबाह

स्थानीय सांसद सह केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने इन परिवारों से मिलना तक ज़रूरी नहीं समझा

राकेश कुमार

केंद्रीय कृषि मंत्री एवं मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह द्वारा गोद लिए गए आदर्श ग्राम खैरीमाल में दबंगों ने 50 महादलित परिवारों के न सिर्फ़ घर उजाड़ डाले, बल्कि जमकर लूटपाट की, आवश्यक कागजात-परिचय पत्र जला दिए और मवेशी हांक ले गए. पीड़ित परिवारों ने गांव छोड़कर खेतों और बसवारी की शरण ले रखी है. हुआ यह कि होली के दिन सहनी-साह जाति के तीन-चार लोग नशे में धुत होकर खैरीमाल मुसहर बस्ती पहुंचे, जहां महिलाओं से छेड़छाड़ को लेकर भुटेली मांझी और हरि सहनी में पहले कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई और क़रीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए. गंभीर रूप से घायल हरि सहनी को इलाज के लिए मोतिहारी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे पटना रेफर कर दिया. दूसरे दिन यानी 24 मार्च को सुबह अफ़वाह फैल गई कि पटना में हरि सहनी की मौत हो गई. फिर क्या था, सहनी जाति के लोगों ने खैरीमाल मुसहर बस्ती पर धावा बोल दिया.

राधा मोहन सिंह

घटना के संबंध में दोनों पक्षों ने प्राथमिकी दर्ज कराई है. पुलिस ने एक पक्ष के खूब लाल मांझी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि दूसरे पक्ष से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई. 24 मार्च को उक्त घटना के बाद देर रात इलाज के दौरान हरि सहनी की मौत हो गई. 25 मार्च को पुलिस की मौजूदगी में गांव में उसका दाह संस्कार हुआ. प्रशासन ने पारिवारिक लाभ योजना के तहत बीस हज़ार और कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत 15 सौ रुपये की धनराशि हरि सहनी के परिवार को दी है. गांव में अभी भी तनाव बरकरार है, जिसे देखते हुए पुलिस वहां कैंप कर रही है. लोगों का आरोप है कि शासन-प्रशासन मामला रफा-दफा करने की फिराक में है. अभी तक ज़िले के किसी भी आला अधिकारी ने गांव पहुंचने की जहमत नहीं उठाई. केंद्रीय कृषि मंत्री एवं स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी में होने के बावजूद खैरीमाल जाना मुनासिब नहीं समझा और घटना को आपसी विवाद का अंजाम बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया. विधायक श्याम बाबू राय घटना के दो दिनों बाद खैरीमाल पहुंचे, लेकिन महादलित परिवारों ने उन पर पक्षपात का आरोप लगाया है.

पिपरा विधानसभा क्षेत्र की जमुनिया ग्राम पंचायत का गांव है खैरीमाल, जिसे सांसद राधामोहन सिंह ने 14 नवंबर, 2014 को गोद लिया था. अपने पहले भ्रमण के दौरान उन्होंने कहा था कि खैरीमाल की आबादी बहुत कम है, इसलिए पूरी जमुनिया ग्राम पंचायत में विकास कार्य किए जाएंगे. लेकिन, खैरीमाल और जमुनिया ग्राम पंचायत की हालत में आज तक कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं हो सका.

मुसहर विकास मंच के लालू मांझी ने मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है. दलित अधिकार मोर्चा के राम सेवक राम ने घटना को सोची-समझी साज़िश करार दिया. वहीं ग्रामीण राष्ट्रवादी जनता दल के ज़िलाध्यक्ष अंकुश कुमार सिंह और मानवाधिकार उल्लंघन नियंत्रण प्रकोष्ठ के ज़िला संयोजक एवं अधिवक्ता पवन कुमार मामले को राजनीति से प्रेरित मानते हैं. गांव वाले भी बताते हैं कि इस बार पंचायत चुनाव में उतरने का ख्वाब संजोए बैठे कुछ लोग हमेशा दलित विरोधी रहे हैं और उन्हें डर है कि दलित उनके ख़िलाफ़ वोट करेंगे. इसलिए उन्होंने हरि सहनी की मौत की झूठी अफ़वाह फैलाकर जाति विशेष का आक्रोश भड़का दिया. लूटपाट के दौरान चुनावी साज़िश के तहत दलितों की ज़मीनों के दस्तावेज और पहचान-पत्र आदि भी नष्ट कर दिए गए. गांव छोड़कर भागे सैकड़ों दलित वापस लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं.

पिपरा विधानसभा क्षेत्र की जमुनिया ग्राम पंचायत का गांव है खैरीमाल, जिसे सांसद राधामोहन सिंह ने 14 नवंबर, 2014 को गोद लिया था. अपने पहले भ्रमण के दौरान उन्होंने कहा था कि खैरीमाल की आबादी बहुत कम है, इसलिए पूरी जमुनिया ग्राम पंचायत में विकास कार्य किए जाएंगे. लेकिन, खैरीमाल और जमुनिया ग्राम पंचायत की हालत में आज तक कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं हो सका. खैरीमाल के चार वार्डों में से सिर्फ़ एक में आंगनबाड़ी केंद्र है, बाकी तीन वार्डों के बच्चे इस लाभ से वंचित हैं. सांसद सिंह ने खैरीमाल दलित बस्ती में नवसृजित विद्यालय भवन का निर्माण तो करा दिया, लेकिन जमुनिया ग्राम पंचायत के कई विद्यालयों के पास आज भी अपना भवन नहीं है. 50 महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की गई, लेकिन कमजोर तबके की महिलाएं इस लाभ से वंचित रह गईं. पेयजल समस्या बरकरार है. खैरीमाल से सीताकुंड होते हुए पीपरा एनएच जाने वाली सड़क आज भी कच्ची पड़ी है. स्वच्छ भारत अभियान के तहत 100 शौचालयों का निर्माण शुरू कराया गया, जिनमें से अधिकांश आज भी अधूरे पड़े हैं.

दलित परिवारों के घरों को उजाड़ने और लूट-पाट करने के पीछे पंचायत चुनाव भी एक वजह माना जा रहा है. ग्रामीण बताते हैं कि मुखिया पद के लिए चुनाव में कई लोग खड़े हैं. इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्होंने हमेशा दलितों का शोषण किया है. उन्हें डर है कि इस बार दलित उन्हें वोट नहीं देंगे. उन्हीं लोगों ने झूठी अफवाह फैलाकर सहनी समुदाय के आक्रोश को भड़का दिया. यही कारण है कि लूटपाट के दौरान दलितों की ज़मीन के क़ागजात, पहचान पत्र आदि नष्ट कर दिए गए. बहरहाल, यह जिले की पहली बड़ी घटना है जहां 51 दलित परिवारों के घरों को उजाड़ दिया गया पर उनके दर्द पर मरहम लगाने की कौन कहे, उनका हाल जानने को भी राजनेता, शासन-प्रशासन तैयार नहीं है. ■

feedback@chauthiduniya.com

गया

नक्सलियों का नया धंधा : अफ़ीम की खेती

चौथी दुनिया ब्यूरो

बिहार-झारखंड की सीमा पर अपनी आधार-भूमि में नक्सलियों ने अब एक नया धंधा शुरू कर दिया है. गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र में जीटी रोड के दोनों ओर स्थित हजारों एकड़ रैयती, सरकारी तथा वनभूमि में अफीम की खेती सुनियोजित तरीके से की जा रही है. पिछले एक दशक से बाराचट्टी प्रखंड की आधा दर्जन पंचायतों के दो दर्जन से अधिक गांवों में अफीम की खेती बड़े पैमाने पर हो रही है. जीटी रोड के बगल में होने के कारण इस नशीले पदार्थ की तस्करी पंजाब, हरियाणा, यूपी, झारखंड आदि राज्यों में बड़ी आसानी से होती है. पिछले दिनों एक गुप्त सूचना मिलने पर नारकोटिक्स के अधिकारियों ने जब बाराचट्टी के एक लाईन होटल में छापामारी कर डेढ़ किलोग्राम अफीम और तकरीबन सवा क्विंटल अफीम के डोडा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया. नक्सली अफीम का पौधा लगाने से लेकर अफीम तैयार होने तक विभिन्न स्तर पर लेवी की वसूली करते हैं. इस मामले में स्थानीय पुलिस और नक्सलियों के खिलाफ अभियान में लगे अर्द्धसैनिक बलों की भूमिका भी संदिग्ध है. नारकोटिक्स के अधिकारियों ने इस सवाल को उठाते हुए कहा कि पुलिस के चौकीदार गांव-गांव में हैं, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती हो रही है, ऐसे में कहीं न कहीं पुलिस व वन विभाग के अधिकारी भी संदेह के घेरे में हैं. क्योंकि वन विभाग के बड़े भू-भाग में अफीम की फसल लहलहा रही है और वन विभाग के लोगों को इसकी भनक तक नहीं है, यह बात समझ में नहीं आती. नारकोटिक्स के अधिकारियों ने कहा कि क्यों न वन विभाग के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए.

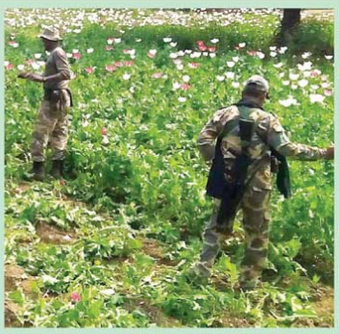

एक दशक पूर्व बाराचट्टी के जंगली क्षेत्र में कट्ठा-दो कट्ठा में चोरी-छिपे अफीम की खेती की जाती थी. अफीम की खेती करने वाले जब दिन-दूना और रात-चौगुना लाभ कमाने लगे, तो अन्य ग्रामीण भी अफीम की खेती करने लगे. धीरे-धीरे अफीम की खेती सरकारी भूमि तथा वन विभाग की भूमि पर भी की जानी लगी. क्षेत्र में सक्रिय नक्सलियों ने अफीम की खेती करने वालों से लेवी वसूलना शुरू किया. प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा (माओवादी) का संरक्षण मिलते ही ग्रामीणों ने बेखौफ होकर हजारों एकड़ भूमि में अफीम की खेती शुरू कर दी. इस वर्ष जनवरी से मार्च के बीच नारकोटिक्स की टीम ने सुरक्षाबलों के सहयोग से करीब 11 हजार कट्ठे में लगी अफीम की फसल को नष्ट किया. इसके बाद भी एक अनुमान के अनुसार दस हजार एकड़ भूमि में अफीम की फसल लहलहा रही है. 21 मार्च 2016 को बाराचट्टी थाना के 71 माईल स्थित लाईन होटल से गिरफ्तार बिरजू यादव ने नारकोटिक्स टीम को बताया कि नक्सली अफीम की फसल बुआई के समय सौ रुपये प्रति कट्ठा, फूल आने पर पांच सौ रुपये प्रति कट्ठा, फसल तैयार होने पर हजार रुपये प्रति कट्ठा तथा अफीम की बिक्री होने पर ढाई हजार रुपये प्रति कट्ठा के हिसाब से लेवी वसूलते हैं. लेवी से संबंधित हिसाब की एक पर्ची जब नारकोटिक्स टीम के हाथ लगी, तब अफीम की तस्करी का सरगना बारवाडीह निवासी बिरजू यादव ने अफीम की खेती में नक्सलियों के संरक्षण और संलिप्तता की बात बताई.

पिछले एक दशक से प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद बाराचट्टी थाना क्षेत्र के जीटी रोड से जुड़े दर्जनों गांवों की हजारों एकड़ भूमि में अफीम की फसल लहलहा रही है और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं है, इसका क्या मतलब निकाला जाए?

बाराचट्टी थाना क्षेत्र के जयगीर, भलुआ, बुमेर, पतलूका, खरांटी तथा नगरपुर पंचायत के दो दर्जन से अधिक गांवों की हजारों एकड़ भूमि में अफीम की खेती की जाती है. बाराचट्टी के जंगल में ही कोबरा बटालियन का मुख्यालय स्थित है. इसके चार-पांच किलोमीटर के दायरे में वनभूमि पर बड़े पैमाने पर अफीम की खेती होती है. सूचना के अनुसार कोबरा बटालियन के आस-पास की लगभग पांच हजार एकड़ वन भूमि पर आज भी अफीम की फसल लहलहा रही है. हालांकि ऐसी बात नहीं है कि पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है. समय-समय पर अफीम की फसल को पुलिस व सुरक्षाबलों द्वारा नष्ट किया जाता है. लेकिन इसके बाद भी अफीम की खेती कम हाने की जगह दिनों-दिन बढ़ती जा रही है. अफीम की खेती ऐसे जंगली क्षेत्रों में की जाती है, जहां दिन के उजाले में भी नक्सलियों के खौफ से पुलिस व सुरक्षाबलों के अलावा शायद ही कोई सरकारी मुलाजिम नज़र आता है. प्रशासन की कार्रवाई अफीम की फसल को नष्ट करने तक ही सीमित है. अफीम की फसल लगाने वाले और इसका कारोबार करने वाले लोग प्रशासन की कार्रवाई के दायरे से बाहर हैं. सूत्रों के अनुसार अफीम की बर्बाद हो चुकी फसल के डंठल व अन्य अवशेषों को भी धंधेबाज इस्तेमाल में ला रहे हैं. कई इलाकों में अफीम की फसल तैयार हो चुकी है और इससे फल निकाला जा रहा है. लोग बताते हैं कि नक्सल प्रभावित बाराचट्टी के जंगली क्षेत्रों में नवंबर माह से अफीम की फसल लगाने का काम शुरू हो जाता है. लेकिन वन विभाग, पुलिस और प्रशासन के लोगों को इसकी भनक भी नहीं लगती है. जबकि पुलिस का चौकीदार प्रत्येक पंचायतों में कार्यरत है. नारकोटिक्स विभाग के बिहार-झारखंड के क्षेत्रीय निदेशक त्रिलोकीनाथ सिंह और अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि बिहार-झारखंड की सीमा पर दर्जनों गांवों में नक्सलियों के संरक्षण में हो रही नशीले पदार्थों की खेती को ध्यान में रखते हुए बाराचट्टी में जीटी रोड पर नारकोटिक्स थाना खोलने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है. लेकिन सवाल यह है कि पिछले एक दशक से प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद बाराचट्टी थाना क्षेत्र के जीटी रोड से जुड़े दर्जनों गांवों की हजारों एकड़ भूमि में अफीम की फसल लहलहा रही है और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? जबकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चौकीदार के अलावा एसपीओ ग्रामीण क्षेत्रों की सूचना थाने तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं. नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों ने वनकर्मियों, स्थानीय पुलिस-प्रशासन और सुरक्षाबलों की कार्रवाई पर शंका जाहिर की है. हालांकि बाराचट्टी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रही अफीम की खेती के मामले में आधिकारिक रूप से कोई भी पदाधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है. ■

feedback@chauthiduniya.com

आग से ख़ाक हुई ज़िंदगी को चाहिए एक ठिकाना

आग से हर साल झरिया की एक बस्ती का अस्तित्व समाप्त हो रहा है. पिछले एक दशक में ज़मीनी आग ने झरिया से जुड़े 6.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वीरान बना दिया है. 1997 में झरिया में लगी आग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने झरिया की आग को राष्ट्रीय त्रासदी घोषित कर केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि वह एक्शन प्लान बनाए और उसकी प्रगति रिपोर्ट से कोर्ट को अवगत कराए. केंद्र सरकार ने 2004 में झरिया पुनर्वास विकास प्राधिकरण की स्थापन की. मास्टर प्लान के अनुसार पुनर्वास के कार्य को दो चरणों में पूरा करना है.

सुनील सौरभ/शैलेंद्र

झारखंड का झरिया शहर पूरी दुनिया में बेहतर कोयले के लिए जाना जाता है. यहां के कोयले से देश-दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कल-कारखानों को ईंधन प्राप्त होता है. ऊर्जा पैदा करने के लिए यहां के कोयले को सबसे अच्छा माना जाता है. लेकिन पिछले सौ साल से धधक रहे झरिया शहर को जिस तरह के ईंधन की जरूरत है, वह उसे कोई नहीं दे पा रहा है. नतीजा है कि झरिया शहर के नीचे कोयले में लगी आग से अब तक पंद्रह छोटे-बड़े शहरों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है. सैकड़ों घर भूगर्भ की आग से हुए भू-धसान की वजह से जमींदोज हो चुके हैं. हजारों लोगों की मौत भी हो चुकी है. लेकिन भूगर्भ आग से झरिया में जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, वे मुआवजा देने या पुनर्वास की व्यवस्था करने में झरिया क्षेत्र पुनर्वास विकास प्राधिकरण पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगा रहे हैं.

झारखंड के धनबाद जिले में दामोदर नदी के एक किनारे बसा झरिया करीब एक सौ साल से धधक रहा है. वर्तमान में झारखंड सरकार तथा धनबाद जिला प्रशासन ने लगभग 60 हजार प्रभावित लोगों को दूसरे स्थान पर बसाने की व्यवस्था की है. झरिया क्षेत्र पुनर्वास विकास प्राधिकरण के प्रभारी पदाधिकारी गोपाल जी ने बताया कि पहले चरण में बेलगड़िया में टाउनशिप बनाकर लोगों को पुर्नस्थापित करने की योजना है. यहां कुल 2,352 यूनिट बनकर तैयार हैं. एक यूनिट दो कमरे की है. इसलिए प्रत्येक परिवार को दो-दो यूनिट देने का निर्णय लिया गया है. बेलगड़िया में ही एक नई टाउनशिप बनाई जा रही है, जहां चार हजार लोगों को बसाने की योजना है. गोपाल जी ने बताया कि झरिया में बीसीसीएल की बंद पड़ी खदानों में लगी आग से प्रभावित होने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए झरिया का मास्टर प्लान साल 2004-05 में बना था. लेकिन इसे साल 2009 में स्वीकृति मिली. इस मास्टर प्लान को दस वर्ष में पूरा करना है. उन्होंने बताया कि इसके लिए आग प्रभावित 595 साइट्स पर 2008 में सर्वे हुआ था. जिसमें पुनर्वास के लिए वास्तविक रूप से 30 हजार रैयतों की सूची बनाई गई थी. इस सर्वे में बताया गया कि 95 हजार अतिक्रमणकारी भी हैं. प्रभारी पदाधिकारी गोपाल जी ने बताया कि 54,159 निवासी हैं, जिन्हें हाउस होल्ड देना है. लेकिन बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के सुरेश पासवान, सुरेश गुप्ता, बिहारीलाल चौहान, विनोद पासवान और धनबाद युवा जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सत्येन्द्र चौहान ने बताया कि सरकार की जो पुनर्वास नीति है, इससे कोयला उत्खनन एवं आग प्रभावित भू-धसान क्षेत्र के लोगों को कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है. इन सभी नेताओं ने कहा कि सरकारी प्रबंधन ने लोगों को मात्र 10 हजार रुपये देकर आग प्रभावित क्षेत्र के आस-पास ही बसा दिया. बलियापुर प्रखंड के निपनीया गांव में आज भी सैकड़ों ग्रामीण अर्द्धनग्न होकर जरेडा प्रबंधन की पुनर्वास नीति के ख़िलाफ आंदोलन कर रहे हैं. 1916 में पहली बार झरिया के भौरा कोलियरी में आग लगने का पता चला था. इसके बाद भी इस क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा 1930 में कोयले का उत्खनन शुरू किया गया. इससे पूर्व 1890 में पहली बार धनबाद में कोयला होने का पता चला था. 1930 में अंग्रेजों ने जब कोयला खदान शुरू की थी, तब सुरंग बनाकर खनन की अवैज्ञानिक प्रक्रिया थी, जिसे आज़ादी के बाद निजी खदान मालिकों ने जारी रखा. 1973 में जब कोयला खदानों को राष्ट्रीयकृत किया गया, उस वक्त यहां 70 जगहों पर ज़मीन के नीचे कोयले में आग लगी थी. तब इन इलाकों में आबादी नहीं थी. आग का पहला सर्वे वर्ष 1986 में हुआ तो पता चला कि तब तक आग 17 वर्ग किलोमीटर में फैल चुकी थी.

आग से हर साल झरिया की एक बस्ती का अस्तित्व समाप्त हो रहा है. पिछले एक दशक में ज़मीनी आग ने झरिया से जुड़े 6.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वीरान बना दिया है. 1997 में झरिया में लगी आग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने झरिया की आग को राष्ट्रीय त्रासदी घोषित कर केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि वह इसके लिए एक्शन प्लान बनाए और उसकी प्रगति रिपोर्ट से कोर्ट को अवगत कराए. केंद्र सरकार ने 2004 में झरिया पुनर्वास विकास प्राधिकरण की स्थापन की. मास्टर प्लान के अनुसार पुनर्वास के कार्य को दो चरणों में पूरा करना है. पुनर्वास पर 4,780 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जबकि आग बुझाने पर 23.11 करोड़ रुपये खर्च होंगे. यहां के 85 हजार परिवार इस आग से प्रभावित हैं. बताया जाता है कि अब तक 10 अरब रुपये से अधिक का कोयला जलकर राख हो चुका है. जानकारों का कहना है कि झरिया में ज़मीन के नीचे आग लगने का कारण अवैज्ञानिक तरीके से कोयले का उत्खनन करना है. नियमतः उत्खनन के बाद खाली जगहों को बालू से भरना चाहिए. इसके लिए भारत कोकिंगकोल लिमिटेड की ओर से बड़े-बड़े ठेके दिए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ठेकेदार इन खादानों में बालू की भराई नाम मात्र करते हैं. जिससे कोयले के सीमो के बीच खाली जगह रहने की वजह से आग लग जाती है. इस पर अब तक करोड़ों रुपये खर्च हो चुके हैं. आईएसएम और सीएसआईआर के वैज्ञानिकों ने भी झरिया में लगी भूमिगत आग पर काबू पाने के लिए कई सुझाव दिए थे. लेकिन इन सुझावों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया. जिसकी वजह से आज भी करीब 5 लाख की आबादी झरिया में ज़मीन के नीचे लगी आग से प्रभावित है. वहीं दूसरी ओर सरकार, बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से झरिया बचाओ और झरिया उजाड़ो का खेल जारी है. इसमें कुछ नेताओं और कुछ तथाकथित समाजसेवियों की ओर से बिचौलियों का कार्य किया जा रहा है. पिछले तीन दशक में झरिया के आग के दरिया में अनेक तथाकथित नेता एवं विस्थापितों के तथाकथित शुभचिंतक करोड़ों रुपये का वारा-न्यारा कर चुके हैं. बताया जाता है कि आग से प्रभावित वास्तविक रैयतों पर अतिक्रमणकारी हावी हैं. नतीजतन आग से प्रभावित लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है. सबकी एक ही मांग है कि सौ साल से लगी झरिया की आग को बुझाया जाए.■

feedback@chauthiduniya.com

HPL Electric & Power Pvt. Ltd.
www.hplindia.com

C/o : C&FA SURYA UDYOG
Ist Floor, Bhagat Sadan, Sahi Lane,
S.P. Verma Road, Patna-1
Ph No. : 0612-3260738
Mob. No. : 7541895555
E-mail : surya.udyog.br@gmail.com

समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से

प्रश्न : डॉ. साहब मेरी उम्र 62 साल की है। उठने बैठने में काफी परेशानी होती है, जोड़ों में अकड़न रहता है। कोई आर्युवेदिक दवा बतायें। दीनानाथ सिंह, रांची

उत्तर : आप REPL निर्मित ऑर्थोविट कैप्सूल एक कौप्सूल सुबह और एक कैप्सूल रात को सोते सम लें और ऑर्थोविट ऑयल से प्रभावित जोड़ों की मालीश करें काफी लाभ होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 21 वर्ष है, काम क्रीड़ा में जबरदस्त उल्लास उठता है। मगर स्पर्श मात्र से ही स्खलित हो जाता हूँ। अंग भी छोटी है-मै क्या करूं? प्रभात, औरंगाबाद

उत्तर : गलत संगत या बुरी आदत के कारण अक्सर ये सब होता है। आप अपने काम पर ध्यान दें और विगोरा 2000 की 7 शीशी का कोर्स करें और विगोरा ऑयल से मालिश करें, निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 32 वर्ष है कुछ दिनों से शिघ्रपतन से परेशान हूँ और एक बार सम्बन्ध स्थापित करने के बाद दोबारा मन नहीं करता और आलस्य बना रहता है। अरूण सिन्हा, नोयडा

उत्तर : आप REPL निर्मिता विगोरा 5000 दिन में 3 बार) कप पानी में लें और विगोरा ऑयल से अंग पर मालिस करें। आपकी परेशानी दूर हो जायेगी।

प्रश्न : मैं 42 वर्षीय दो बच्चों का पिता हूँ मेरी समस्या यह है कि मुझे पत्नी से सहवास की इच्छा नहीं होती। यदि होती है तो मुश्किल से 15 सेकेन्ड के लिए । मैं क्या करूं? शंकर तिवारी, गुरगांव

उत्तर : बढ़ती उम्र में अक्सर ऐसा होता है। तनाव, भागदौड़ एवं किशोरावस्था की गलती बहुत से कारण हो सकते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नही है आप विगोरा हाई पावर का 90 दिन का कोर्स करें एवं हाई पावर मुसली ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें। निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : उम्र 64 वर्ष है। संभोग की तिव्र इच्छा होती है मगर शिशन में कोई हरकत नहीं होती है। इसलिए मन मारकर रह जाता हूँ। सुनील मेहरा वर्धमान

उत्तर : इस उम्र में ऐसा होता है। आप विगोरा 5 X का 5 शीशी का कोर्स करें और साण्डह ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें।

प्रश्न : डॉ. साहब मैने टी.वी. पर विज्ञापन देखकर वासनोउत्पति के लिए एक हलवा तरह की दवा मंगवाया उस दवा से फायदा तो कुछ नहीं हुआ उलटा पूरी रात सिर दर्द से छटपटाता रहा। कोई आर्युवेदिक और हानिरहित दवा बताएं। ईश्वरी राय, गाजियाबाद

उत्तर : ईश्वरी जी, कुछ दवा निर्माता बड़े-बड़े विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपने भ्रम जाल में फंसाते हैं और अपने दवा में सिर्फ सिल्डेनाफी मिलाकर बेचते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। मेरे सुझाव से आप REPL निर्मित सुपर सोनिक कैप्सूल समय से दो घंटा पहले लें। यह दवा पूर्णतः आर्युवेदिक है एवं इसका कोई भी साइड इफैक्ट नहीं है।

प्रश्न : मैं 24 वर्षीया एक अविवाहित युवती हूँ मेरे स्तनों का विकास अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। जिससे मैं काफी परेशान रहती हूं, आशा है कि आप मुझे सही मार्गदर्शन करायेंगे। स्नेहलता वर्मा, नोयडा

उत्तर : स्तनों का का संपूर्ण विकास नहीं होने के अनेक कारण हैं, जैसे हार्मोन्स की कमी अनुवांशिक। आप चिन्ता मन से निकाल दें एवं REPL का Breastrim Oil स्तनों पर सुबह-शाम दिये गये निर्देश के अनुसार 3 माह तक मसाज करें। इसके नियमित इस्तेमाल से स्तन में उभार आयेगा एवं आप आकर्षक नजर आयेंगी।

प्रश्न : मैं 36 वर्षीय विवाहित स्त्री हूँ पिछले एक वर्ष से पानी गिरने की समस्या है और मेरी जननांग भी काफी ढीली हो गई है। कोई हानिरहित उपचार बतायें। आभा दिल्ली

उत्तर : आभा जी आप विगोरा 1000 दिन में 2 बार 15-15 बूँद आधा कम पानी मिलाकर पियें और Virgin Oil का अंदरूनी हिस्से पर लगाएं। यह बिल्कूल ही हानिरहित दवा है।

प्रश्न : मैं 38 वर्षीय पुरूष हूँ। समस्या यह है कि शरीर में हर वक्त आलस बना रहता है काम में भी मन नहीं लगता है एवं सहवास की भी इच्छा नहीं होती है। कोई आयुर्वेदिक दवा बताये। शम्भु सिंह, देहरादून

उत्तर : शम्भु जी! आप हाईपावर मुसली कैप्सूल का 1 कैप्सूल प्रत्येक दिन रात में सोते वक्त दूध के साथ लें और हाई पावर मुसली ऑयल दो बार 45 दिनों तक इस्तेमाल करें आपके शरीर में शक्ति आयेगी एवं आलस भी दूर रहेगा।

चिकित्सीय परामर्श के लिए स्वपता लिखित डाक लिफाफा, निम्न पते पर भेजें :
REPL प्लाजा, तीसरा तल्ला
फेडरल, पटना - 801505

Contact : 9304792851,9386880107 & 0612-2251189, (10 AM to 5 PM)
E-mail : customercare@replpharma.com, Visit us at : replpharma.com

डिस्ट्रीब्यूटरः दिल्ली/हरियाणा/पंजाब : निशा मेडिकोज 8860206755, 9988532909, जयपुरः आर.के. डिस्ट्रीब्यूटर 0141-2315071, उत्तर प्रदेश-कानपुर : खरया मेडिकल एजेंसी 0512-2372347, 9415127822, मुगलसरायः प्रकाश होमियो स्टोर 253078, मध्य प्रदेश-जबलपुर : मनीष फार्मा 0761-4004863, 9425157379, छत्तीसगढ़-भिलाई : सिंह होमियो हॉल 0788-403828, 9302839666, रायपुर : जर्मन होमियो 0771 4095630, बिहारः मॉर्डन डिस्ट्रीब्यूटर 9304018193, नॉर्थईस्ट आसाम- बोरिक होमियो रेमेडिज 03672 225340, 09435061793, पश्चिम बंगाल : एम एस ट्रेडर्स 9903175579, देव मार्केटिंग 033-30221018, सिलिगुड़ी : कलकत्ता होमियो 9593313011, झारखंडः सिंघानियां डिस्ट्रीब्यूटर 9431164318, उड़ीसा-भुवनेश्वर डायनेमिक होमियो हॉल 9437110810 कर्नाटक -विजापुर 9341610592 गुलवर्ग:9343834519

दुबारा टी.बी. बन रही मौत का कारण

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

DR RAVI RANJAN KUMAR
T.B. Officer, Aurangabad

टी.बी. उन्मूलन के लिए सरकार प्रयासरत है। लेकिन उनका क्या है जो टी.बी. की दवाई का पुरा कोर्स नहीं करते। इसलिए एम.डी.आर मरीजों की संख्या में बढ़ोत्तरी होती जा रही है। यह कहना है औरंगाबाद में टी.बी. उन्मूलन में लगे डॉ. रवि रंजन कुमार का जो टी.बी. के रोगीयों के इलाज के विशेषज्ञ हैं।

डॉ. रवि रंजन ने बताया कि साधारण टी.बी. मरीजों के लिए 6 से 8 महीने का कोर्स होता है लेकनि एम.डी.आर (मल्टी ड्रग रेसिसटेन्ट) के मरीजों के लिए 24 + 3 महीने का कोर्स होता है और यह नहीं करने पर जानलेवा सिद्ध होता है। सरकार टी.बी. के मरीजों के ईलाज के लिए कई कार्यक्रम चला रही है और ईलाज मुफ्त में करा रही है। डॉ. रंजन ने बताया कि यह बिमारी इनफेक्शन से फैलती है इसलिए सचेत रहने की जरूरत है। दवाई से रेसिटेन्ट कर दुबारा होने वाले टी.बी. मरीजों की संख्या लगभग 2 से 3 प्रतिशत है जबकि पहली बार होने वाली मरीजों की संख्या लगभग 17-18 प्रतिशत के आसपास है।

Carbo - XT Drops Susp.
Ferrous Ascorbate100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamine B5 mcg Tab.

A Colic Drops.
Simethocone Emulsion, Dil Oil Fennel Oil

Siliplex Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus

Oflogyl-OZ Susp. (60 ml)
Ofloxacine 100 mg & Omindazole 125 mg

Acoba Syp.
Methylocobalamine, Lycopene, Multivitamine Multimineral & Antioxident

एक नजर में - टी.बी. यानि क्षय रोग एक संक्रामक रोग है, जो कीटाणु के कारण होता है। टी.बी.के लक्षण - तीन सप्ताह से ज्यादा खांसी बुखार विशेष तौर से शाम को बढने वाला बुखार, छाती में दर्द, वजन का घटना, भूख में कमी, बलगम के साथ खून आना, टी.बी. की अगर तीन सप्ताह से ज्यादा खांसी हो तो तुरन्त नजदीकी कुशल चिकित्सक से मिलें या सरकारी अस्पताल में ईलाज करायें जहां दवा मुफ्त दी जाती है। तीन नमूनों की निःशुल्क जांच होती है। बचाव - बच्चों को जन्म से एक माह के अन्दर BCG का टीका लगवायें। रोगी खांसते व छींकतें वक्त मुंह पर रूमाल रखें। रोगी जगह.जगह नहीं थूंके। क्षय रोग का पूर्ण इलाज ही सबसे बडा बचाव का साधन है। टी.बी. रोग विशेषकर 85 प्रतशित फॅफडों को ग्रसित करता हैए 15 प्रतिशत केसेज शरीर के अन्य अंग जैसे मस्तिष्क, आंतें, गुर्दे, हड्डी व जोड इत्यादि भी रोग से ग्रसित होते हैं। ▪ भारती

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

भ्रष्टाचार के आरोपी आईएएस पंधारी यादव को बचाने का सत्ताई हथकंडा

सीबीआई जांच के बीच ही पुलिस ने दे दी क्लीन-चिट

महेंद्र अग्रवाल

सत्ता शीर्ष तक सीधी पहुंच रखने वाले आईएएस अफसर पंधारी यादव भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में चाहे जितने पगे हों, पर पुलिस वाले उनके इतने सगे हैं कि पंधारी में उन्हें कोई ऐब नहीं दिखता. पंधारी यादव मुख्यमंत्री सचिवालय तक तैनात रहे हैं और तमाम विवादों में रहे हैं. पंधारी यादव के घपले-घोटालों की सीबीआई जांच कर रही है. इन्हीं वजहों से उन्हें मुख्यमंत्री सचिवालय से हटाया गया. पंधारी जब सोनभद्र के जिलाधिकारी थे, तब भी भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के कई मामले उजागर हुए थे. तब रॉबर्ट्सगंज के सीजेएम के आदेश पर डीएम पंधारी यादव, रेलवे के वरिष्ठ मंडल अभियन्ता संतोष गुप्ता, पीडब्लूडी के एक्सईएन सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और कूट रचना का मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था. लगभग दो साल तक मामले को दबाकर रखने के बाद अदालत से स्थिति की जानकारी मांगे जाने पर पता चला कि पुलिस ने सभी को क्लीन चिट देते हुए अदालत में फाइनल रिपोर्ट भी दाखिल कर दी.

मामला यह है कि सन् 1954 में चुर्क-अरीली-सिद्धी मार्ग पर ग्रामीणों के आवागमन हेतु एक ओवर ब्रिज (संख्या-436) बनाया गया था. कुछ साल पूर्व जेपी एसोसिएट्स ने चुर्क में पावर प्लांट बनाना प्रारम्भ किया तो इस पुल से पाइप लाइन एवं केबल गुजारने की अनुमति जिला प्रशासन व रेलवे से मांगी. रेलवे के विभागीय नियमों के अनुसार यह सम्भव नहीं था. तब रेलवे के तत्कालीन वरिष्ठ मंडल अभियन्ता संतोष गुप्ता ने विभागीय रिकॉर्ड न मिलने का हवाला देते हुए पुल को राज्य सरकार की सम्पति बता दिया. इसी आधार पर पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन एक्सईएन ने भी आनन-फानन में अनापत्ति जारी कर दी और तब के जिलाधिकारी पंधारी यादव ने फौरन अनुमति जारी कर दी. तत्कालीन जिलाधिकारी पंधारी यादव के दबाव में ही रेलवे के मंडल अभियन्ता सहित पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन द्वारा यह सब किया गया जबकि पुल रेलवे की सम्पत्ति के रूप में अभिलेखों में दर्ज है. पंधारी यादव द्वारा पूर्व में ही जेपी एसोसिएट्स को दस्तावेजों में हेराफेरी करके लाइम स्टोन वाली सैकड़ों हेक्टेयर वन भूमि अवैध ढंग से दे दी गई थी. अनेक शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर 2014 में सीजेएम की अदालत में धोखाधड़ी एवं कूट रचना का मामला दर्ज कराया गया था. साक्ष्यों से संतुष्ट होने पर अदालत ने 10 अप्रैल 2014 को तत्कालीन वरिष्ठ मंडल अभियन्ता, पीडब्लूडी एक्सईएन, डीएम एवं अन्य के कृत्यों को संज्ञेय अपराध मानते हुए पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. विवेचक एएसपी शंभुशरण यादव ने सीजेएम न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट (एफआर) दाखिल कर दी है.

मुकदमा वादी एवं अधिवक्ता विजय प्रकाश मालवीय ने कहा कि प्रगति रिपोर्ट न्यायालय के जरिए मांगी गई थी, उसके बाद पुलिस ने 25 फरवरी 2016 को एफआर दाखिल की है. अधिवक्ता विजय प्रकाश मालवीय ने पूर्व डीएम पंधारी यादव, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद के तत्कालीन वरिष्ठ मंडल अभियंता (प्रथम) अजय शर्मा, अधिशासी अध्यक्ष जेपी एसोसिएट्स चुर्क इंडस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स चुर्क और इंद्रदेव राम तत्कालीन एक्सईएन प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग सोनभद्र के विरुद्ध सीजेएम न्यायालय में धारा 156 (3) आईपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था. न्यायालय के आदेश के अनुपालन में रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने एक अप्रैल 2015 को केस दर्ज किया था. इन पर फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेज तैयार कर रेलवे ओवरब्रिज पर कार्य करवाने के लिए अनुमति प्रदान कर लाभ प्राप्त करने का आरोप है. अधिवक्ता विजय प्रकाश मालवीय का कहना है कि धोखाधड़ी के दस्तावेजी साक्ष्य होने के बावजूद पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी. यह कार्रवाई तब हुई जब 18 फरवरी को प्रार्थना पत्र देकर मामले की प्रगति रिपोर्ट न्यायालय के जरिए मंगवाई गई. और आनन-फानन में 25 फरवरी को फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी गई. मालवीय ने कहा कि न्यायालय की ओर से सूचना मिलने के बाद इसके विरुद्ध प्रोटेस्ट पेटिशन दाखिल की जाएगी.

ज्ञातव्य है कि 2007 से 2011 तक प्रदेश के सबसे कमाऊ जिले सोनभद्र में डीएम रहे पंधारी यादव के ही कार्यकाल में मनरेगा में सैकड़ों करोड़ रुपये का घोटाला, घपला और लूटखसोट हुई जिसकी जांच सीबीआई कर रही है. सीबीआई की जांच भी अंतिम दौर में है. सीबीआई ने घोटाले से जुड़े डेढ़ सौ से अधिक लोगों को चिन्हित कर लिया है और छोटी मछलियों की धरपकड़ भी शुरू कर दी है. पंधारी यादव ने मनरेगा सहित अन्य योजनाओं की रकम की लूटखसोट के लिए जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर एक एनजीओ भी बनाया था जिसके मार्फत लाखों-करोड़ों रुपये की बंदरबांट की गई. पंधारी यादव के कार्यकाल में जिले में हर तरफ घोटाला, घपला और लूटखसोट मची हुई थी. करोड़ों रुपये बटोरने वाले पंधारी यादव अखिलेश यादव की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री के विशेष सचिव बनकर पंचम तल पर बैठ गए. मुख्यमंत्री सचिवालय में तैनात होते हुए भी वे वहीं से सोनभद्र जिला हांकते थे. उन्हीं की मर्जी से वहां कोई अधिकारी तैनात होता था या वहां से खिसकाया जाता था. सत्ता पहुंच के कारण ही मनरेगा घोटाले के मामले को काफी लंबे अर्से तक खींचा जाता रहा. आखिरकार अदालत द्वारा सीबीआई जांच का आदेश देने के बाद ही यादव को पंचम तल से हटना पड़ा, लेकिन इस बीच जिले से घोटाले से जुड़े अहम दस्तावेज और पत्रावलियां ठिकाने लगाई जा चुकी थीं. समाजवादी सत्ता अब पंधारी को बचाने के लिए सीबीआई को साधने में लगी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

रिश्तेदार को बचाना तो सपा नेतृत्व का पुनीत दायित्व है!

समाजवादी पार्टी के नेता अपने रिश्तेदार को आखिर क्यों न बचाएं! आईएएस अफसर पंधारी यादव का पावन कर्तव्य था कि वे सत्ता से दम लेकर भ्रष्टाचार करें और सपा नेतृत्व का पुनीत दायित्व था कि वे सत्ता के दम पर अपने भ्रष्ट रिश्तेदार को बचाएं, संरक्षण दें. पंधारी यादव भी कोई मामूली आईएएस अफसर थोड़े ही हैं. वे कासगंज जिले के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद देवेंद्र सिंह यादव के दामाद हैं. आईएएस अफसर पंधारी की पत्नी नीरज यादव कासगंज में सोरों ब्लॉक के तहत अल्लीपुर बरवारी की ग्राम प्रधान हैं. पंधारी की एक साली बसू यादव कासगंज की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और दूसरी साली तनु यादव सोरों की ब्लॉक प्रमुख चुनी गई हैं. सत्ता सामर्थ्य के बेजा इस्तेमाल का नायाब उदाहरण यह है कि तनु यादव विदेश में थीं और यहां नामांकन दाखिल हो गया. जिलाधिकारी से शिकायत की जाती रही कि प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने आया नहीं तो नामांकन कैसे दाखिल हो गया? बाकायदा शिकायत दर्ज हुई कि नामांकन प्रपत्र पर प्रत्याशी के हस्ताक्षर फर्जी हैं, इसके बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की. मतदान के एक दिन पहले तनु यादव सोरों पहुंचीं और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीत गईं. ...तो पंधारी यादव की राजनीतिक ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है. इससे यह भी अंदाजा लगता है कि भ्रष्टाचार के आरोपी पंधारी यादव पर कानून कितना हाथ डाल पाएगा. ■

यूपी के कासगंज में बिजली घोटाले और बिजली चोरी का नायाब मामला

162 पंचायतों के सचिव व प्रधान बिजली चोर

अधिकारियों ने जांच ठंडे बस्ते में डाली, बिजली विभाग नहीं कर रहा कार्रवाई

अवधेश दीक्षित

कासगंज जनपद की 162 पंचायतों के प्रधान व सचिव बिजली चोरी के दोषी पाए गए हैं. लोक निर्माण विभाग की तीन सदस्यीय जांच समिति (एएसडीएम, डीडीओ व एई) ने ग्राम पंचायतों में बिजली चोरी की पुष्टि भी कर दी है और इस मामले में आगे की जांच सीबीसीआईडी या किसी अन्य एजेंसी से कराने की संस्तुति भी की है. बिजली अधिकारियों ने भी पंचायतों में कटिया डालकर बिजली चोरी करने वाले ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव के विरुद्ध बिजली चोरी का मामला दर्ज कराने के बजाए इस ओर से आंखें मूंद ली हैं.

कुछ अर्सा पहले जनपद के तत्कालीन प्रभारी जिलाधिकारी, एडीएम (वित्त एवं राजस्व) बाल मयंक मिश्र को एक शिकायती पत्र मिला कि जनपद की ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइटें लगाने के नाम पर लाखों रुपये का घपला-घोटाला किया गया है. इन लाइटों को कटिया कनेक्शन द्वारा जलाकर व्यापक पैमाने पर बिजली चोरी की जा रही है. प्रभारी जिलाधिकारी ने इस मामले की जांच तत्कालीन एएसडीएम नरेंद्र सिंह, डीडीओ एमलाल और लोकनिर्माण विभाग के एई एई पीके राकेश को सौंपी. अधिकारियों ने जैसे ही जांच शुरू की तो जिला पंचायती राज विभाग में हड़कंप मच गया. जांच के दायरे में आए डीपीआरओ, ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव ने जांच में अड़ंगा लगाना शुरू कर दिए. लेकिन दो माह की जांच में तीनों अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की कि जनपद की 162 ग्राम पंचायतों में लगाई गई 3,945 लाइटों में घपला हुआ है और कटिया कनेक्शन से जलाई जा रही लाइटें पूर्ण रूप से अवैध हैं. शासन में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा है. अवैध कनेक्शन के माध्यम से ग्राम पंचायतों में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी करके शासकीय धनराशि की क्षति पहुंचाई जा रही है. इस जांच में साफ तौर पर बिजली चोरी के लिए प्रथम दृष्टया ग्राम पंचायतों के प्रधान व पंचायत सचिव दोषी पाए गए हैं. पंचायतों में जो स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं उनका पूर्व अनुमोदन भी डीपीआरओ के द्वारा नहीं लिया गया है. जिसकी पुष्टि डीपीआरओ के पत्र से होती है. डीपीआरओ का एक और पत्र, जो सहायक विकास अधिकारियों को लिखा गया था, उसमें भी माना गया कि जनपद में जो लाइटें लगाई गई हैं, उनका कहीं भी स्वीकृत प्रभार नहीं है. ऐसे में सचिव या प्रधान बल्ब या लाइट का कहीं भी प्रयोग करता है तो वह अवैध होगा और वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा. जांच में यह तथ्य भी उजागर हुआ कि जनपद में नियम विरुद्ध लाइटें लगाए जाने की पूर्ण जानकारी डीपीआरओ को थी और इन्हीं की मिलीभगत से ग्राम पंचायतों में अवैध लाइटें लगाई गईं.

जनपद की 162 ग्राम पंचायतों में से 45 में स्ट्रीट लाइटें एक लाख रुपये से लेकर चार लाख रुपये तक लगाई गईं. जबकि विशेष सचिव के आदेश के मुताबिक एक लाख से अधिक मूल्य का सामान टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से ही खरीदा जा सकता है. इन 45 ग्राम पंचायतों में से एक ने भी शासन के आदेश का अनुपालन नहीं किया. जांच अधिकारियों ने पाया कि यह पूरा खेल सुनियोजित तरीके से ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, डीपीआरओ और संबंधित फर्म की मिलीभगत करके किया गया. ■

लाइटों की ख़रीद में लगा 75 लाख का चूना

कासगंज स्ट्रीट लाइट घोटाले में तीन अधिकारियों की समिति ने इस बात की भी पुष्टि की है कि जो लाइटें ग्राम पंचायतों द्वारा खरीदी गईं, वह बाजार मूल्य से दुगने दाम पर खरीदी गईं. पंचायतों ने प्रति लाइट 36 सौ रुपये की दर से लाइटें खरीदीं, जबकि कई स्थानीय फर्म गुणवत्ता वाली लाइटें आधी दर पर ही देने को तैयार थीं. पंचायतों द्वारा इन फर्मों को 142 लाख रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है. लाइटों की खरीद में ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों व संबंधित फर्म द्वारा 75 लाख रुपये का चूना शासन को लगाया गया है. ■

जांच भटकाने में हो गए कामयाब

कासगंज स्ट्रीट लाइट घोटाले की जांच को भटकाने में ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, संबंधित फर्म व डीपीआरओ ने तरह-तरह के हथकंडे अपनाए. जांच टीम द्वारा 45 ग्राम पंचायतों से पंचायतों के प्रस्ताव, टेंडर की कार्रवाई, कार्यादेश कोटेशन, कैशबुक, स्टॉक रजिस्टर से संबंधित दस्तावेज बार-बार मांगे जाने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराए गए. जिला पंचायती राज विभाग में जांच से हड़कंप मचा और कई ग्राम प्रधानों द्वारा समिति के अधिकारियों के विरुद्ध शोषण की शिकायतें प्रमुख सचिव पंचायती राज विभाग और निदेशक पंचायती राज से की गईं. इसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों की शिकायतों के संबंध में जांच समिति के अधिकारियों से दो दिनों के अंदर स्पष्टीकरण तलब किए और जांच को पंचायती राज निदेशक के यहां भेज दिया. जबकि जांच अधिकारियों का मानना था कि घोटाला व्यापक पैमाने पर हुआ है और इसकी जांच सीआईडी या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए. तत्कालीन जिलाधिकारी ने जांच को पंचायती राज निदेशक के यहां स्थानांतरित कर दिया. जिस विभाग में घोटाला हुआ था, जांच उसी विभाग के अधिकारियों के पास स्थानांतरित होने की वजह से पूरा प्रकरण ठंडे बस्ते में चला गया. ■

किसकी हिम्मत है उन पर कार्रवाई करे!

कासगंज जिला प्रशासन एवं बिजली विभाग के समन्वय से बिजली चोरी रोकने का अभियान भी चलाया गया था, लेकिन वे प्रयास भी विफल ही रहे. अभियान के लिए अपर जिलाधिकारी बाल मयंक मिश्र और अपर पुलिस अधीक्षक राधे मोहन भारद्वाज नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे. यह तय हुआ था कि कासगंज में समन्वय के लिए कासगंज के उप-जिलाधिकारी, सीओ व उपखंड अधिकारी जांच टीमों के साथ समन्वय करेंगे और गंजडुंडवारा में पटियाली के उप-जिलाधिकारी, सीओ व उपखंड अधिकारी समन्वय करेंगे. तमाम जांच टीमें गठित करने का उपक्रम भी हुआ और प्रत्येक टीमों के साथ पुलिस का दस्ता भी अटैच किया गया, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात निकला. बिजली चोरी के नायाब तरीकों का पता तो चला, लेकिन बिजली चोरों का कुछ नहीं बिगड़ा. कुछ मामूली मामलों पर कार्रवाई का प्रहसन किया गया और प्रशासनिक सक्रियता की इतिश्री हो गई.

कटिया कनेक्शन के अलावा मीटर से भी चोरी के जुगाड़ सामने आए. इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर हटाकर जो नए इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए गए थे, उनसे भी बिजली चोरी की जा रही है. बिजली चोरी के लिए रिमोट खिलौने (हवाई जहाज उड़ाने वाले रिमोट खिलौने) का इस्तेमाल किया जा रहा है. रिमोट से मीटर को कंट्रोल किया जा रहा है. जैसे ही कोई बिजली चेकिंग के लिए आता है तो रिमोट से मीटर चालू कर दिया जाता है. चेक करने पर मीटर चलता हुआ मिलता है. इसके अलावा बिजली मीटर में जाने वाली अर्थिंग के तार को काटकर बीच में प्रतिरोधक डिवाइस लगा दी जाती है. यह डिवाइस न्यूट्रल की सप्लाई काट देती है, जिस वजह से काउंटर चल ही नहीं पाता और यूनिट घूम ही नहीं पाते. यह डिवाइस रिमोट के साथ जुड़ी होती है. इसकी रेंज 30 मीटर तक होती है. जब भी कोई चेकिंग के लिए आता है तो दूर से ही इस डिवाइस को बंद कर दिया जाता है. इससे न्यूट्रल की सप्लाई बहाल हो जाती है. मीटर की अर्थ वाली डायट (लाइट) भी जल जाती है. लेकिन बिजली चोरी के इन आधुनिक तरीकों का पता लगाने के बावजूद कारगर कार्रवाई नहीं हो पाई. जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा कि जब बड़े-बड़े नेताओं के सामर्थ्यवान रिश्तेदार ही बिजली चोरी करेंगे तो किसकी हिम्मत है कि उन पर सख्त कार्रवाई करे! ■

आज़म ख़ान ने विधानसभा में राज्यपाल के ख़िलाफ़ की अमर्यादित टिप्पणी

आज़म मंत्री पद के योग्य नहीं- नाईक

राज्यपाल ने बयान की मूल सीडी मंगाई, मुख्यमंत्री और विस अध्यक्ष को पत्र लिखा

दीनबंधु कबीर

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री आज़म ख़ान की अमर्यादित और असंवैधानिक वाक-शैली राज्य की संवैधानिक पीठ विधानसभा में भी अपने कीर्तिमान स्थापित कर रही है. उत्तर प्रदेश नगर निगम संशोधित विधेयक-2015 को लेकर आज़म ख़ान ने राज्यपाल राम नाईक के खिलाफ पिछले दिनों सदन में जो अमर्यादित टिप्पणियां कीं उन पर संवैधानिक प्रश्न खड़े हो गए हैं. राज्यपाल राम नाईक ने सदन में दिए गए आज़म के वक्तव्यों की मूल रिकॉर्डिंग सुनकर कहा है कि आज़म ख़ान मंत्री पद के योग्य नहीं हैं. आज़म की अभद्र टिप्पणी को गंभीरता से लेते हुए राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिखा है और इस मसले पर उनसे वार्ता करने को कहा है. आज़म ख़ान ने राज्यपाल राम नाईक के खिलाफ ऐसी टिप्पणी की थी कि उन्हें सदन की कार्यवाही से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन सदन में तो उनका वक्तव्य विधानसभा अध्यक्ष से लेकर सारे सदस्यों ने सुना. आज़म ख़ान ने राज्यपाल की नैतिक-संवैधानिक प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हुए कहा था कि मेयरों को उनके भ्रष्टाचार से बचाने के लिए राज्यपाल उत्तर प्रदेश नगर निगम संशोधित विधेयक-2015 को सालभर से मंजूरी नहीं दे रहे हैं. आज़म ने कहा कि राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में काम कर रहे हैं.

इसके पहले भी आज़म ख़ान राज्यपाल के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करते रहे हैं. उन्होंने राज्यपाल को संघ के कारसेवक की तरह आचरण करने वाला व्यक्ति बताया था. ताज प्रकरण को लेकर भी आज़म ख़ान ने राज्यपाल को आरएसएस का एजेंट कहा था. अभी हाल ही में आज़म ने राज्यपाल पर सीधा प्रहार करते हुए कहा था कि राम नाईक यूपी के राज्यपाल कम अयोध्या के पुजारी अधिक लगते हैं. समाजवादी पार्टी ने आज़म की अभद्रता पर उन्हें अनुशासन की सीख देने के बजाय उनकी तरफदारी शुरू कर दी है और इसे भी राजनीति का हिस्सा बना दिया है. सपा ने आज़म ख़ान को राजनीति का कुशल महारथी बताया है और कहा है कि आज़म ने राम नाईक को दो टूक जवाब दिया है. राज्यपाल राम नाईक ने विधानसभा अध्यक्ष से आज़म ख़ान के वक्तव्य की नॉन-एडिटेड वीडियो फुटेज की सीडी मांगी थी. असंपादित सीडी और लिखित कार्यवाही पढ़ने और सुनने के बाद राज्यपाल ने कहा कि आजम मंत्री पद के योग्य नहीं हैं. उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिखकर मिलने को कहा है. राज्यपाल से मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष मिलते, उसके पहले ही सपा ने आज़म का पक्ष लेकर

आज़म ख़ान ऐसे बयान महज सुर्ख़ियों में बने रहने के लिए नहीं देते, बल्कि उनका बयान समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं के सिखावे और उकसावे पर जारी होता है और इसके गहरे राजनीतिक निहितार्थ हैं. अब तो सामने विधानसभा चुनाव भी है, लिहाजा समाजवादी पार्टी के स्टैंड को उस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए.

अपनी स्थिति साफ कर दी है.

सपा के इस रुख के बावजूद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने आज़म के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का रुख अपनाया हुआ है. राज्यपाल ने स्पष्ट कहा है कि आज़म ख़ान का वक्तव्य उनकी योग्यता पर सवाल उठाता है. राजभवन के प्रवक्ता ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि करते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 15 मार्च को आज़म ख़ान की टिप्पणी के बारे में भेजी गई असंपादित सीडी और लिखित कार्यवाही का अवलोकन करने के बाद राज्यपाल ने उन्हें लिखे पत्र में कहा है, प्राप्त असंपादित एवं संपादित मुद्रित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि संसदीय कार्य मंत्री आज़म ख़ान द्वारा 8 मार्च 2016 को विधानसभा में राज्यपाल के प्रति की गई लगभग 60 पंक्ति की टिप्पणी में से 20 पंक्तियां हटा दी गई हैं. नाईक ने पत्र में कहा है कि विधानसभा की कार्यवाही से संसदीय कार्यमंत्री के वक्तव्य की 33 प्रतिशत पंक्तियां हटाना यह दर्शाता है कि उनकी भाषा विधानसभा की गरिमा, मर्यादा और परम्परा के अनुकूल नहीं है. सदन में संसदीय कार्यमंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्यमंत्री के रूप में उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है. इस विषय पर मुख्यमंत्री जी से मुझे विचार करना पड़ेगा. राज्यपाल ने पत्र में कहा कि वह इस पत्र को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास भी उनके संज्ञान के लिए भेज रहे हैं.

आज़म ख़ान के अमर्यादित आचरणों का समाजवादी पार्टी द्वारा पक्ष लेने से यह साफ हो गया है कि समाजवादी सरकार ही आज़म ख़ान को आगे कर राजनीति करती रही है. आज़म ख़ान कभी प्रधानमंत्री के खिलाफ, कभी केंद्र सरकार के मंत्रियों के खिलाफ, कभी नेताओं के खिलाफ तो कभी राज्यपाल के खिलाफ ऊल-जुलूल बयान देकर राजनीति गर्म करते रहते हैं. इस बार आजम ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक के खिलाफ विधानसभा के अंदर मोर्चा खोलकर राजनीति को गैर-संवैधानिक रास्ते पर बढ़ाने की दिशा दिखा दी है. राजनीति समझने वाले यह समझते हैं कि आज़म ख़ान ऐसे बयान महज सुर्ख़ियों में बने रहने के लिए नहीं देते, बल्कि उनका बयान समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं के सिखावे और उकसावे पर जारी होता है और इसके गहरे राजनीतिक निहितार्थ हैं. अब तो सामने विधानसभा चुनाव भी है, लिहाजा समाजवादी पार्टी के स्टैंड को उस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए. आजम के विवादास्पद बयान प्रकरण में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का आधिकारिक वक्तव्य देखें तो आपको सपा की राजनीतिक मंशा साफ-साफ दिख जाएगी. राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि विधानसभा में आज़म ख़ान का प्रबंधकीय कौशल काबिले तारीफ है. भाजपा नेता सदैव प्रदेश के विकास में रोड़ा बनने और साम्प्रदायिकता फैलाने की कोशिश करते रहते हैं. भाजपा को तो बस बोलते रहने की बीमारी है. आज़म ख़ान भाजपा की आंखों में किस वजह से चुभते हैं, यह सभी जानते हैं. सपा प्रवक्ता आगे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज़म ख़ान ने मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में साम्प्रदायिक ताकतों का कड़ा मुकाबला किया है. आज़म ख़ान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं. सपा के इस आधिकारिक बयान से सपा के इरादे और उसकी राजनीतिक मंशा शीशे की तरह साफ-साफ दिख जाती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

समाजवादी पार्टी के राज में आतताइयों का राज

वोट नहीं दिया तो बस्ती फूंक दी

दो बच्चे और 12 मवेशी झुलस कर मरे, सरकार ने पूछा भी नहीं

लूफी यायावर

पंचायत चुनाव के दरम्यान समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देने का फैसला सीतापुर के दलितों और अति पिछड़ों पर कहर बन कर टूटा, लेकिन इस पर प्रदेश और देश ने ध्यान नहीं दिया. दलितों और अति पिछड़ों की पूरी बस्ती फूंक दिए जाने और दो बच्चों को जिंदा जलाए जाने की घटना पर राहुल गांधी या डोंगी बुद्धिजीवियों का ध्यान नहीं गया और न ढिंढोरची मीडिया का ही इस ओर ध्यान गया जो रोहित वेमुला पर ढोल पीटते हैं और दलितों की बस्ती फूंक दिए जाने पर शातिराना चुप्पी साध लेते हैं. रिहाई मंच ने सही ही कहा कि चुनावी वैमनस्यता में दलितों की बस्ती फूंक देना और बच्चों को जिंदा जला डालना मध्ययुगीन बर्बरता का प्रमाण है. सीतापुर में ही रेवसा के बिंविया गांव में 8 मार्च 2012 को सपा को जीत मिलने के बाद दलितों के 13 घर जला दिए गए थे, क्योंकि दलितों ने सपा को वोट नहीं दिया था. उसी तरह की घटना को ज्यादा बड़े वीभत्स रूप में फिर से अंजाम दिया गया.

राजधानी लखनऊ से सटे सीतापुर के गांव पट्टी दहलिया में दलित व कहार जाति के अतिपिछड़े लोगों के घरों को पिछले दिनों वहां के प्रधान कमलेश वर्मा के गुंडों ने फूंक डाला. घटना में दो बच्चे तीन साल की प्रियांशी (रमाकांत व रजनी देवी की बेटी) और आठ साल के मुकेश (सियाराम व सुनीता देवी का बेटा) की दर्दनाक मौत हो गई और कुछ जानवर झुलसकर मर गए. इस घटना पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और न ही भुक्तभोगियों के लिए किसी मुआवजे की घोषणा की गई. घटना को अंजाम देने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं. जिला प्रशासन मौन साधे है. इतनी बड़ी वारदात हो जाने के बावजूद गांव में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं. पूरे गांव में सन्नाटा छाया है और पुलिस का एक सिपाही भी वहां नज़र नहीं आता. बस्ती में अधिकांश घर कहार जाति के अति पिछड़े गरीब और दलितों के हैं. गांव के लोग मजदूरी करके अपना जीवन गुजारते हैं. उनसे केवल यह गलती हुई कि वर्तमान प्रधान कमलेश वर्मा को उन्होंने वोट नहीं दिया था. प्रधान ने उस गलती की उन्हें सजा दी, लेकिन प्रशासन ने सत्ता संरक्षण में पलने वाले अपराधी प्रधान पर कोई कार्रवाई नहीं की.

आपराधिक आगजनी के पीड़ितों की सरकार ने कोई सुध नहीं ली. कुछ राजनीतिक दल और कुछ सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने मौके पर जाकर पीड़ितों का हालचाल पूछा और सरकार से उनकी आर्थिक मदद और अपराधियों पर कार्रवाई

करने की मांग की. पीड़ितों से उनके गांव जाकर मिलने वाले संगठनों में रिहाई मंच, सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया), भाकपा माले (रेड स्टार), इंसाफ अभियान, पिछड़ा समाज महासभा, संगतिन किसान मजदूर संगठन के प्रतिनिधि शामिल थे. इन लोगों ने मौके पर देखा कि किस तरह प्रधानी के चुनाव में दबंग प्रत्याशी को वोट न देने के कारण दलितों और कहारों के तकरीबन दो दर्जन घर फूंक दिए गए. इसमें दो बच्चों और 12 मवेशियों के जलकर मरने के अलावा 35 से अधिक परिवार गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं.

बस्ती के रामपाल ने बताया है कि प्रधान कमलेश वर्मा और उसके गुर्गे उनके घरों में आग लगा रहे थे और कटाक्ष भी कर रहे थे कि सरकार 25-25 हजार रुपये देगी और पक्का मकान देगी. बस्ती के महिला-पुरुष विरोध करते रहे लेकिन प्रधान और उसके गुंडे बाज नहीं आए. ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान के आदमी मेड़ीलाल व कुछ अन्य लोग खुद ही छप्परों में आग लगा रहे थे. थाने में एफआईआर दर्ज कराने गए पप्पू ने बताया कि प्रधान कमलेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात पर कोतवाल ने उल्टा उन्हें ही डांटा और भगा दिया. बहुत मुश्किल से बाद में एफआईआर दर्ज हुई पर आज तक कमलेश की गिरफ्तारी नहीं हुई. मौके पर गए प्रतिनिधिमंडल ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने, प्रधान को निलम्बित कर उसके खिलाफ आपराधिक मामला चलाने, जिनके घर जले हैं उन्हें सरकारी आवास योजना के तहत पक्के मकान आवंटित करने और मृत बच्चों के निर्धन अभिभावकों को 50-

राजधानी लखनऊ से सटे सीतापुर के गांव पट्टी दहलिया में दलित व कहार जाति के अतिपिछड़े लोगों के घरों को पिछले दिनों वहां के प्रधान कमलेश वर्मा के गुंडों ने फूंक डाला. घटना में दो बच्चे तीन साल की प्रियांशी (रमाकांत व रजनी देवी की बेटी) और आठ साल के मुकेश (सियाराम व सुनीता देवी का बेटा) की दर्दनाक मौत हो गई और कुछ जानवर झुलसकर मर गए. इस घटना पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और न ही भुक्तभोगियों के लिए किसी मुआवजे की घोषणा की गई. घटना को अंजाम देने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं.

50 लाख रुपये का मुआवजा देने की सरकार से मांग की है. यह भी कहा है कि जिला प्रशासन बतौर अंतरिम सहायता पीड़ितों को खाद्य सामग्री, कपड़े और बिस्तर वगैरह उपलब्ध कराए और उनकी सुरक्षा की गारंटी करे. घटना स्थल का दौरा करने वालों में रिहाई मंच के अध्यक्ष मुहम्मद शुऐब, सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित संदीप पांडेय, संगतिन किसान मजदूर संगठन की ऋचा सिंह, भाकपा माले रेड स्टार के डॉ. बृज बिहारी, राजीव यादव, शाहनवाज आलम, पिछड़ा समाज महासभा के अध्यक्ष एहसानुल हक़ मलिक व महासचिव शिव नारायण कुशवाहा, इंसाफ अभियान के शबरोज मोहम्मबी, शकील कुरैशी, मौलाना इरशाद, मोहम्मद अबू अशरफ, बीएचयू के छात्र मोनीश बब्बर, आचार्य नरेन्द्र देव युवजन सभा के पवन सिंह यादव, हाजी जावेद, डॉ. एजाज, अकरम अली, शेख सिराज, अनुराग आग्नेय, प्रशांत मिश्रा, बुद्धि प्रकाश, अमर शिवा मिश्रा वगैरह शामिल थे. ■

feedback@chauthiduniya.com

साहित्य में मार्च लूट का मौसम

अनंत विजय

बिहार के कस्बाई शहर जमालपुर से सटे गांव बलिपुर में रहता था तो शहर से हमारे गांव को जोड़ने वाली सड़क से लेकर बाजार की मुख्य सड़क पर मार्च के महीने में अलकतरा के बड़े-बड़े ड्रम खड़े होने लगते थे. कहीं सड़कों पर पैबंद लगाने का काम किया जाता था तो कहीं नालियों को ठीक करने का. जब जमालपुर से दिल्ली आकर यहां के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में रहने लगा, तब भी यह नोटिस किया कि मार्च के महीने में बनी-बनाई सड़कों को फिर से बना दिया जाता था. सड़क किनारे के फुटपाथ को ठीक कर रंग-रोगन कर दिया जाता था. दिल्ली छोड़कर जब इंदिरापुरम में रहने आया तो यहां और भी अद्भुत नजारा देखने को मिला. इंदिरापुरम में कॉलोनी के अंदर इक्का-दुक्का बस कभी-कभार दिखाई देती है लेकिन मार्च में यहां कई बस शेल्टर बना दिए गए. बस शेल्टर बनाने के लिए फुटपाथ को तोड़ा गया. हमारी हाउसिंग सोसाइटी के बाहर की सड़क बने-ना-बने, हर साल मार्च महीने में फुटपाथ की टाइल्स बदल दी जाती है. फुटपाथ की टाइल्स बदलने के क्रम में बस शेल्टर के चबूतरे को तोड़ा जाता था. यह एक ही महीने में होता था. इन इलाकों से जब साहित्य की दुनिया में आया तो यहां भी मार्च की अहमियत का एहसास हुआ. हिंदी साहित्य के ज्यादातर आयोजन विश्वविद्यालयों के हिंदी विभागों में किए जाते रहे हैं. अब भी हो रहे हैं. यहां मार्च में हर वर्ष ताबड़ तोड़ कार्यक्रम किए जाते हैं. साहित्य से जुड़े लोग हर दिन किसी ना किसी कॉलेज, विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग आदि में प्रवचन देते नजर आते हैं. इसके अलावा कई विश्वविद्यालय भी स्वतंत्र रूप से आयोजन आदि करते हैं. सोशल मीडिया के फैलाव और वहां लाइक्स के आकर्षण ने हिंदी विभागों के इस मार्च सिंड्रोम को उखाड़ कर रख दिया है. जो भी इन कार्यक्रमों में शामिल होता है वो भाषण देते हुए अपनी तस्वीर फेसबुक आदि पर पोस्ट कर अपनी उपलब्धि की दुंदुभि बजाता है. जाहिर सी बात है कि जब दुंदुभि का शोर होगा तो आसपास के लोगों को पता चलेगा ही और सोशल मीडिया के इस फैलाव ने तो इसकी चौहद्दी को और भी विस्तृत कर दिया है. अब तो हालत यह है कि कई लेखक अपनी उपलब्धियों का जो इश्तेहार लगाते हैं, उसमें सुबह किसी कॉलेज में तो शाम को किसी कॉलेज में, अगले दिन किसी अन्य विश्वविद्यालय में प्रवचन का कार्यक्रम होता है.

कई बार शहर बदल जाते हैं लेकिन आयोजन लगभग एक जैसा ही दिखाई देता है.

कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सेमिनार कराने के लिए यूजीसी से लेकर कई अन्य सरकारी संस्थाएं आर्थिक मदद देती हैं. इसके अलावा कॉलेज का अपना भी फंड होता है. वित्तीय वर्ष खत्म होने यानी 31 मार्च के पहले इस फंड को खत्म करने का दबाव भी होता है. साल भर से सो रहे ये विभाग मार्च में जागते हैं और आनन-फानन में सेमिनार आदि करा डालते हैं. मौजूदा शिक्षा नीति के हिसाब से माना यह गया था कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों में इस तरह के सेमिनार से नवाचार को बढ़ावा मिलेगा. कॉलेज कैंपस से बाहर किस तरह की ज्ञान की बातें हो रही हैं या विश्वविद्यालय सिस्टम से बाहर के विद्वान किन अवधारणाओं की बात कर रहे हैं, इससे छात्रों और शिक्षकों का परिचय कराया जा सकेगा. यह एक बेहतर अवधारणा है लेकिन इसका विकृत रूप इन दिनों दिखाई दे रहा है. इन सेमिनारों को कॉलेज शिक्षकों ने अपने प्रमोशन की सीढ़ी बना लिया है. तुम मुझे बुलाओ, हम तुम्हें बुलाएंगे की तर्ज पर काम हो रहा है. इसके पीछे भी एक खेल है जिसको एपीआई कहते हैं. इस पर आगे चर्चा होगी.

हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि साल भर ऐसी सक्रियता देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में क्यों नहीं होती है. ये गोष्ठियां और ये सेमिनार साल भर क्यों नहीं आयोजित किए जाते हैं. इसकी वजहों की पड़ताल करने के लिए हमें विश्वविद्यालयों और उसके अंतर्गत के कॉलेजों की कार्य पद्धति का विश्लेषण करना होगा. नियमों के मुताबिक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को पूरे सप्ताह में चौदह क्लास लेनी होती है. अगर प्रोफेसर साहब विभागाध्यक्ष भी हैं तो उनको सिर्फ बारह क्लास लेने का प्रावधान है. उनको प्रशासनिक कार्य की वजह से दो क्लास कम लेने की छूट दी गई है. यानी सप्ताह में छह या सात घंटे. इस तरह से औसत निकालें तो यह हर दिन करीब घंटा सवा घंटा बैठता है. यही स्थिति एसोसिएट प्रोफेसरों की भी है. उनको भी सप्ताह में चौदह क्लास लेने का प्रावधान है. असिस्टेंट प्रोफेसर को सप्ताह में सोलह पीरियड लेना तय किया गया है. जब इस तरह का नियम बनाया गया था, तब माना यह गया था कि कक्षा खत्म होने के बाद विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षक शोध छात्रों को वक्त देंगे, छात्रों को पढ़ाने के लिए खुद पढ़ेंगे. अब भी नियम है कि शिक्षकों को कैंपस में पांच से छह घंटे बिताना अनिवार्य है. शिक्षकों का कैंपस में रहने का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है. उनकी उपस्थिति उनके कक्षा में उपस्थित रहने से ही तय होती है. इस तरह का कोई मैकेनिज्म अब तक नहीं बनाया गया है कि यूनिवर्सिटी के शिक्षक कैंपस में कितनी देर रहते हैं, उस पर नजर रखी जा सके. वे चाहें तो घंटे सवा घंटे में अपने पीरियड के बाद जा सकते हैं. ज्यादातर केसों में ऐसा ही होता भी है. इसके अलावा इनको सेमिनार आदि में भाग लेने के लिए छुट्टी का भी प्रावधान है. असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसरों को तो सेमिनार में भाग लेने के प्वाइंट भी मिलते हैं, जो उनके करियर प्रमोशन के वक्त काम आता है. अगर सेमिनार अंतरराष्ट्रीय है तो दस प्वाइंट और अगर राष्ट्रीय है तो साढ़े सात प्वाइंट. इन प्वाइंटस के चक्कर में ही इस तरह के सेमिनारों में तुम मुझे, मैं तुझे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है. हर कॉलेज के शिक्षक एक दूसरे को अपने यहां बुलाते हैं, ताकि आसानी से प्वाइंट इकट्ठा हो सके.

दूसरा, अगर हम इन सेमिनारों पर नजर डालें तो यह बात सामने आती है कि हर साल अक्टूबर-नवंबर से विभागों के चंद शिक्षक सक्रिय हो जाते हैं. उन्हें मालूम है कि सरकारी व्यवस्था में बजट आदि देने के बाद भी अनुमति मिलने में दो तीन महीने का वक्त लग जाता है. हर जगह यही जुगत रहती है कि मार्च के पहले-पहले सेमिनार आयोजित हो जाए, ताकि फंड भी खर्च हो जाए और जरूरी प्वाइंटस भी मिल जाएं. मार्च की इस साहित्यिक लूट में हिंदी विभागों के शिक्षक बाहर के अपने जानकार लेखक आदि को भी बुलाकर उपकृत करते हैं. इन सेमिनारों में क्या होता है, बहुधा इस बात को भुला दिया जाता है. भुलाया इसलिए भी जाता है कि याद करने लायक कुछ होता नहीं है. सेमिनारों की रस्म अदायगी के नाम पर कुछ पुरानी अवधारणाओं पर चर्चा हो जाती है. नई प्रवृत्तियों पर कम ही बात होती है. अब वक्त आ गया है कि विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों की जवाबदेही तय की जाए. उनके काम के घंटे तय किए जाएं और कोई ऐसा सिस्टम बने कि उनके कार्यों का ऑडिट हो सके. ऐसी व्यवस्था बने कि उनके काम का आकलन हो सके. उनके कैंपस में रहने के घंटे पर नजर रखी जा सके. कुछ लोगों को यह विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर खतरे जैसी बात लग सकती है लेकिन स्वायत्तता का मतलब अराजकता तो नहीं हो सकता है. स्वायत्तता के साथ जवाबदेही तो होनी ही चाहिए. काम करने के घंटे भी तय किए जाने चाहिए. क्या स्वायत्तता के नाम पर करदाताओं के पैसों की इस तरह से बरबादी जायज है. नई शिक्षा नीति तो बनाने का काम चल रहा है. तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय की कमेटी बातचीत कर फीडबैक ले रही है. खुद मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी कई राज्यों में जाकर बातचीत कर चुकी हैं. नई शिक्षा नीति में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि स्वायत्तता के नाम पर करदाताओं की गाढ़ी कमाई के पैसे का अपव्यय ना हो. नवाचार और बाहरी ज्ञान से परिचय के नाम पर मार्च में होने वाली इस साहित्यिक लूट पर भी लगाम लगाने का प्रावधान हो. सेमिनार हों, लेकिन वो रस्म अदायगी ना हो. सेमिनार हो, साल भर हों और उनमें नवाचार पर चर्चा हो. छात्रों के साथ शिक्षकों का भी फायदा हो. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

जिए सो खेले फाग

वृंदावन में विधवाओं ने होली खेलकर न सिर्फ जिंदादिली का परिचय दिया, बल्कि रूढ़िवादी मान्यताओं को भी आईना दिखाया.

सिन्धु रत्न पुरस्कार-2016

यह सम्मान नहीं, ज़िम्मेदारी है

अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, उनकी बात निराली होती है. देश के कुछ ऐसे ही निराले लोगों को बीते 31 मार्च को नोएडा स्थित लक्ष्मी स्टूडियो में आयोजित एक समारोह में सिन्धु रत्न अवॉर्ड-2016 से सम्मानित किया गया. इस समारोह का आयोजन एम फॉर यू म्यूजिक कंपनी एवं अमित भाटी के संयुक्त तत्वावधान में किया गया. सिन्धु रत्न अवॉर्ड के संयोजक एवं चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह अवॉर्ड पूरी तरह एम फॉर यू के निदेशक दुष्यंत सिंह की परिकल्पना है. दिल्ली में ऐसे समारोह कम आयोजित होते हैं. कुछ पत्रकारों को आधार बनाकर होते हैं, तो कुछ राजनीतिज्ञों को. लेकिन, दुष्यंत ने मुझसे कहा कि क्यों न हम एक ऐसे पुरस्कार की शुरुआत करें और उन लोगों को सम्मानित करें, जिन्होंने समाज के लिए सचमुच काम किया है. दुष्यंत सिंह ने कहा कि समाज के लिए निःस्वार्थ भाव से काम करने वालों से मिलकर आपको एक अलग तरह की ऊर्जा मिलती है, उन्हें ऊर्जावान रखकर ही हम समाज को ऊर्जावान रख सकते हैं और यह पुरस्कार उस दिशा में हमारी पहल है.

कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए वरिष्ठ भाजपा नेता संजय जोशी ने कहा कि समाज के लिए काम करने वालों को इस तरह सम्मानित करने से उनमें और बेहतर काम करने की ललक पैदा होती है. यही नहीं, दूसरों को भी समाज के लिए काम करने की प्रेरणा मिलती है. यह सम्मान उन लोगों को दिया जा रहा है, जिन्होंने सफलता के लिए नहीं, बल्कि उत्कृष्टता के लिए काम किया. समारोह को संबोधित करते हुए भारतीय कृषक समाज के डॉ. कृष्णवीर चौधरी ने कहा कि सम्मान करना भारत की परंपरा है. कर्म हर व्यक्ति करता है, लेकिन उस कर्म को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान किया जाता है. स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े अश्विनी महाजन ने कहा कि देश में विभिन्न समारोह होते हैं, लेकिन यह सम्मान उन लोगों के लिए है, जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है. ऐसे आयोजन समाज सेवा करने वालों को संदेश देते हैं कि उनके कार्यों को समाज में स्वीकार्यता मिल रही है.

सिन्धु रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए गायक अनुज ने कहा कि लोगों को पुरस्कार सम्मान के लिए मिलते हैं, लेकिन यह पुरस्कार मुझे ज़िम्मेदारी के रूप में मिला है. इससे मुझे आगे और बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी. सिन्धु रत्न अवॉर्ड से पुरस्कृत हुए जाने-माने पत्रकार श्रीवर्धन त्रिवेदी ने कहा कि निश्चित तौर पर पुरस्कार मिलने से ज़िम्मेदारी का एहसास होता है. यदि आप समाज में निःस्वार्थ भाव से

संवेदनशीलता बांटते हैं, तो प्रकृति आपको उसका कई गुना करके वापस करती है. हर कोई कुछ बड़ा करना चाहता है. कई बार बहुत छोटी-सी चीजें बड़ी हो जाती हैं. लेकिन, कार्य का परिणाम तय करता है कि कार्य छोटा था या बड़ा.

समारोह को संबोधित करते हुए महामंडलेश्वर मार्तण्ड पुरी ने कहा कि सिन्धु रत्न मंथन का शब्द है. उत्सव का अर्थ होता है, अपने उत्स से जुड़ना. यह हमारे मन के मंथन से उत्पन्न अमृत को बांटने के आनंद का उत्सव है. समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि जिसे समाज सेवा करनी है, वह करेगा ही, लेकिन ऐसे लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि समाज का एक तबका ऐसा है, जो हमारे कार्यों को मान्यता दे रहा है, सम्मान कर रहा है. समारोह में राधे-राधे बाबू जी महाराज सहित समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

विराट कोहली

किंग ऑफ चेज़

खेलों में यह कहावत बहुत प्रचलित है कि रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं. सचिन तेंदुलकर ने साल 2012 में जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सौ शतक बनाने का अद्भुत कारनामा किया था. उसके बाद एक कार्यक्रम में उनसे पूछा गया था कि उनके इस रिकॉर्ड को कौन सा खिलाड़ी तोड़ सकता है, तब उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम लिया था. तब भले ही लोगों ने सचिन की बात को गंभीरता से न लिया हो, लेकिन अब लोगों को यह बात समझ में आने लगी है कि सचिन ने विराट का नाम क्यों लिया था और यह बात उन्होंने बहुत सोच समझकर कही थी.

नवीन चौहान

टी-20 विश्वकप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करो या मरो वाली स्थिति में विराट कोहली ने रनों का पीछा करते हुए भारत को जीत क्या दिलाई, पूरी दुनिया उनकी मुरीद हो गई. क्या देश-क्या विदेश,क्या आम-क्या ख़ास आज हर किसी की जुबान पर सिर्फ विराट कोहली का नाम है. आठ साल के अपने क्रिकेट करियर में कोहली ने विराट मुकाम हासिल किया है. पिछले कुछ सालों में विराट ने क्रिकेट के हर फॉर्मेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. विश्वकप में खेली गई उनकी हालिया पारियों के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या विराट मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से बेहतर बल्लेबाज हैं? क्या वह क्रिकेट इतिहास के सर्वकालिक महान खिलाड़ी बनने की राह पर हैं? रनों का पीछा करते वक्त वे जिस तरह की आक्रामक और मैच जिताऊ पारियां खेलते हैं क्या यह उन्हें सचिन तेंदुलकर से एक पायदान ऊपर खड़ा करता है? जिस दबाव में बड़े से बड़े खिलाड़ी धराशायी हो जाते हैं, उसी दबाव में विराट जैसे खिलाड़ी के खेल में अद्भुत निखार आ जाता है. क्या उनकी यही खूबी उन्हें वर्तमान में दुनिया का सबसे घातक बल्लेबाज बनाती है. इन सवालों का जवाब ढूंढ़ना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि भारत में धर्म माने जाने वाले क्रिकेट की जो विरासत सचिन छोड़कर गए हैं, उसे विराट जैसे खिलाड़ी और कितना आगे ले जा रहे हैं या फिर वह सचिन से इतर सफलता की एक नई गाथा लिख रहे हैं.

खेलों में यह कहावत बहुत प्रचलित है कि रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं. सचिन तेंदुलकर ने साल 2012 में जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सौ शतक बनाने का अद्भुत कारनामा किया था. उसके बाद एक कार्यक्रम में उनसे पूछा गया था कि उनके इस रिकॉर्ड को कौन सा खिलाड़ी तोड़ सकता है, तब उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम लिया था. तब भले ही लोगों ने सचिन की बात को गंभीरता से न लिया हो, लेकिन अब लोगों को यह बात समझ में आने लगी है कि सचिन ने विराट का नाम क्यों लिया था और यह बात उन्होंने बहुत सोच समझकर कही थी. क्योंकि बांग्लादेश में एशिया कप के दौरान विराट ने पाकिस्तान के खिलाफ रनों का पीछा करते हुए 183 रनों की आक्रामक पारी खेली थी और टीम इंडिया को विजय दिलवाई थी. अंततः सचिन तेंदुलकर के करियर का यह आखिरी एकदिवसीय मैच साबित हुआ. इसके बाद विराट कोहली के खेल के स्तर में लगाता इज़ाफा होता गया. आज अपने आठ साल लंबे अंतराष्ट्रीय क्रिकेट करियर में वह उस मुकाम पर पहुंच गए हैं, जब उनकी तुलना विश्व के सर्वकालिक महानतम बल्लेबाजों से हो रही है.

25 साल तक अंतरराष्ट्रीय करियर खेलने वाले सचिन तेंदुलकर से उनकी तुलना करना कितना सही है. एकदिवसीय क्रिकेट में जब सचिन तेंदुलकर ने अपना 25वां शतक पूरा किया था तब वह 27 साल थे. इसके लिए सचिन को 234 पारियां खेलनी पड़ी थीं और उनके नाम तकरीबन 8 हजार एकदिवसीय रन थे. लेकिन विराट 27 वर्ष की उम्र में 171 एकदिवसीय मैचों में 7,212 रन बना चुके हैं. उन्होंने अपना 25वां एकदिवसीय शतक 162वें मैच में पूरा किया था. यह एक नया रिकॉर्ड है. 171 एकदिवसीय मैचों में सचिन 38.85 की औसत से 5,828 रन बना सके थे और उनके नाम 12 शतक थे. सचिन को पहला एकदिवसीय शतक लगाने के लिए 79 मैचों का इंतजार करना पड़ा था. 27 वर्षीय विराट कोहली आज जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं. अपने करियर के आखिर तक वह रनों का विराट पहाड़ खड़ा कर देंगे. साल 2016 की शुरूआत विराट के लिए बेहतरीन रही है. साल 2016 में आस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मैच तक विराट ने 12 टी-20 मैचों की 11 पारियों में 536 रन बनाए हैं और विश्व में सबसे ऊपर हैं. यह पहला मौका है जब किसी बल्लेबाज़ ने एक सीजन में टी-20 में 500 रनों के आकड़े को पार किया है. साल 2016 में 133.66 के स्ट्राइक रेट और 107.20 की औसत से रन बनाते हुए विराट ने 6 अर्धशतक जड़े हैं और 6 पारियों में वह नाबाद रहे हैं. इस दौरान उनका उच्चतम स्कोर 90 रन रहा है.

रनों का पीछा करने के मामले में कोहली का रिकॉर्ड बहुत अद्भुत है. उनकी इसी क्षमता की वजह से आज सचिन तेंदुलकर, इयान चैपल, नासिर हुसैन, वीवीएस लक्ष्मण और महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गज उनका गुणगान कर रहे हैं. पिछले कुछ सालों में उन्होंने जो मेहनत की है, उसका फल उन्हें मिल रहा है. उनकी आक्रामक और तकनीकि रूप से सुदृढ़ता की वजह से उन्हें सचिन, सहवाग और द्रविड़ का हाइब्रिड वर्जन भी कहा जाता है. समय और परिस्थिति के अनुरूप वह अपनी बल्लेबाजी में परिवर्तन कर लेते हैं. पिछले कुछ समय में उन्होंने दबाव झेलने की अद्भुत क्षमता विकसित

की है. कोहली भी कई बार यह बात सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि खचाखच भरे स्टेडियम में जब लोग आपको चियर करते हैं, तो आपके ऊपर दबाव भी होता है और जिम्मेदारी भी. आप ऐसे ही दिन के लिए क्रिकेट खेलते हैं. मैदान पर जितनी स्लेजिंग होती है, विराट उतनी ही दृढ़ता के साथ पिच पर खड़े रहते हैं और आक्रामक लहजे में ही जवाब देते हैं. शायद इसीलिए पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके खेल के स्तर में उछाल आ जाता है.

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन तो विराट को रनों का पीछा करने के मामले में अब तक का सबसे बड़ा बल्लेबाज या किंग ऑफ रन चेज कह चुके हैं. हर खिलाड़ी की विराट को लेकर अपनी समझ है. वीवीएस लक्ष्मण को लगता है कि कोहली को दबाव का मतलब ही नहीं मालूम है. लेकिन विराट के टीम मेट आशीष नेहरा बताते हैं कि विराट ने अपनी फिटनेस और इस मानसिक स्तर को पाने के लिए अथक मेहनत की है. पिछले तीन सालों में उन्होंने अपने खेल और जीवन शैली में बहुत से बदलाव किए हैं. उन्होंने अपने खान-पान को बहुत संतुलित किया है. यदि आप उनके साथ खाने पर चले जाएं तो आपको भारतीय या ग्रेवी वाला खाना नसीब नहीं होगा. यहां तक कि विराट ने मिठाई खाना भी बंद कर दिया है. ऑस्ट्रेलियाई अख़बार सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने लिखा कि विश्वस्तरीय खिलाड़ी बन चुके कोहली भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के दिलो-दिमाग में सचिन तेंदुलकर के उत्तराधिकारी के रूप में जगह बना रहे हैं. उन्होंने अपनी इस पारी(आस्ट्रेलिया के खिलाफ) से महान खिलाड़ी बनने की दिशा में एक कदम और बढ़ाया है साथ ही रनों का पीछा करने वाले विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की छवि में इज़ाफा हुआ है.

विराट कोहली में रनों की भूख नज़र आती है. टी-20 और एक दिवसीय मैचों में रनों का पीछा करते हुए वह एक अलग ही बल्लेबाज बन जाते हैं.

अब तक रन चेज करने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के माइकल बेवेन का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता था, वह आखिरी तक मैदान में डटे रहते और टीम की जीत दिलाकर ही वापस लौटते थे. उनकी ही परंपरा को विराट एक अलग स्तर पर ले जाने में सफल हुए हैं. हालांकि बेवेन पर उतना दबाव नहीं होता था, जितना कोहली के ऊपर होता है. लेकिन विराट के पास शॉट्स की ज्यादा वेरायटी है. वह पारंपरिक-बेसिक क्रिकेट खेलते हुए फॉर्मेट के हिसाब से खेल में बदलाव करते हैं. इस बात की तस्दीक करते हुए पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज इयान चैपल ने कहा कि विराट की इस बेमिसाल पारी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. बेहद दबाव भरे पलों में भी विराट ने पूरी जिम्मेदारी और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की और अपना बेसिक खेल दिखाया. पूरी पारी के दौरान उनके शॉट सेलेक्शन में कोई खामी नहीं थी. मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अपनी इस पारी से उन्होंने वेस्टइंडीज ब्रायन लारा को भी पीछे छोड़ दिया है. उनका शॉट सेलेक्शन लाजवाब है और वह निडर होकर गेंदबाजों का सामना करते हैं.

विराट क्रिकेट के कैनवास पर नए भारत की नई तस्वीर बना रहे हैं. वह भारत के उस युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो खुले तौर पर अपने प्रेम का इजहार भी करता है और फैशन ट्रेंड भी सेट करता है, टैटू भी बनवाता है. लेकिन इसका असर उनके खेल पर नहीं पड़ता. एक बार उनके स्पाइकी हेयर स्टाइल की वजह से टीम मेट्स ने उनकी नाम कार्टून कैरेक्टर के नाम पर चीकू रख दिया, लेकिन विराट को यह बात समझने में देर नहीं लगी कि कोई भी फैशन टशन तब जंचता है, जब बल्ले से रन निकलते हैं. विराट कोहली में रनों की भूख नज़र आती है. टी-20 और एक दिवसीय मैचों में रनों का पीछा करते हुए वह एक अलग ही बल्लेबाज बन जाते हैं. आंकड़े खुद ही विराट की अद्भुत कहानी बयां कहते हैं. टी-20 क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करते हुए उनका औसत 91.6 का है, जबकि उनके बाद मिस्टर क्रिकेट कहलाने वाले ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी माइकल हसी हैं, जिनका औसत 52.6 है. इसके बाद दुनिया के बेस्ट फिनशर महेंद्र सिंह धोनी का नंबर आता है, धोनी की औसत 47.9 की है. इन खिलाड़ियों के औसत में अंतर इतना बड़ा है कि इसी से जाहिर हो जाता है कि उन्हें किंग ऑफ चेज क्यों कहा जाता है. चंड़ीगढ़ में विराट ने जिस तरह विकेट को समझा और परिस्थितियों के अनुरूप बल्लेबाजी की वह काबिले तारीफ है. ऐसी पारियां के बल पर ही उन्हें विश्व के सर्वकालिक महानतम खिलाड़ियों में शुमार किया जाएगा. आज दुनियाभर के क्रिकेट प्रेमियों को इस बात का गर्व है कि उन्हें सचिन के संन्यास लेने के बाद उनके जैसे या उनके तुल्य खिलाड़ी के खेल का लुत्फ उठाने का मौका मिल रहा है और विराट समय के साथ लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं.■

navinonline2003@gmail.com

रनों का पीछा करने के मामले में कोहली का रिकॉर्ड बहुत अद्भुत है. उनकी इसी क्षमता की वजह से आज सचिन तेंदुलकर, इयान चैपल, नासिर हुसैन, वीवीएस लक्ष्मण और महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गज उनका गुणगान कर रहे हैं. पिछले कुछ सालों में उन्होंने जो मेहनत की है, उसका फल उन्हें मिल रहा है. उनकी आक्रामक और तकनीकि रूप से सुदृढ़ता की वजह से उन्हें सचिन, सहवाग और द्रविड़ का हाइब्रिड वर्जन भी कहा जाता है. समय और परिस्थिति के अनुरूप वह अपनी बल्लेबाजी में परिवर्तन कर लेते हैं.

कंगना-ऋतिक की लड़ाई ने लिया गंभीर रूप

एकतरफ़ा नहीं था मेरा प्यार : कंगना

मेरा प्यार एकतरफा नहीं था, इसमें ऋतिक भी पूरी तरह से शामिल थे. सवाल उठाए गए हैं कि यदि उनका मुझसे भावनात्मक जुड़ाव नहीं था, तो उन्होंने ई-मेल्स पर आपत्ति क्यों नहीं उठाई? उन्होंने मुझे ऐसा करने से कभी रोका क्यों नहीं? सच तो यह है कि ऋतिक की सहमति और भागीदारी से उन्हें ई-मेल्स भेजी गईं.

कंगना रनौत

हाल ही में अभिनेता ऋतिक रोशन ने अभिनेत्री कंगना रनौत पर मानहानि का केस दायर किया था. उसके जवाब में कंगना ने भी ऋतिक को जवाबी नोटिस भेजा था. बता दें कि कंगना ने अपने वकील रिजवान सिद्दीकी के जरिए 21 पेजों के नोटिस में कई बातों का खुलासा किया है. कंगना और ऋतिक ने फिल्म काइट्स और कृष 3 में साथ काम किया था. इन्हीं फिल्मों के दौरान दोनों की नज़दीकियां बढ़ी थीं. हालांकि दोनों ने अपने संबंधों को कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया था.

ऋतिक और कंगना के बीच यह बेहद ही गोपनीय रिश्ता रहा. उनके बीच दोस्ती की चर्चा हुई. इन दोनों में कब प्यार हुआ किसी को भनक तक नहीं लगी. ब्रेकअप भी हो गया, इसकी भी जानकारी किसी को दोनों ने नहीं लगने दी. लेकिन कंगना के इंटरव्यू ने सारी पोल खोल दी. इस इंटरव्यू से न सिर्फ दोनों के बीच की कड़वाहट सामने आई, बल्कि यह भी पक्का हो गया कि दोनों एक-दूसरे के बेहद करीब थे. कंगना ने इंटरव्यू में कहा था कि सिली एक्सेस सस्ती लोकप्रियता के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं. कंगना का इशारा किस की ओर था, लोगों ने तुरंत भांप लिया.

कंगना ने नाम नहीं लिया था, सिर्फ सिली एक्सेस ही कहा था, लेकिन उनका इशारा ऋतिक रोशन की ओर था. ऋतिक भी समझ गए थे कि कंगना का इशारा उनकी ओर है, लिहाजा उन्होंने तुरंत ट्विटर पर आकर कंगना को इसका जवाब दिया. इस बयानबाजी के बाद करीब दो माह तक मामला शांत रहा, लेकिन नोटिस प्रकरण के बाद से एक बार फिर यह मामला गर्मा गया है. कंगना ने नोटिस में खुलासा किया है कि यह कोई एकतरफा प्यार नहीं था, इसमें ऋतिक भी पूरी तरह से शामिल थे. सवाल उठाए गए हैं कि यदि उनका मुझसे भावनात्मक जुड़ाव नहीं था, तो उन्होंने इमेल्स पर आपत्ति क्यों नहीं उठाई. उन्होंने ने मुझे ऐसा करने से कभी रोका क्यों नहीं? सच तो यह है कि ऋतिक की सहमति और भागीदारी से उन्हें ई-मेल्स भेजी गईं.

> मैंने और कंगना ने केवल दो फिल्मों में साथ काम किया है और पेशेवर संबंधों के अलावा हम दोनों के बीच किसी भी तरह का सामाजिक, व्यक्तिगत, दोस्ताना या अंतरंग संबंध नहीं था. -ऋतिक रोशन

ऋतिक ने जहां अपने लीगल नोटिस में दावा किया है कि कंगना को एस्पर्गर्स सिंड्रोम नामक बीमारी है, जिस वजह से वो ऐसी चीजों की कल्पना करती हैं, जिसके सच होने की कोई संभावना नहीं होती है. इस पर कंगना ने भी ऋतिक पर पलटवार करते हुए कहा है कि ऋतिक के भी अपने मेंटल इश्यूज हैं.

कंगना द्वारा भेजे गए नोटिस के एक पैराग्राफ में लिखा है कि आपके क्लाइंट (ऋतिक) ने दावा किया है कि जिस दिन से कंगना को उनकी सही ई-मेल आईडी का पता चला था, तब से लेकर नोटिस भेजे जाने तक कंगना उन्हें रोजाना 50 ई-मेल भेजती थीं. इस घटनाक्रम को करीब 601 दिन हो चुके हैं, जिस हिसाब से उन्हें लगभग 30 हजार ई-मेल्स मिलनी चाहिए थीं, लेकिन आपके नोटिस में कुल 1,439 ई-मेल्स का जिक्र है. बाकी ई-मेल्स का क्या हुआ? इससे यह साबित होता है कि आपके क्लाइंट ने झूठे दावे किए हैं और बातों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया है.

ऋतिक ने अपने नोटिस में कहा है कि उन्होंने और कंगना ने केवल दो फिल्मों में साथ काम किया है और पेशेवर संबंधों के अलावा दोनों के बीच किसी भी तरह का सामाजिक, व्यक्तिगत, दोस्ताना या अंतरंग संबंध नहीं था.

खैर अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा की कंगना और ऋतिक की ये लड़ाई किस मोड़ पर जाकर खत्म होती है.■

बॉलीवुड ख़बरें

अजय की शिवाय

अजय देवगन की फिल्म *शिवाय* की शूटिंग बुल्गेरिया में काफी समय से चल रही है. समय-समय पर अजय वहां से फिल्म शूटिंग के वीडियो व फोटो फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं. लेकिन हाल ही में फिल्म के सेट से कई तस्वीरें बाहर आई है. बुल्गेरिया की खूबसूरत वादियों में जहां शिवाय की शूटिंग हो रही है, फिल्म की लोकेशन काफी शानदार बताई जा रहीं है. अजय ने शिवाय की कहानी अभी तक लीक नहीं की है, लेकिन फिल्म के टीजर को देखते ही लगता है कि शिवाय बाकी फिल्मों से तो काफी अलग दिखने वाली है.

गौरतलब है कि अजय देवगन की शिवाय उनका महत्त्वाकांक्षी डायरेक्शन प्रोजेक्ट है और वो इस फिल्म को सफल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं. फिल्म 2016 में दिवाली पर रिलीज़ होने वाली है. शिवाय की टक्कर रणबीर कपूर स्टारर फिल्म *ऐ दिल है मुश्किल* से होगी.■

सनी देओल ने दी सबको चुनौती!

घायल वन्स अगेन की सफलता भले ही बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा न दिखी हो, लेकिन इस फिल्म ने सनी देओल के करियर को एक बार फिर से स्पीड दिला दी है. जहां सनी के साथ वाले एक्टर्स अनिल कपूर और जैकी श्राफ अब पिता के किरदार में दिखाई देने लगे हैं, ऐसे में सनी का कदम काबिले तारीफ है.

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सनी देओल से पूछा गया कि क्या आप दो एक्टर वाले फिल्मों में काम नहीं करना चाहते? तो सनी देओल ने साफ-साफ कहा कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी एक्टर के साथ काम करने को तैयार हूं, लेकिन मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि कोई एक्टर मेरे साथ काम नहीं करेगा. सनी देओल ने कहा कि मुझे नहीं पता किसी को भी मुझसे क्या परेशानी है. मैं सबके साथ कंफर्टेबल हूं..लिहाजा आज मैं सारे एक्टर्स को चुनौती देता हूं कि आओ और मेरे साथ काम करो.■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

न उम्र बढ़ी न बदला अंदाज़

मलाइका अरोड़ा खान बॉलीवुड की ऐसी सेलिब्रिटी हैं जो आए दिन सुर्खियों में किसी न किसी वजह से रहती हैं. कुछ दिनों पहले वे एक बीच पर अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाती देखी गईं. टीजे से करियर की शुरूआत करने के बाद मलाइका ने मॉडलिंग में कदम रखा, लेकिन उनको पहचान *दिल से* में शाहरूख के साथ छैयां-छैयां गाने से मिली. मलाइका 42 साल की होते हुए भी बिल्कुल नहीं लगती कि वह इतने उम्र की हैं. वो खुद को बेहतरीन तरीके से मेंटेन करती हैं और खूबसूरत दिखती हैं.■

फ्लैशबैक

टुनटुन

गाने की शौकीन थीं उमा देवी

टुनटुन भारतीय हास्य अभिनेत्री होने के साथ-साथ एक पार्श्व गायिका भी थीं. उनका असली नाम उमा देवी खत्री था. उन्हें अक्सर हिन्दी सिनेमा की पहली हास्य अभिनेत्री भी कहा जाता है. टुनटुन फिल्मों में उमा देवी के नाम से गाती थीं.

उमा देवी खत्री, का जन्म उत्तर प्रदेश के एक ग्रामीण पंजाबी परिवार में हुआ था. उनके माता-पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और उनकी परवरिश उनके चाचा ने की थी. 13 वर्ष की आयु में यह घर से भाग कर मुंबई आ गई थीं और मुंबई में सीधे संगीत निर्देशक नौशाद अली के पास गई थी. उमा ने नौशाद अली से कहा था कि वो गा सकती हैं और अगर उन्होंने उन्हें काम नहीं दिया तो वो सागर मे डूब कर अपनी जान दे देंगी. नौशाद ने उमा की आवाज़ सुनने के बाद तय किया कि उमा एक अच्छी गायिका बन सकती हैं और उसी समय उन्हें काम दे दिया. उमा देवी को अभिनय से ज़्यादा गायकी का शौक था. उन्होंने अपनी मेहनत से हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी में शिक्षा प्राप्त की और महज़ 13 वर्ष की उम्र में ही मुंबई आ पहुंची. सन् 1947 में उमा देवी को अपना पहला एकल गीत गाने का मौका मिला. फ़िल्म दर्द का गाना, *अफ़साना लिख रही हूं दिल-ए-बेक़रार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतज़ार का* उमा देवी द्वारा गाया ये गीत सुपर हिट हो गया. इसके बाद उमा ने कई फिल्मों में अपनी मधुर अवाज़ से लोगों के दिलो पर राज किया.

पार्श्व गायिका के रूप में अपना करियर शुरु करने वाली उमा देवी को जब एहसास हुआ की इस क्षेत्र में वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाएंगी, तो उन्होंने अपनी प्रतिभा को अभिनय के क्षेत्र में आज़माया और एक ऐसी हास्य अभिनेत्री बनीं कि वो जिस किसी फिल्म में भी आतीं लोगों को हंसा-हंसा कर लोट पोट कर देती थीं. गायन के क्षेत्र में तो उनका बहुत ज़्यादा नाम नहीं हुआ लेकिन उनके हास्य अभिनय से कई फ़िल्में सजी और फ़िल्म जगत की बेहतरीन कॉमेडियन के रूप में उनका नाम आज भी सम्मान से लिया जाता है.

नौशाद साहब ने उन्हें फ़िल्मों में हास्य चरित्र के रूप में काम करने का सुझाव दिया और इस प्रकार आरंभ हुई उमा देवी की दूसरी पारी, जिन्हें हम टुनटुन के नाम से जानते हैं, उनकी यह दूसरी पारी सब को इतनी पसंद आई कि उमा देवी अपने प्रशंसकों के दिल में आज तक टुनटुन के नाम से ही बसी हुईं हैं और हमेशा रहेंगी. अपने फिल्मी करियर के दौरान उन्होंने लगभग 198 फिल्में और उस समय के लगभग सभी प्रमुख हास्य अभिनेताओं जैसे कि भगवान दादा, आगा, सुंदर, मुकरी, धूमल और जॉनी वॉकर के साथ काम किया.■

feedback@chauthiduniya.com